

CBC 22201/13/0004/2627



अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है



जन धन खातों से हम 32+ करोड़ महिलाएं सशक्त



₹47,000+ करोड़ के स्टैंड-अप इंडिया लोन से हमारे सपनों को मिला बल



हम 10+ करोड़ महिलाएं 90+ लाख SHGs से जुड़कर हो रहीं आत्मनिर्भर

ट्रंप का एलान

आज एक संपूर्ण सभ्यता का अंत हो जाएगा

अमेरिका धमकी पर अमल करेगा तो तेहरान तत्काल जवाब देगा : ईरान

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के तेल उद्योग के लिए अति अहम खार्ग द्वीप पर हमला किया है। वाइट हाउस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि अमेरिका ने द्वीप पर स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को मांगों को मानने या बड़े हमले का सामना करने के लिए निर्धारित की गई समय सीमा से कुछ घंटे पहले हुए। इस बीच ट्रंप ने मंगलवार सुबह एक बार फिर धमकी दी कि अगर ईरान ने



समझौता नहीं किया तो 'संपूर्ण सभ्यता आज रात ही खत्म हो जाएगी'।

उधर, ईरान के एक राजनयिक ने मंगलवार को कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके देश की पूरी सभ्यता को खत्म करने की अपनी धमकियों पर अमल करते हैं, तो तेहरान तत्काल और आनुपातिक जवाबी कार्रवाई करेगा। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि आम्बर सईद ईरावनी ने कहा कि ट्रंप की यह धमकी कि अगर तेहरान कोई समझौता नहीं करता है, तो पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, युद्ध अपराधों और संभावित नरसंहार के लिए उकसावे के समान है। ट्रंप ने द्वीप पर महत्वपूर्ण तेल अवसंरचना पर कब्जा करने के लिए एअर सेनिकों को भी उतारने की धमकी दी है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के अभियान में कई अमेरिकी सैन्य कर्मियों की जान जाएगी और यह



अमेरिकी वायुसेना के चालक दल के प्रमुख मिशन से पहले 'बी-2 स्पिरिट स्टीलथ बांबर' की उड़ान से पहले जांच करते हुए।

युद्ध को समाप्त करने की दिशा में निर्णायक कदम नहीं होगा। 'इंस्टीट्यूट फार द स्टडी आफ वार' और 'अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट' के क्रिटिकल थ्रेट्स प्रोजेक्ट द्वारा उग्रहों से प्राप्त तस्वीरों के आधार पर किए विश्लेषण के मुताबिक युद्ध के शुरुआती दौर में अमेरिका ने द्वीप पर कई ठिकानों पर हमला किया था, जिनमें हवाई सुरक्षा, एक रडार साइट, एक हवाई पट्टी और एक होवरक्राफ्ट बेस शामिल थे। इससे पहले अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी मेहर ने एक खबर में कहा था कि खार्ग द्वीप पर कई विस्फोट हुए हैं। वहीं, ईरान की राजधानी तेहरान के उत्तर पश्चिमी अल्बोर्ज प्रांत में हुए एक हवाई हमले में 18 लोगों की मौत हो

बाकी पेज 8 पर

भारत ने ईरान में अपने नागरिकों के लिए 'जहां हैं, वहीं रहें' का परामर्श जारी किया

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (ब्यूरो)।

वाशिंगटन द्वारा तेहरान को दी गई चेतावनी के बाद पश्चिम एशिया संकट के एक गंभीर मोड़ पर पहुंचने के बीच भारत ने मंगलवार को ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को अगले 48 घंटों तक 'जहां हैं, वहीं रहने' की सलाह दी। आपातकालीन परामर्श में, ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीयों से घर के भीतर रहने तथा सैन्य ठिकानों, ऊर्जा ढांचों और बहुमंजिला इमारतों की ऊपरी मंजिलों से पूरी तरह दूर रहने का आग्रह किया।

असम पुलिस पवन खेड़ा के आवास पर पहुंची कई उपकरण जब्त किए, घर पर नहीं मिले कांग्रेस नेता

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

असम पुलिस की एक टीम मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के आवास पर उनसे पूछताछ के लिए पहुंची और तलाशी ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सर्मा की पत्नी द्वारा खेड़ा के आरोपों के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत पर की गई। खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर तीन पासपोर्ट



कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर से दस्तावेज ले जाती असम पुलिस।

और अपोषित संपत्ति रखने का आरोप देबोजित नाथ ने कांग्रेस नेता के लगाया था। असम पुलिस के डीसीपी आवास के बाहर संवाददाताओं से

कहा कि खेड़ा अपने आवास पर नहीं मिले। उन्होंने कहा, हालांकि आवास की तलाशी ली गई और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। नाथ ने कहा कि कुछ दोष साबित करने वाली सामग्री मिली है, लेकिन जांच के इस स्तर पर इसकी विस्तृत जानकारी साझा नहीं की जा सकती। डीसीपी ने बताया कि गुवाहाटी की अपराध शाखा पुलिस थाना ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। शर्मा ने खेड़ा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। कांग्रेस प्रवक्ता खेड़ा ने रविवार

बाकी पेज 8 पर

मणिपुर में हमले के बाद फिर हिंसा भड़की दो बच्चों की मौत; सीआरपीएफ की चौकी पर धावा बोलने की कोशिश, दो लोग मारे गए

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

मणिपुर के बिष्णुपुर में मंगलवार तड़के सुबह एक चार साल के लड़के और उसकी नवजात बहन की सोते समय मौत हो गई। उनके घर पर राकेट जैसा कोई गोला आकर गिरा था। इसके बाद यहां हिंसा भड़क उठी। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना के बाद जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए और सीआरपीएफ जवानों को चौकी पर धावा बोलने की कोशिश कर रहे लोगों पर गोली चलायी पड़ी। इस दौरान दो नागरिकों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य को गोली लगी है और उनका इलाज चल रहा है। सरकार ने हिंसा के मद्देनजर इफल पूर्व, इफल पश्चिम, बिष्णुपुर और काकचिंग जिलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया।

मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने कहा कि दो बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सुरक्षा बलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उन्हें पकड़ें। खेमचंद ने कहा कि सरकार ने इस मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी



मणिपुर के बिष्णुपुर में विरोध-प्रदर्शन करती महिलाएं।

(एनआइए) को सौंपने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें शक है कि इस हमले के पीछे कोई ऐसा समूह या व्यक्ति है, जो राज्य में शांति प्रक्रिया को विगाड़ना चाहता है, जबकि हमने इस दिशा में काफी प्रगति कर ली है। राज्य सरकार ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए घाटी के पांच जिलों इफल पूर्व, इफल पश्चिम, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर में तीन दिनों के लिए इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से

पश्चिम बंगाल में मतदाता पुनरीक्षण

अदालत के निर्णय के बाद पहली सूची में 27 लाख नाम कटे

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

पश्चिम बंगाल में होने वाले मतदान से पहले निर्वाचन आयोग ने अंतिम सूची तैयार कर ली है। इस सूची में 27 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, ये मतदाता इस बार के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आयोग ने न्यायिक मामले निपटाने के बाद 58 लाख मामलों में से लगभग 45 फीसद (27.16 लाख) नाम मतदाता सूची से हटाए हैं।

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) के बाद पश्चिम बंगाल में अब तक कुल 90 लाख से अधिक अविद्यमान मतदाताओं के मत कटते जा चुके हैं। एसआइआर की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आयोग ने यह मतदाता सूची जारी की है, जिसमें सभी जिलों के मतदाताओं के नाम को शामिल किया गया है। इन नामों एसआइआर प्रक्रिया और कानूनी प्रक्रिया की समीक्षा के बाद तैयार किया गया है। मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य के अंतिम मतदाता आधार की घोषणा अभी बाकी है।

पश्चिम बंगाल में पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और इस चरण में 152 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए 23 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा। आयोग के मुताबिक जिन मतदाताओं के नाम

अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के नाम हटाए गए : ममता

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (ब्यूरो)।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूचियों से मनुआ और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। नदिया जिले के चक्रवाहा में आयोजित एक रैली में बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस उन लोगों के साथ खड़ी रहेगी जिनके नाम एसआइआर की प्रक्रिया के बाद मतदाता सूचियों से हटा दिए गए थे। आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, एसआइआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पश्चिम बंगाल में लगभग 91 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से हटा दिए गए हैं।

मतदाता सूची में नहीं हैं, वे मतदाता अब इस मामले में सुनवाई के लिए अपील न्यायाधिकरण में आवेदन कर सकते हैं और यदि न्यायाधिकरण मतदाता के नाम बाकी पेज 8 पर

केरल, असम व पुदुचेरी में चुनाव प्रचार थमा, दांव पर दिग्गज

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

केरल, असम और पुदुचेरी में मंगलवार शाम को चुनाव प्रचार का शोर थम गया। केरल में 140, असम में 126 और पुदुचेरी में 30 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीनों ही प्रदेशों में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। असम में बड़ा चेहरा वर्तमान में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सर्मा हैं, यहां गौरव गोगोई कांग्रेस के चेहरा हैं, जबकि केरल में मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन व पुदुचेरी में मुख्यमंत्री एन रंगासामी हैं। तीनों प्रदेशों की 296 सीटों नौ अप्रैल को मतदान होगा, उस दिन इन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। मतगणना 4 मई को की जाएगी। केरल में 140 सीटों के लिए 890 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि असम में 722 उम्मीदवार हैं और पुदुचेरी में 296 प्रत्याशी।

-पूरी खबर पेज 9

भारत की विमान कंपनियों की उड़ानें 300-350 से घटकर 80-90 रहीं

व्यवधान

यूरोप, उत्तर अमेरिका की उड़ानें अब लंबे वायुमार्ग से जा रही हैं

जंग छिड़ने के बाद से पश्चिम एशिया के लिए 10,000 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण भारतीय विमान कंपनियों की 10,000 से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। नागर विमानन मंत्रालय के संयुक्त सचिव असंगबा चुबा आव ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले भारतीय विमान कंपनियां पश्चिम एशिया के लिए रोजा 300-350 उड़ानें संचालित करती थीं। यह अब घटकर केवल 80-90 रह गई हैं।

संघर्ष के कारण इजराइल, जार्डन, लेबनान, कुवैत, कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों में हवाई क्षेत्र बंद या सीमित कर दिया गया है। इससे वैश्विक



विमानन संचालन और संपर्क पर अभूतपूर्व असर पड़ा है।

यूरोप और उत्तर अमेरिका जाने वाली उड़ानें अब लंबे मार्ग से जा रही हैं। इससे यात्रा समय और लागत दोनों बढ़ गए हैं। इससे निपटने के लिए सरकार ने पायलट के लिए कार्य समय में

अस्थायी छूट दी है, ताकि लंबी दूरी की उड़ानों का संचालन सुचारु रूप से हो सके। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष से वैश्विक विमानन नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय संपर्क व्यवस्था में अभूतपूर्व व्यवधान पैदा हुआ है। पायलट को मिली इस छूट के तहत उड़ान और ड्यूटी की

अवधि बढ़ा दी गई है (जैसे उड़ान समय लगभग 11.5 घंटे तक), जिससे एअरलाइन कंपनियां हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध और भू-राजनीतिक तनाव के कारण लंबा मार्ग अपनाते वाली उड़ानों का बेहतर संचालन कर सकें। इस कदम का उद्देश्य उड़ानों का संचालन सुचारु बनाए रखना और समय-सारिणी की विश्वसनीयता बनाए रखना है, खासकर उन अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर जो मार्ग परिवर्तन से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले की फिर से समीक्षा की जाएगी।

एक अधिकारी ने बताया कि विमान ईंधन की अंतरराष्ट्रीय कीमतें तेजी बढ़ी हैं, हालांकि भारत में कीमतों को नियंत्रित रखते हुए इसका केवल आंशिक असर ही घरेलू विमान कंपनियों पर डाला गया है। उन्होंने कहा कि एटीएफ की

कीमतों पर सरकारी हस्तक्षेप से घरेलू हवाई किराए स्थिर रखने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। नागर विमानन मंत्रालय इस कठिन समय में उद्योग को सहारा देने के लिए विभिन्न उपायों पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। युद्ध के कारण आपूर्ति शृंखला बनाए रखने के लिए एमिरेट्स, कुवैत एअरवेज और जजीरा एअरवेज जैसी विदेशी एअरलाइन कंपनियों को यात्री विमानों से माल ढुलाई की विशेष अनुमति दी गई है, जिससे जरूरी सामान की आपूर्ति जारी रह सके। अधिकारी ने कहा कि सरकार यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा, माल ढुलाई की निरंतरता और पूरे क्षेत्र की स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने न्यायिक कार्यों में कृत्रिम मेधा पर रोक लगाई

चंडीगढ़, 7 अप्रैल (ब्यूरो)।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को फैसला लिखने और कानूनी शोध के लिए कृत्रिम मेधा (एआइ) उपकरणों का उपयोग न करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने उन्हें अपने अधीन कार्यरत न्यायिक अधिकारियों से कहा है कि वे फैसला लिखने और कानूनी शोध के लिए चैटजीपीटी, जेमिनी, कोपायलट, मेटा आदि सहित किसी भी एआइ उपकरण का उपयोग न करें। आदेश में यह भी चेतावनी दी गई है कि इन निर्देशों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई संभव है।

..पूरी खबर पेज 10



दिल्ली सरकार ने दिए सख्त निर्देश

सड़क खोदने से पहले लेनी होगी अनुमति, जमा कराना पड़ेगा शुल्क

भूपेंद्र पांचाल
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

राजधानी की अनधिकृत कालोनियों में बिना अनुमति के सड़कों की खुदाई करने को लेकर अब दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। शहरी विकास मंत्री आशीष सुद के कड़े रुख के बाद विभाग ने एक बार फिर सभी सरकारी या निजी विभागों के साथ-साथ एजेंसियों के लिए निर्देश जारी किए हैं कि बिना तय शुल्क जमा कराए सड़क खोदने की अनुमति नहीं मिलेगी।

विभाग ने खासकर अनधिकृत कालोनियों में काम करने वाली नामित निष्पादन एजेंसियों (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और डीएसआइआइडीसी) को स्पष्ट कर दिया है कि वह अनधिकृत कालोनियों में सड़क खोदने की

इसके अलावा विभाग को इसकी भी रपट देनी होगी कि क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत या पुनर्निर्माण कर दिया गया है।

अनुमति मांगने वाली एजेंसी के अनुरोधों पर विचार करेंगी।

इस तरह के अनुरोध के लिए जीएसडीएल (दिल्ली भू-स्थानिक लिमिटेड) द्वारा संचालित पीडब्ल्यूडी के पीडीएम पोर्टल (योजना, खुदाई और निगरानी प्रणाली) या आफलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। इतना ही नहीं, एजेंसियों को कार्यों की तकनीकी व्यवहार्यता की जांच भी करनी होगी और निर्धारित अनुमानित बहाली शुल्क का आकलन भी करना होगा। शहरी विकास विभाग का मानना

है कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और डीएसआइआइडीसी पर ही अनधिकृत कालोनियों की सड़कों के रखरखाव करने का जिम्मा है।

ऐसे में यह दोनों एजेंसी ही संबंधित विभाग या एजेंसी से सड़क बहाली शुल्क वसूलने के बाद ही अनधिकृत कालोनियों में सड़क काटने की अनुमति जारी करेंगी और कार्य पूरा होने के बाद आइएंडएफसी और डीएसआइआइडीसी आम लोगों की सुविधा के मद्देनजर क्षतिग्रस्त सड़क की तुरंत मरम्मत कराएगी। खास बात यह है कि शहरी विकास विभाग ने इन दोनों निष्पादन एजेंसियों की यहीं तक जिम्मेदारी तय नहीं की है बल्कि इनको हर माह इसकी रपट भी भेजनी होगी। सड़कों की खुदाई करने की अनुमति देने और सड़क बहाली शुल्क वसूलने की पूरी जानकारी यूडी विभाग को देनी होगी।

गाजीपुर, नरेला, ओखला और तेखंड में कचरे से बिजली बनाने के संयंत्र लगेंगे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के विभिन्न विकास कार्यों, विशेषकर

कूड़ा प्रबंधन एवं सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं आधुनिक बनाने के उद्देश्य से उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कूड़ा प्रबंधन को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने पर जोर देते हुए गाजीपुर, नरेला, ओखला और तेखंड में अत्याधुनिक तकनीक से युक्त कचरे से बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए। साथ ही, जैविक कचरे के बेहतर उपयोग के लिए मुख्यमंत्री ने गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दिशा में गोयला डेरी, घोघा और गाजीपुर में तीन नए संयंत्र शीघ्र शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने एमसीडी के अंतर्गत संचालित लगभग 1000 शौचालयों एवं यूरिनल ब्लाकों को नए स्वरूप में विकसित करने के लिए आवश्यक बजट उपलब्ध

कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि केवल निर्माण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन सुविधाओं का संचालन भी उच्च स्तर का होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सार्वजनिक सुविधाओं के लिए ऐसी कार्ययोजना तैयार की जाए, जिससे वहां किसी प्रकार की दुर्गंध न रहे, नियमित सफाई सुनिश्चित हो।

मुख्यमंत्री ने गांदगी फैलाने वालों पर लगाए गए जुर्मानों की प्रभावी वसूली सुनिश्चित करने के लिए सख्त रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाना अनिवार्य है और इसके लिए

निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जाए। डीडीए के माध्यम से संचालित करने के मुद्दे पर भी गंभीर ध्यान हुआ। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस विषय पर डीडीए के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखें और सभी बाजारों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त, रेलवे ट्रैक के किनारे कूड़ा हटाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की समीक्षा की गई।

'मिशन अनमोल' में हर वर्ष होगी ढाई लाख नवजात की जांच

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

दिल्ली सरकार ने मिशन अनमोल को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत बड़े स्तर पर नवजात शिशु की जांच का कार्यक्रम शुरू हो सकेगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राजधानी में जन्म लेने वाले हर शिशु में जन्मजात बीमारियों की समय पर पहचान कर उनका उचित इलाज सुनिश्चित करना है।

इसके कार्यान्वयन में सहायता के लिए 148 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें मौजूदा 73 प्रयोगशाला और फील्ड कर्मचारियों के पदों को जारी रखने के साथ 60 स्टाफ नर्सों और 15 आर्टोमेट्रिस्ट के रूप में अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि मिशन अनमोल पहल के तहत अब हर वर्ष 1.5 लाख की जगह लगभग 2.5 लाख नवजात शिशुओं की पूरी जांच की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में लगभग हर नवजात की जांच सुनिश्चित की जा सके।

धनशोधन मामले में सुकेश चंद्रशेखर को मिली जमानत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

दिल्ली की एक अदालत ने आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषमम (अन्नाद्रमुक) के दो पत्नियों चुनाव चिह्न से जुड़े धनशोधन मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को मंगलवार को जमानत दे दी।

अदालत ने कहा कि वह धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत निर्धारित अधिकतम सात साल की सजा के आधे से अधिक समय तक हिरासत में रह चुका है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोंगने ने कहा कि स्वतंत्रता को संविधान में सबसे पवित्र मानक माना गया है। अदालतें विशेष

कानूनों या आर्थिक अपराधों को ढाल बनाकर सरकार के साथ साठगांठ करते हुए अपने फैसलों में केवल स्वतंत्रता का उपदेश नहीं दे सकतीं। चंद्रशेखर इस मामले में एक अप्रैल, 2022 से जेल में है। हालांकि वह अपने खिलाफ दर्ज अन्य लंबित मामलों में जेल में ही रहेगा। उसे अपने खिलाफ दर्ज 31 मामलों में से 26 में जमानत मिल चुकी है।



जेल से नहीं आया बाहर।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का मामला पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चंद्रशेखर ने अन्नाद्रमुक नेता टीटीवी दिनाकरन के लिए मध्यस्थ के रूप में काम किया।

दीनदयाल लाडो लक्ष्मी एप फोन में डालो

अब तक 9.56 लाख पात्र महिलाओं को ₹835 करोड़ की राशि जारी

अब हर महीने पा लो

इस योजना का लाभ

- * 23 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को
- * ₹1 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को प्राथमिकता

अब ₹1.80 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को भी नियमानुसार लाभ

नाॅन-स्टॉप हरियाणा

दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना

सम्मान भी, सुरक्षा भी

सूचना, लोक संपर्क तथा भाषा विभाग, हरियाणा

www.prharyana.gov.in | Follow us on [social media icons]

LIC भारतीय जीवन बीमा निगम

पीसीएमसी विभाग, जीवन सेवा एनेक्स, प्रथम तल, एस.वी. रोड, सांताक्रूज (पश्चिम), मुंबई 400054

निविदा सूचना

भारतीय जीवन बीमा निगम ऑनलाइन प्रीमियम एवं अन्य भुगतानों के संग्रह हेतु विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से **Payment Aggregator** के चयन के लिए प्रस्ताव (RFP) आमंत्रित करता है।

RFP संदर्भ/ LIC/CO/CRM/PS/PA/RFP/2026-27 दिनांक 07/04/2026.

बोली जमा करने की अंतिम तिथि/	07/05/2026 (by 15:00 Hrs)
RFP दस्तावेज डाउनलोड करने हेतु -	https://licindia.in/web/guest/tenders https://eprocure.gov.in/epublish/app https://www.tenderwizard.com/LIC

कार्यकारी निदेशक (ग्राहक संबंध प्रबंधन- बीमा सेवा)

दिनांक: 08.04.2026

पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय - खिचड़ीपुर, दिल्ली-110091

फर्मों से पंजीकरण हेतु आमंत्रण

पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय खिचड़ीपुर द्वारा सत्र 2026-27 हेतु विभिन्न सेवाओं/सामग्री की आपूर्ति के लिए इच्छुक पंजीकृत फर्मों से पंजीकरण आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक पंजीकृत फर्म विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु अपना पंजीकरण Registered Post/ E-mail (pmshrikvkhichripur@kvsrodelhi.in) के माध्यम से दिनांक 20.04.2026 तक प्रेषित कर सकती हैं। अधिक जानकारी/विवरण हेतु विद्यालय की वेबसाइट https://khicharipur.kvs.ac-in का अवलोकन करें।

अरविंद कुमार, प्राचार्य

इंडियन बैंक Indian Bank

कॉर्पोरेट कार्यालय, मानव संसाधन विभाग
254-260, अर्बे फणुमग साले,
रायपेड़ा, चेन्नै - 600 014.

विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती - 2026

इंडियन बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक, जिसका मुख्यालय चेन्नै में है, वेतनमान I, II और III में निम्नलिखित पदों के लिए विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित करता है।

क्र.सं.	विशेषज्ञता / संवर्ग	III	II	I	कुल
1	कंप्यूटर / आईटी इंजीनियर		25		25
2	सीसीडी/विपणन		10		10
3	ऋण अधिकारी / वित्त अधिकारी / एफए	50	200		250
4	समदी लेखाकार		10		10
5	सुरक्षा			10	10
6	डीलर / फोरिक्स अधिकारी	5			5
7	जोखिम अधिकारी	15			15
8	ट्रेजरी	5			5
9	एचआर / कार्मिक		10		10
10	आर्किटेक्ट / इंजीनियर			5	5
11	धन प्रबंधक	5			5
	कुल	75	260	15	350

महत्वपूर्ण तिथियों की समय-सारिणी

उम्मीदवारों द्वारा आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन शुल्क/सूचना प्रसार का भुगतान (ऑनलाइन) 08.04.2026 से 28.04.2026 (दोनों दिन शामिल है)

विस्तृत विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट www.indianbank.bank.in के 'करियर' पेज पर जाएं।

स्थान : चेन्नै दिनांक: 08.04.2026

मुख्य महाप्रबंधक (सीडीओ एवं सीएलओ)

खबर कोना

पुलिस मुख्यालय में की गई कैसर की जांच

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

विश्व स्वास्थ्य दिवस पर दिल्ली राज्य कैसर संस्थान ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में कैसर जांच व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर संस्थान की विलिनिकल आन्कोलाजी विभागाध्यक्ष डाक्टर प्रज्ञा शुक्ल ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाकर और सुलभ जांच सेवाएं उपलब्ध करवाकर कैसर की शुरुआती पहचान और रोकथाम को बढ़ावा देना है। शिविर में स्तन एवं सर्वोद्वल कैसर की निःशुक्त जांच की सुविधा प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, एचपीवी-डीएनए स्व-परीक्षण किट, विशेषज्ञ परामर्श, शैक्षिक सत्र तथा स्तन स्व-परीक्षण का प्रशिक्षण भी दिया गया। शिविर में पीएसए प्रोस्टेट कैसर के लिए 42 पुलिस कर्मियों की जांच की गई। वहीं मुंह के कैसर स्क्रीनिंग में 55 पुलिस अधिकारियों व कर्मियों ने जांच कराई। नौ महिला पुलिस की मैमोग्राफी की गई। जबकि 18 लोगों की एचपीवी परीक्षण किया गया। संस्थान के निदेशक डाक्टर विनोद कुमार ने कहा कि कैसर से लड़ाई में शुरुआती पहचान सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। इन जैसी पहलों के माध्यम से हम जागरूकता और इलाज के बीच की खाई को पाटने का प्रयास कर रहे हैं।

दिल्ली-एनसीआर में हुई तेज बारिश, नारंगी चेतावनी जारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार रात को आंधी और गरज के साथ तेज बारिश हुई। जिसके बाद मौसम विभाग ने नारंगी चेतावनी जारी की। मौसम विभाग ने नारंगी चेतावनी के तहत निवासियों को आंधी और गरज के साथ बारिश के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। बारिश के कारण अधिकतम तापमान में आसतन 6.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। विभाग के अनुसार, शहर में दिन भर रुक-रुककर बारिश होती रही। सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे के बीच सफदरजंग और लोधी रोड में 3-3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बुधवार को भी राजधानी में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से काफी कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी ग्रेनो में बनेगा मेट्रो विश्वविद्यालय

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 7 अप्रैल।

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को ग्रेनो में मेट्रो विश्वविद्यालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में उच्च शिक्षा से जुड़े इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। जिसके तहत ग्रेनो में मेट्रो विश्वविद्यालय खोला जाएगा।

उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के मुताबिक, यह फैसला उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के नियमों के तहत लिया गया है। इस कानून के जरिए राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, उनके संचालन और नियंत्रण के लिए स्पष्ट व्यवस्था की गई है। इससे शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और छात्रों को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही युवाओं को आधुनिक तकनीक और रोजगार से जुड़ी पढ़ाई का लाभ मिलेगा। जिससे उनके भविष्य को



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेते मंत्री।

नई दिशा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि यह पहल राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार उच्च शिक्षा के विस्तार, गुणवत्ता संवर्धन और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना से प्रदेश में शिक्षा के साथ-साथ रोजगार और कौशल विकास के अवसर भी बढ़ेंगे।

नोएडा स्थित सनहिल हेल्थकेयर प्रालि को ग्रेनो

प्राधिकरण से आर्बाटि 26.1 एकड़ जमीन पर मेट्रो विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे विधिक प्रावधानों तहत मंजूरी दी गई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की अनुसूची में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2026 प्रख्यापित किए जाने और प्रायोजक संस्था को संचालन प्राधिकार-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है।

शराब के नशे में पिता और चाचा की हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

दिल्ली के उत्तम नगर में शराब के नशे में हुए झगड़े में अपने पिता और चाचा की हत्या करने के आरोप में 22 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि घटना के बाद से आरोपी ईश्वर फरार था, लेकिन उसे एक पुख्ता सूचना पर सोमवार को पकड़ लिया गया।

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि चार अप्रैल को पुलिस को इस घटना के बारे में सूचना मिली, जिसके आधार पर देवेन्द्र कुमार (50) और उनके भाई अमित (48) के शव एक कमरे से बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि कमरा अस्त-व्यस्त पड़ा था और वहां शराब की बोतलें बिखरी पड़ी थीं। जांच दल और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल का मुआयना किया और सबूत जुटाए। शवों को पोस्टमार्टम के लिए दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल भेजा गया। पुलिस अधिकारी

के मुताबिक, पोस्टमार्टम रपट से पता चला कि दोनों व्यक्तियों की मौत हमले के कारण लगी आंतरिक चोटों से हुई। जांच के दौरान पता चला कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में कार्यरत देवेन्द्र हाल में अपने भाई और बेटे के साथ किराए के मकान में रहने आए थे। मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि तीन अप्रैल को रात को उसे अपने किराएदार के यहां झगड़े की सूचना मिली और जब वह मौके पर पहुंचा, तो ईश्वर ने दरवाजा खोला। पुलिस ने मकान मालिक के हवाले से बताया कि ईश्वर नशे की हालत में लग रहा था तथा उसे शांत करने के बाद वह (मकान मालिक) अपने घर लौट गया। बाद में मकान मालिक को सूचना मिली कि देवेन्द्र की हत्या कर दी गई है और जब वह दोबारा घर पहुंचा तो उसे दोनों भाई मृत मिले। बेटे ईश्वर ने कथित तौर पर झगड़े के दौरान अपने पिता और चाचा पर हमला किया और फिर मौके से फरार हो गया। ईश्वर को मोहन गार्डन इलाके से गिरफ्तार किया गया।

वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो की मौत, चालक फरार

जनसत्ता संवाददाता
गाजियाबाद, 7 अप्रैल।

गाजियाबाद के लोनी थाना अंतर्गत बंधला-चिरोड़ी मार्ग पर मंगलवार को एक सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवारों दो लोगों की मौत हो गई। निटौरा गेट के समीप दोपहर करीब डेढ़ बजे के आसपास एक तेज रफ्तार बोलरो पिक्अप और विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पिक्अप वाहन बंधला फ्लाईओवर की दिशा से चिरोड़ी की ओर जा रहा था। तभी यह भीषण भिड़ंत हुई। टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्ति सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से चोटिल हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायलों को लोनी बार्डर स्थित 59 शैथ्या अस्पताल में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस जांच में मृतकों की शिनाख्त अफजलपुर निस्तोली निवासी 48 वर्षीय राजेश और महल कालोनी बंधला निवासी 52 वर्षीय धर्मवीर के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है। फिलहाल, दुर्घटना के बाद वाहन चालक मौके से भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम जुटी हुई है। पुलिस ने कई टीमों गठित की हैं व चालक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों दबिश दे रही हैं।

सड़क हादसे में एक की गई जान, आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (संवाददाता)।

बाहरी दिल्ली के पश्चिम विहार पूर्व इलाके में तेज रफ्तार से जा रहे एक ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक ले कर चालक भाग निकला, जिसे बाद में पकड़ लिया गया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोमवार रात को पश्चिम विहार पूर्व पुलिस थाना क्षेत्र में पंजाबी बाग से पीरागढ़ी चौक की ओर जाने वाले रास्ते पर सड़क हादसा होने की जानकारी पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) को फोन काल पर मिली। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची, जहां पीरागढ़ी कैप निवासी कृष्ण मोहन सड़क पर मृत पड़ा था। मोहन की मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हालत में घटनास्थल पर मिली। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों ने वाहन के साथ फरार होने की कोशिश कर रहे ट्रक चालक को कुछ दूरी पर ही पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उसने बताया कि आरोपी चालक की पहचान सौरभ कुमार (26 वर्ष) के रूप में हुई। शुरुआती जांच के मुताबिक, ट्रक चालक ने मौके से भागने की कोशिश करने से पहले, मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी।



मौसम

नई दिल्ली में मंगलवार को बारिश का लुफ्त उठाते लोग।

न्यू नोएडा के लिए एक माह में भूमि अधिग्रहण की तैयारी

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 7 अप्रैल।

दो सौ नौ किलोमीटर में बसने वाले न्यू नोएडा के लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया आगामी एक से डेढ़ महीने में शुरू करने की तैयारी है। अधिग्रहण कार्य के लिए कुछ पदों और अधिकारियों का चयन पहले ही कर लिया गया था, लेकिन मुआवजा दर निर्धारण में देरी की वजह से इसे शुरू नहीं किया जा सका।

गत सोमवार को हुई नोएडा की 222वीं बोर्ड बैठक में न्यू नोएडा के लिए मुआवजा दर यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की

न्यू नोएडा के लिए मुआवजा दर यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तर्ज पर रखे जाने की सहमति बनी है।

तर्ज पर रखे जाने की सहमति बनी है। जिसके बावत करीब आठ सौ करोड़ रुपए आरक्षित किए हैं। प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक, यीडा की तर्ज पर यहाँ 4300 प्रति वर्ग मीटर मुआवजा दर होगी, जिसकी अंतिम मंजूरी के लिए दर निर्धारण प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है। वहाँ से मंजूरी मिलने के साथ पहले चरण की

अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र, यानी न्यू नोएडा को गौतमबुद्ध नगर और जनपद बुलंदशहर के 80 गांवों की जमीन पर विकसित किया जाना है। यह औद्योगिक शहर मास्टर प्लान-2041 तक 20,000 हेक्टेयर से अधिक में फैलेगा, जिसमें करीब तीन हजार औद्योगिक इकाइयां होंगी। न्यू नोएडा के लिए अक्टूबर 2024 में अधिसूचना जारी की गई थी। न्यू नोएडा के लिए जमीन अधिग्रहण प्रारूप को लेकर लखनऊ में एक प्रस्तुतिकरण दिया गया था। साथ ही समझौते के आधार पर भी जमीन लेने के लिए किसानों से बातचीत की जा रही है।

दिल्ली पुलिस
शांति सेवा न्याय

यातायात निर्देशिका

आई.पी.एल. टी-20 क्रिकेट मैच
on 08-04-2026

दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटन्स
सायं 7:00 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक

अरुण जेटली स्टेडियम फिरोज शाह कोटला मैदान, नई दिल्ली

यात्रा में असुविधा से बचने के लिए मेट्रो/बस की सवारी करें

दिल्ली कैपिटल्स द्वारा फ्री बस सर्विस
फ्री पार्किंग : 1 माता सुंदरी रोड 2 राजघाट पावर हाउस रोड 3 वेलोड्रम रोड 4 राजघाट और शांतिवन सर्विस रोड के दोनों तरफ

सुरक्षा निर्देश: स्टेडियम में आने वाले दर्शकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित प्रतिबंधित वस्तुएं साथ में न लाएं

24 घण्टे यातायात हेल्पलाइन: 011-25844444/1095

महत्वपूर्ण संकेत

- विन वाहनों के पास पार्किंग लेबल नहीं है वे जगत तीर के निशान के अनुसार जाएं।
- विन वाहनों के पास पार्किंग लेबल है वे नीले तीर के निशान के अनुसार जाएं।
- पार्क एंड राइड फ्री पार्किंग :- (पाना सुंदरी रोड, राजघाट पावर हाउस रोड, वेलोड्रम रोड राजघाट और शांतिवन सर्विस रोड के दोनों तरफ)
- राहत सेवा के लिए फिक अप प्वाइंट
- राहत सेवा के लिए जॉय ऑफ प्वाइंट
- टेक्स्ट (ड्राय ऑफ फिक अप लेन)
- स्टेडियम तक पहुंचने के लिए मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें।
- नजदीक मेट्रो स्टेशन : दिल्ली मेट (गेट नं. 4 & 5) आर्टिडीओ (गेट नं. 3, 4 & 5)

मार्ग परिवर्तन/प्रतिबंध
(जब एक जैसी भी आवश्यक होगा)

आपरकलानुसार, 8 अप्रैल 2026 को शाम 5 बजे से रात 1 बजे तक बहादुर शाह जफर मार्ग और जेएलएन मार्ग पर यातायात में बदलाव / प्रतिबंध लागू रहेंगे।

निम्नलिखित मार्गों पर कोई भी वाहे या वाणिज्यिक वाहन नहीं चलें
1) दरियागंज से दिल्ली गेट चौक तक (बीएसजेड मार्ग), (2) दिल्ली गेट चौक से गुरु नानक चौक की ओर (जेएलएन मार्ग) और (3) आर्टिडीओ से दिल्ली गेट चौक तक (बीएसजेड मार्ग)।

वाहनों से अनुरोध है कि मैच वाले दिन शाम 5 बजे से रात 1 बजे तक निम्नलिखित सड़कों पर आवागमन से बचें, क्योंकि इस दौरान दर्शक स्टेडियम में आने और यातायात में भीड़भाड़ होने की संभावना है।

राजघाट से दिल्ली गेट लेते हुए आर/ए कमला मार्केट तक जे. एल. एन. मार्ग (दोनों तरफ पक्की सड़क) तुर्कमन गेट से दिल्ली गेट तक आरएफ अली रोड। दिल्ली गेट से रामनगला अग्रवाल चौक /आर्टिडीओ चौक तक बहादुर शाह जफर मार्ग (दोनों पक्की सड़क)।

स्टेडियम में प्रवेश

- गेट नंबर 1 को 8 तक स्टेडियम के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है और इन गेटों में प्रवेश बहादुर शाह जफर मार्ग से दिया जाएगा।
- गेट नंबर 10 से 15 तक स्टेडियम के पूर्वी भाग में स्थित है और इन गेटों में प्रवेश जे.एल.एन. मार्ग पर अर्बेडकर स्टेडियम बस टर्मिनस के पास है।
- गेट नंबर 16, 17, 18 पर स्टेडियम के पश्चिमी भाग में स्थित है और इन गेटों में प्रवेश बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित ट्रेडोल्ड प्लन के पास से है।

फ्री पार्किंग एण्ड राइड
दर्शकों के बिना लेबल लेने वाले वाहनों के लिए फ्री पार्किंग एण्ड राइड प्रदान किया जाएगा।
- माता सुंदरी रोड - राजघाट पावर हाउस रोड - वेलोड्रम रोड - राजघाट और शांतिवन सर्विस रोड के दोनों तरफ

पार्किंग
लेबल वाले वाहन

स्टेडियम के आसपास लेबल लेने वाले वाहनों के लिए फ्री पार्किंग एण्ड राइड प्रदान किया जाएगा।
- माता सुंदरी रोड - राजघाट पावर हाउस रोड - वेलोड्रम रोड - राजघाट और शांतिवन सर्विस रोड के दोनों तरफ

किसी भी वाहन को आसपास लेबल लेने वाले वाहनों के लिए फ्री पार्किंग एण्ड राइड प्रदान किया जाएगा।
- माता सुंदरी रोड - राजघाट पावर हाउस रोड - वेलोड्रम रोड - राजघाट और शांतिवन सर्विस रोड के दोनों तरफ

यस
सभी वसों की सेवाएं मैच शुरू होने के 2 घंटे पूर्व से रात 12:30 बजे तक उपलब्ध रहेंगी।

एन सीआर में आसपास लेबल लेने वाले वाहनों के लिए फ्री पार्किंग एण्ड राइड प्रदान किया जाएगा।
- माता सुंदरी रोड - राजघाट पावर हाउस रोड - वेलोड्रम रोड - राजघाट और शांतिवन सर्विस रोड के दोनों तरफ

गाजियाबाद में 16वीं मंजिल से गिरकर युवती की मौत

गाजियाबाद, 7 अप्रैल (संवाददाता)।

इंदिरापुरम क्षेत्र स्थित जयपुरिया सनराइज ग्रीन सोसाइटी में मंगलवार सुबह एक 18 वर्षीय युवती की 16वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान संस्था के रूप में हुई है, जो मूल रूप से हरदोई की रहने वाली थी और वर्तमान में अपने परिवार के साथ कनावली गांव में रह रही थी। घटना सुबह करीब सवा छह बजे की है। बताया जा रहा है कि जब युवती जमीन पर गिरी, तब वह अर्धनग्न अवस्था में थी, जिसे देख सोसाइटी के लोग सन्न रह गए। आनन-फानन में पुलिस को सूचित किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, संस्था के पिता सुखदेव कर्नोजिया सोसाइटी में कपड़े रूठी (प्रेस) करने का काम करते हैं। संस्था खुद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही थी और रोजाना सुबह वीडियो जाती थी। मंगलवार सुबह भी वह घर से कसरत के लिए निकली थी, लेकिन वह जयपुरिया सोसाइटी के सी ब्लॉक की 16वीं मंजिल पर कैसे पहुंची और किन परिस्थितियों में नीचे गिरी, यह अभी जांच रहा हुआ है। पुलिस जांच में एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग खंगालने पर संस्था लिफ्ट के भीतर अकेली जाते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि, परिजनों ने आत्महत्या की बात को सिर से खारिज किया है। पिता सुखदेव का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ कोई सजिश हुई है। उनका कहना है कि संस्था को किसी ने बहाने से ऊपर बुलाया और फिर वहां से धक्का दे दिया। वहीं, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले को हर पहलू से तपतीश कर रही है।

नोएडा में 300 टन कचरे का होगा निस्तारण, संयंत्र लगाएगी आइजीएल

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 7 अप्रैल।

औद्योगिक महानगर में गीले कचरे के निस्तारण के लिए आइजीएल एक कंप्रेसड बायो-गैस संयंत्र लगाएगी। करीब तीन सौ टन क्षमता वाले इस संयंत्र पर करीब डेढ़ सौ करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहां बने वाली बायोगैस का शहर में इस्तेमाल किया जाएगा। इस परियोजना को अस्ट्रैली में लगाया जाएगा। गौरतलब है कि नोएडा में फिलहाल रोजाना एक हजार टन कचरा निकल रहा है। भविष्य में 1200 से लेकर 1500 टन कचरा प्रतिदिन के निस्तारण की चुनौती होगी। नोएडा प्राधिकरण का

एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड से कुल 600 टन कचरा प्रतिदिन के निपटारे का करार किया है। यह संयंत्र लगाने का करीब पचास फीसद काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा 40-40 टन प्रतिदिन की क्षमता के छह हिस्ट्रीट्रैलरजड इंटीग्रेटेड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। जिसके चलते 240 टन कचरे का रोजाना निस्तारण किया जा सकेगा। अब प्राधिकरण तीन सौ टन प्रतिदिन की क्षमता का एक नया एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र और लगाने जा रहा है। जिसकी क्षमता को बढ़ाकर 500 टन प्रतिदिन किया जा सकता है। यहां एक ही स्थान पर गीले और सुखे कूड़े का निवारण हो जाएगा।

प्ररूप संख्या आईएनसी-26

(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय 1, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मागले में

जी-टैक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

(सीआईएन: U74140UP2008PTCO34745) जिसका पंजीकृत कार्यालय: सी-27 विक्रान्त खंड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत-226010 में है, के मामले में

...आवेदक कंपनी/वाचिकाकर्ता

एतद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह आवेदक कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "उत्तर प्रदेश राज्य" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए 18 मार्च, 2026 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट में बदलाव को पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विवेक का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय 1, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पहिले दीनदयाल अंबेडकर भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजे।

सी-27 विक्रान्त खंड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत-226010

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से **जी-टैक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड** हस्ता /—

अमित कुमार अग्रवाल (निदेशक)
दिनांक: 07.04.2026
स्थान: लखनऊ **सीआईएन:** 03426915

प्ररूप संख्या आईएनसी-26

(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय 1, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मागले में

केकेएम प्रीफेब्र प्राइवेट लिमिटेड

(सीआईएन: U452001DL2003PTC123560) जिसका पंजीकृत कार्यालय: C/6 6 संजय मार्केट, गेंदर कलाशा, नई दिल्ली-110048 में है, के मामले में

...आवेदक कंपनी/वाचिकाकर्ता

एतद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह आवेदक कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए सोमवार, 18 मार्च, 2026 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट में बदलाव को पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विवेक का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय 1, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पहिले दीनदयाल अंबेडकर भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजे।

C/6 6 संजय मार्केट, गेंदर कलाशा, नई दिल्ली-110048

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से **केकेएम प्रीफेब्र प्राइवेट लिमिटेड** हस्ता /—

जसवीर सिंह देसवाल (निदेशक)
दिनांक: 07.04.2026
स्थान: दिल्ली **सीआईएन:** 00427546

फॉर्म नं. आईएनसी-26

(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (उत्तरी क्षेत्र निदेशालय क नई दिल्ली) के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) के साथ पठित कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (क) के मागले में

तथा

ट्रिपल प्ले ग्रॉइंडेड प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U32204DL2007PTC168410), लिस्बन पंजीकृत कार्यालय: ख. नं. 540/180, प्लॉट नं. 217, ग्राम बिजवासन, सोडवाला कुआँ के पास, पश्चिम पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली - 110061 के पार, दिग्भंग पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली के मामले में

...आवेदक

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.क्षेत्र) दिल्ली" से बदलकर "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सहमत बनाने के लिए 31.03.2026 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट में परिवर्तन को पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं। अथवा उसके नीचे दिए गए पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा सर्वप्रथम अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय क नई दिल्ली के पास जमा करें या जमा करवाएं या पंजीकृत डाक से भेजे: ख. नं. 540/180, प्लॉट नं. 217, ग्राम बिजवासन, सोडवाला कुआँ के पास, दिग्भंग पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली - 110061

ट्रिपल प्ले ग्रॉइंडेड प्राइवेट लिमिटेड की ओर से और उनके लिए हस्ता /—

नवनील सेठी (निदेशक)
दिनांक: 08/04/2026
स्थान: नई दिल्ली **DIN:** 01953974

SBI भारतीय स्टेट बैंक
तनावग्रस्त आस्तियां वसूली शाखा

द्वितीय तल, पटना मुख्य शाखा भवन, पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना-800001 फोन नं०: 0612-2999140, ई-मेल: sbi.05176@sbi.co.in

सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत सम्पत्ति के कब्जा के संबंध में सूचना का प्रकाशन

प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट/SARFAESI Act) 2002 (2002 का 54) के तहत सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति निहित हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 धारा 13(12) नियम 3 के साथ पठित है, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खातों के सामने अंकित तिथि को, जैसा कि बाद में उल्लेखित है, निम्नलिखित ऋण/जमानतदार को मौग नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्हें उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर नोटिस में उल्लेखित राशि वापस करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि ऋणी/जमानतदारों देय राशि के भुगतान करने में असफल रहे एतद् द्वारा ऋणी/जमानतदारों तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) जो उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित है, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खातों के सामने अंकित तिथि को उक्त सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है जो यहाँ नीचे उल्लिखित है।

विशेषकर ऋणी/जमानतदारों एवं सम्पत्ति मालिक तथा सामान्यतः आम जनता को एतद् द्वारा सावधान किया जाता है कि इस सम्पत्ति के साथ कोई लेन-देन न करें तथा इस सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन भारतीय स्टेट बैंक के देय राशि तथा उस पर ब्याज एवं अन्य खर्च के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता/जमानतदार का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

खाता/ऋणी का नाम एवं पता	सम्पत्ति का प्रोपराइटर/ पार्टनर्स/जमानतदार/ मालिक का नाम	बंधक/भार सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि एवं कब्जा सूचना की तिथि	चकाया धनराशि
उधारकर्ता: मेसर्स संजु कुमार, प्रो. श्रीमती संजु कुमारी	जमानतदार: श्री अनिल कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह एवं श्री अरविन्द कुमार सिंह	जमीन एवं भवन का सांयिक बंधक जो श्री मुन्ना सिंह पिता-शिवाजी सिंह, मौजा-हकिमपुर, थाना नं.-157, थाना-डुमराव, जिला-बक्सर, अंचल-डुमराव, खाता नं.-26, प्लॉट नं.-15 एवं 16, रकबा-1 कट्ठा 05 धुर, सेल डीड नं.-643 तिथि 22/01/2014, चौहद्दी: उत्तर-निज मनमोहक, दक्षिण-रास्ता, पूर्व-चान्द, पश्चिम-कनक सिंह एवं मयूर सिंह।	11.07.2025 एवं 22.12.2025	₹4,31,85,253/- रि. 30.06.2025 तक इसके अलावा अतिरिक्त बढ़ा हुआ ब्याज, शुल्क, अन्य विविध व्यय आदि दिनांक 01.07.2025 से प्रभावशी।

दिनांक : 22.12.2025 **नोट:-विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।** **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : डुमराव **भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्तियां वसूली शाखा, पटना**

This advertisement is for information purposes only and not for publication, distribution or release directly, outside India. This advertisement does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell the securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated February 28, 2026 ("Letter of Offer" or "LOF") filed with BSE Limited ("BSE"), National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

HILTON METAL FORGING LIMITED
CORPORATE IDENTITY NUMBER: L28900MH2005PLC154986

Our Company was incorporated as "Hilton Metal Forging Limited" on July 21, 2005, as a public limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra, the "RoC" bearing Registration No. 154986 upon conversion of a partnership firm named "M/S Hilton Forge". Our Company received its certificate of commencement of business dated September 09, 2005 from the RoC. For details of the change in the address of the registered office of our Company. For details see "General Information" on page 41 of this Letter of Offer.

Registered & Corporate Office: 303, Tanishka Commercial Co-op. Society Ltd, Akurli Road, Kandivali East, Mumbai, Kandivali East, Maharashtra, India, 400101; **Telephone:** + 91 22 4042 6565; **Email:** info@hiltonmetal.com; **Website:** www.hiltonmetal.com; **Contact Person:** Mrs. Richa Shah, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. YUVRAJ HIRALAL MALHOTRA, MRS. DIKSHA YUVRAJ MALHOTRA AND MS. YASHIKA YUVRAJ MALHOTRA
FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF HILTON METAL FORGING LIMITED ("OUR COMPANY" / "ISSUER") ONLY

ISSUE OF UPTO 1,67,70,000* FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF HILTON METAL FORGING LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹166.68/- EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹68.68/- PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AMOUNT AGGREGATING UPTO ₹ 2797.24 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 29 (TWENTY-NINE) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 60 (SIXTY) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE HELD BY SUCH ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2026. ("ISSUE"). THE ISSUEPRICE IS 1.67 (ONE POINT SIXTY-SEVEN) TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE. FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED 'TERMS OF THE ISSUE' BEGINNING ON PAGE 83 OF THE LETTER OF OFFER (the "LOF").

*Assuming full subscription with respect to Rights Equity Shares.
Assuming full subscription and receipt of all Call Monies with respect to Rights Equity Shares.

PAYMENT SCHEDULE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES			
AMOUNT PAYABLE PER RIGHTS EQUITY SHARE*	FACE VALUE (₹)	PREMIUM (₹)	TOTAL (₹)
On Application	10	6.68	16.68

*For details on the payment method, please refer to the chapter titled "Terms of the Issue" on page 83 of this Letter of Offer

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Hilton Metal Forging Limited wishes to thank all its shareholders and investors for their response to the issue which opened for subscription on Friday, March 06, 2026 and closed on Thursday, April 02, 2026 and the last date for on-market renunciation of Rights Entitlements was Tuesday, March 10, 2026. Out of the total 2616 Applications for 20092093 Equity Shares, 322 Applications for 534226 Equity Shares were rejected on the basis of Ground for technical rejections as disclosed in the Letter of Offer.

Sr. no.	Category	Number of Applications	Number of Equity Shares applied for against Res	Number of additional Equity Shares applied for	Total Equity Shares applied for
A.	Eligible Equity Shareholders	2304	6915826	12529053	19444879
B.	Fractional Shareholders	20	20	102346	102366
C.	Renouces*	11	296262	6311	302573
D.	Not Eligible Shareholders	275	0	177111	177111
E.	Invalid Application	6	0	65164	65164
	Total	2616	7212108	12879985	20092093

*The Investors (identified based on PAN) whose names do not appear in the list of Eligible Equity Shareholders on the record date and who hold the REs as on the Issue Closing Date and have applied in the Issue are considered as the Renouces.

After removing technical rejections (details of which are given in the subsequent paragraphs), the total number of valid applications eligible to be considered for allotment were as detailed below:

Sr. No.	Particulars	Number of Applications	Number of Equity Shares
1	Gross Applications	2616	20092093
2	Less: Rejections	322	534226
	Net valid Applications considered for Allotment (1 - 2)	2294	19557867

Category	Gross			Less: Rejections/Partial Amount			Valid		
	Applications	Shares	Amount (₹)	Applications	Shares	Amount (₹)	Applications	Shares	Amount (₹)
Eligible Equity Shareholders	2304	19444879	324340581.72	39	291921	4869242.28	2265	19152958	319471339.44
Fraction	20	102366	1707464.88	2	30	500.40	18	102336	1708964.48
Renouces	11	302573	5046917.64	0	0	0.00	11	302573	5046917.64
Not an eligible equity shareholders of the company	281	242275	4041147.00	281	242275	4041147.00	0	0	0.00
Total	2616	20092093	335136111.24	322	534226	8910889.68	2294	19557867	326225221.56

Conclusion
Based on the above discussions, the Basis of Allotment was prepared and it was decided that the same be submitted to NSE, the Designated Stock Exchange, for its approval, along with a set of the relevant documents. Summary of Allotment in various categories is as under:

Category	Number of Equity Shares Allotted - against REs	Number of Equity Shares Allotted - Against valid additional shares	Total Equity Shares Allotted
Eligible Equity Shareholders	6877905	9595833	16473738
Renouces	296262	0	296262
Total	7174167	9595833	16770000

Intimations for Allotment/Refund/Rejection cases: The dispatch of allotment advice-cum-refund/unblocking intimation and the communication of reasons for rejection, as applicable, to the investors has been completed on April 08, 2026. The instructions to the SCSBs for unblocking of funds in case of ASBA applications were issued on April 08, 2026. The listing application was submitted to BSE and NSE on April 7, 2026, and the listing approval is expected to receive on or before April 08, 2026.

The Credit of Equity Shares in dematerialized form to the respective demat accounts of the allottees will be completed on or before April 09, 2026. For further details, please refer to the section titled "Terms of the Issue – Allotment Advice or Refund/Unblocking of ASBA Accounts" on page 83 of the Letter of Offer. Pursuant to the listing and trading approvals granted/ to be granted by BSE and NSE, trading in the Rights Equity Shares allotted in the Issue is expected to commence on BSE and NSE on or before April 10, 2026.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALIZED FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE):
It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by NSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the disclaimer on page 78 under paragraph titled "Disclaimer Clause of NSE (The Designated Stock Exchange)".

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE
It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the disclaimer on page 77 under paragraph titled "Disclaimer Clause of BSE".

REGISTRAR TO THE ISSUE

PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED
Address: Unit No. 9, Ground Floor, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Lower Parel (East), Mumbai – 400011, Maharashtra, India;
Tel No: +91 22 49614132+ 91 22 49700138;
Email: npwssu@purvashare.com; **Website:** www.purvashare.com
Contact Person: Ms. Deepali Dhuri;
Investor Grievance: nseissue@purvashare.com
SEBI Registration Number: INR000001112

Investors may contact the Registrar or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre issue or post issue related matter. All grievances relating the ASBA process may be addressed to the Registrar, with a copy to the SCSBs in case of ASBA process, giving full details such as name, address of the Applicant contact number(s), e-mail address of the sole first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked (in case of ASBA process), ASBA Account number, and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form or the plain paper applications as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip (in case of ASBA process).

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For Hilton Metal Forging Limited
Sh/
Mrs. Richa Shah
Company Secretary & Compliance Officer

Date: April 08, 2026
Place: Mumbai

सेलकॉर गैजेट्स लिमिटेड
सीआईएन: L32300DL2020PLC375196
पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय: एजी-12, शालीमार बाग, दिल्ली-110088
लैंडलाइन: 011-49934764, 011-49934734, वेबसाइट: www.celecor.com, ई-मेल आईडी: cs@celecor.in

पोस्टल बैलेट की सूचना तथा ई-वोटिंग की जानकारी

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और नियम 22 (किसी भी वैधानिक संशोधन या तत्समय लागू उसके पुनः अधिनियमन सहित) ("नियम") के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 110 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, (किसी भी वैधानिक संशोधन या तत्समय लागू पुनः अधिनियमन सहित), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 ("सूचीबद्धता विनियम"), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 संपठित इस संबंध में जारी किए गए एवं प्रासंगिक परिपत्रों, नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 ("एमसीए परिपत्र"), सामान्य बैठकों पर भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक ("एसएस-2") और किसी भी अन्य लागू कानून, नियम और विनियम (तत्समय लागू होने वाले किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसार, सेलकॉर गैजेट्स लिमिटेड के सदस्यों को मंजूरी लेने के लिए दिनांक 07 अप्रैल, 2026 के पोस्टल बैलेट नोटिस ("पोस्टल बैलेट नोटिस") में निर्धारित व्यवसाय का लेन-देन करने के लिए, पोस्टल बैलेट के माध्यम से उक्त संकल्पों को पारित करके, केवल रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रक्रिया से बैठक आयोजित की जाएगी।

पोस्टल बैलेट नोटिस 07 अप्रैल, 2026 को केवल उन पात्र सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजा जा रहा है, जिन्होंने कट-ऑफ तिथि यानी 03 अप्रैल, 2026 को डिफॉजिटरी/उनके डिफॉजिटरी प्रतिभागी/कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों/कंपनी के साथ अपने ई-मेल पते पहले ही पंजीकृत कर लिए हैं।

रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट द्वारा निम्नलिखित संकल्पों के लिए सेलकॉर गैजेट्स लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की मंजूरी मांगी जा रही है।

क्र.सं.	संकल्प का विवरण
1	कंपनी के प्रबंध निदेशक और प्रमोटर श्री रवि अग्रवाल को अधिमात्री आधार पर 3,50,00,000 (तीन करोड़ पचास लाख मात्र) तक के पूर्ण परिवर्तनीय वारंट ("वारंट") जारी करना

उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, नोटिस या पोस्टल बैलेट फॉर्म की भौतिक प्रतियों का कोई प्रेषण नहीं होगा। सदस्यों के मतदान का अधिकार शुक्रवार, 03 अप्रैल, 2026 को इस उद्देश्य के लिए निर्धारित कट-ऑफ तारीख है, को व्यावसायिक घंटों की समाप्ति पर उनके द्वारा धारित इलेक्ट्रॉनिक शीयर्स पर परिगणित किया जाएगा।

कंपनी ने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्विटीटीज डिफॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की सेवाएं ली हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि ई-

संपादकीय जनसत्ता

8 अप्रैल, 2026

कल्पमेधा

आपको जो भी मिला है, उसका अधिक मूल्यांकन न करें और न ही दूसरों से ईर्ष्या करें।

वे लोग जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, उन्हें मन की शांति कभी प्राप्त नहीं होती।

– गौतम बुद्ध

युद्ध की आग

ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद शुरू हुए युद्ध को अब एक महीना से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब भी तनाव और टकराव की आक्रामकता में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। बीच-बीच में युद्ध विराम की बात उठती है और अगले ही दिन पहले से ज्यादा तीव्रता वाले हमलों के बीच गुम होकर रह जाती है। खबरों के मुताबिक, अमेरिका ने ईरान के खर्ग द्वीप पर फिर हमला किया। इसके अलावा, ईरान के अल्बोर्ज प्रांत में हुए ताजा हवाई हमले में कम से कम अठारह लोगों की मौत हो गई। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है कि अगर ईरान मंगलवार रात आठ बजे तक होर्मुज जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह बहाल नहीं करता है, तो उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों पर बमबारी की जाएगी। सवाल है कि क्या अमेरिका को इस बात की फिक्र है कि नागरिक ढांचों पर होने वाले हमलों को युद्ध अपराधों के दायरे में देखा जा सकता है। ईरान में हमले की वजह से एक स्कूल की कई बच्चियों की मौत को लेकर पहले ही अमेरिका-इजराइल के रवैये पर तीखे सवाल उठ चुके हैं।

ऐसा लगता है कि इस युद्ध में हमले के टिकाने चुनने के मसले पर मानवीयता के प्रश्न पीछे छूट गए हैं। जहां इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान पर मिसाइल की मार करने से लेकर बमबारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, तो वहीं ईरान ने भी इजराइल सहित मध्य-पूर्व के देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला करने में कोई कमी नहीं की है। इससे इतर युद्ध की वजह से मध्य-पूर्व के समूचे प्रभावित इलाके में जिस पैमाने पर कच्चे तेल का उत्पादन और उसका कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है, उसका असर समूची दुनिया पर किसी न किसी रूप में पड़ रहा है। बहुत सारे देशों में तेल, गैस और खाद की आपूर्ति बाधित हुई है। विडंबना यह है कि यह सब देखने-समझने के बावजूद युद्ध को खत्म करने या कम से कम कुछ दिनों के विराम की बात भी टोस तरीके से सिरा नहीं पकड़ रही है। एक ओर अमेरिका के राष्ट्रपति आए दिन ईरान में सब कुछ नष्ट कर देने की धमकी देते हैं, तो दूसरी ओर ईरान इसका जवाब देने की बात करता है।

तनाव के स्वरूप का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ईरान ने पैंतालीस दिन के युद्धविराम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि वह युद्ध की स्थायी और पूर्ण समाप्ति तथा फिर से ईरान पर आक्रमण नहीं किए जाने की गारंटी चाहता है। एक तरह से ईरान को इस मांग को समझा जा सकता है कि कूटनीतिक प्रयासों की सार्थकता तभी है, जब किसी भी वार्ता के माध्यम से स्थायी समाधान तक पहुंचा जा सके। अगर हल निकालने के लिए चल रही बातचीत में कोई तात्कालिक आश्वासन दिया जाता है और उसमें विश्वसनीयता की कमी होगी, तो ऐसे प्रयास युद्ध के मूल कारणों को दूर करने में नाकाम रहेंगे। बल्कि इसके विपरीत नतीजे भी निकल सकते हैं। जाहिर है, कुछ समय के युद्धविराम की गुंजाइश निकालने के बजाय संघर्ष को पूरी तरह खत्म करने के उपायों पर पहुंचने के उद्देश्य से बिना देर किए शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मगर अभी युद्ध को लेकर जिस तरह की जिद देखी जा रही है, उससे किस तरह का समाधान निकाला जा सकता है। व्यापक पैमाने पर विनाश के बाद जब युद्ध थमेगा, तब किसी भी तरह के समाधान की कीमत क्या होगी?

धमकियों का जाल

देश भर में शिक्षा संस्थानों, अस्पतालों, सरकारी भवनों और अन्य सार्वजनिक स्थलों को बम से निशाना बनाने की झूठी धमकियों का बढ़ता सिलसिला सुरक्षा की लिहाज से चुनौती बन गया है। ई-मेल या फिर सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की धमकियां दी जाती हैं, जिससे न केवल लोगों में दहशत फैलती है, बल्कि सुरक्षा एजंसियों का कीमती समय और संसाधन भी बर्बाद होते हैं। बीते सोमवार को चंडीगढ़ के कई स्कूलों और सरकारी इमारतों को बम से उड़ाने की धमकियां ई-मेल पर दी गईं, हालांकि जांच में कुछ भी सदिग्ध नहीं मिला। संभवतः धमकी देने वालों का मकसद महज दहशत फैलाना ही रहा होगा। मगर सवाल है कि आखिर इस तरह की घटनाओं पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहा है? क्या सुरक्षा एजंसियां धमकी देने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने में तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है? ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह के ज्यादातर मामलों में पुलिस या अन्य जांच एजंसियां अपराधियों तक पहुंच ही नहीं पाती हैं।

गौरतलब है कि हाल के वर्षों में बम की झूठी धमकियां देने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। मई, 2024 में दिल्ली-एनसीआर में एक ही दिन में करीब ढाई सौ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से पुलिस के हाथ-पांव फूल गए थे। हालांकि, इस तरह की तमाम धमकियां झूठी साबित हुई हैं, लेकिन इससे जहां दहशत का माहौल पैदा हो जाता है, वहीं जांच एजंसियों के सामने कई चुनौतियां पैदा हो जाती हैं। ऐसे मामलों में अब तक की जांच में सामने आया है कि धमकी भरे ज्यादातर ई-मेल वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए विदेशी आडों पी पते से भेजे जाते हैं। मगर आज डिजिटल तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि इसके जरिए दुनिया के किसी भी कोने में छिपे अपराधी को खोजा या पकड़ा जा सकता है। मगर पुलिस और अन्य जांच एजंसियों में अलग से बनाई गई साइबर शाखाओं के विशेषज्ञ क्या डिजिटल तकनीक में इतने पारंगत नहीं हैं कि वे ऐसे अपराधियों का पता लगा सकें? सरकार और प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि यह केवल दहशत फैलाने का मामला नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा और तकनीकी क्षमता का भी सवाल है।

जलवायु संकट से जटिल होती चुनौतियां

जलवायु संकट केवल पर्यावरणीय आपदा नहीं, बल्कि बहुआयामी चुनौती है। यह आर्थिक असमानता को गहरा रही है और सामाजिक स्थिरता को मुश्किल में डाल रही है। यह समस्या केवल मौसमी अनियमितताओं तक सीमित नहीं है। यह प्रणालीगत विफलता का भी द्योतक है।

अजय प्रताप तिवारी

वैश्विक प्रगति की दौड़ में, जहां मानव सभ्यता सतत विकास को आत्मसात करने का प्रयास कर रही है, वहीं जलवायु परिवर्तन एक अदृश्य, लेकिन दुर्जेय अवरोध के रूप में उभरा है। आज के विश्व में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में निहित आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय संतुलन के त्रिविमीय उद्देश्य बाढ़, सूखा और प्राकृतिक आपदाओं की भंवर में उलझ जाते हैं। जलवायु संकट केवल पर्यावरणीय आपदा नहीं, बल्कि बहुआयामी चुनौती है। यह आर्थिक असमानता को गहरा रही है और सामाजिक स्थिरता को संकट में डाल रही है। यह संकट केवल मौसमी अनियमितताओं तक सीमित नहीं है। यह प्रणालीगत विफलता का भी द्योतक है।

हिमालयी क्षेत्रों में हिमनदों के तेजी से पिघलने से जल संसाधनों का संकट बढ़ रहा है। यह स्थिति भारत की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी, जहां साठ फीसद से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रपट चेतावनी देती है कि यदि वैश्विक तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर जाती है, तो सतत विकास लक्ष्य जैसे- सबको भोजन, स्वच्छ जल, आर्थिक समानता, जलवायु कार्रवाई जैसे लक्ष्य असाध्य हो जाएंगे। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की अवधि वर्ष 2030 निर्धारित है। वैश्विक लक्ष्यों में गरीबी खत्म करना, पर्यावरण की रक्षा, नवाचार, टिकाऊ उपभोग, आर्थिक असमानता को कम करना और सभी के लिए शांति और न्याय सुनिश्चित करना शामिल है। जबकि ऊर्जा संसाधनों पर एकाधिकार के लिए हो रहे युद्ध इस बात का संकेत है कि सतत विकास और समावेशी समाज के निर्माण का संयुक्त राष्ट्र का स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा। पश्चिम एशिया में जारी अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष न केवल रणनीतिक नुकसान है, बल्कि यह एक बड़ा पर्यावरणीय संकट है। इसके प्रतिकूल परिणाम दीर्घकालिक होंगे।

ब्रिटेन स्थित पर्यावरणीय शोध संस्था ‘कमिन्सलव एंड एनवायरनमेंट आब्जर्वेटरी’ ने युद्ध के दौरान तीन सौ से अधिक जगहों को चिह्नित किया है, जहां पर्यावरण को गंभीर नुकसान हुआ है। ईरान की तेल रिफाइनरियों पर हुए हमलों से हजारों टन तेल समुद्र में पहुंच रहा है, जो समुद्री जीवों के पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर रहा है। विस्फोट से विषैला धुआं श्वास रोग को बढ़ावा दे रहा है। इतना ही नहीं ऊर्जा, खाद्य संकट, गरीबी और महंगाई विकासशील राष्ट्रों के लिए विशेष रूप से जटिल समस्या है। जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक स्तर पर खाद्य संकट की समस्या पहले से बढ़ रही है। खाद्य संकट पर एक वैश्विक रपट के अनुसार 53 देशों में 29 करोड़ पचास लाख से अधिक लोग गंभीर भुखमरी से प्रभावित हैं। भारत सहित विकासशील देशों में कृषि पर वर्षा और मौसम का गहरा असर देखने को मिलता है। यहां के किसानों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। यह समस्या करीबन हर साल सामने आती है।

दूसरी ओर कहा जा रहा है कि गेहूं और धान जैसी प्रमुख फसलों की कुल उपज में छह से 25 फीसद और धान में तीन से 15 फीसद तक कमी आ सकती है। अनियमित मानसून, सूखा और बाढ़ कृषि उत्पादन को



अस्थिर कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट भी बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रपट से पता चला है कि वर्तमान समय में हर दूसरा व्यक्ति जल संकट की समस्या से जूझ रहा है। विश्व बैंक ने अपने एक अध्ययन में अनुमान लगाया है कि स्वच्छ जल की कमी से प्रत्येक वर्ष 260

जलवायु परिवर्तन, गरीबी, असमानता, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे किसी एक देश तक सीमित नहीं हैं, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि कुछ देशों के बीच युद्ध के कारण पूरी दुनिया में मानवता खतरे में है। इसी के साथ पशु-पक्षियों का जीवन भी संकट में है। पर्यावरण हितैषी जीवों की चिंता इस समय किसी को नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध और मानवता के लिए बनाए गए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय नियम सिर्फ कमजोर देशों के लिए बने हैं। जिनेवा सम्मेलन ने पर्यावरणीय नुकसान को युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा है। यह अचरज की बात है संयुक्त राष्ट्र और रेडक्रास जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं महाशक्तियों के आगे मौन हैं। युद्ध जैसी घातक विपदा खत्म होने के बाद भी पर्यावरणीय घाव लंबे समय तक बने रहते हैं। ऐसे तो सतत विकास के लक्ष्य वैश्विक हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बिना इन लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विकासशील देशों को वित्तीय सहायता, तकनीकी ज्ञान और नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करना जरूरी है। मगर विकसित देश इसमें रुचि नहीं लेते। युद्ध और जलवायु परिवर्तन की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी देशों को एक मंच पर आना होगा। यह केवल पर्यावरणीय चिंता का विषय नहीं है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के लिए भी इससे खतरा है। इस संकट से निपटने के लिए हर स्तर पर समन्वित प्रयास आवश्यक है।

अरब डालर का नुकसान होता है। स्थिति गंभीर है क्योंकि अब दुनिया को आगाह किया जा रहा है कि जल संकट से जूझ रहे देशों को वर्ष 2050 तक

भरोसे की शक्ति

अनंतपद्मनाभन

मानव मन एक अद्भुत पहलू है, जो एक क्षण में ब्रह्मांड की सीमाओं को लांघ सकता है और दूसरे ही पल एक छोटी-सी आशंका के पिंजरे में कैद हो सकता है। हम कल्पना करं कि हमने अभी-अभी कोई महत्त्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया है। चारों ओर प्रशंसा के शब्द गूँब रहे हैं और हमें सम्मान मिल रहा है। सफलता के उस शिखर पर मन में केवल संतोष होना चाहिए, लेकिन जैसे ही शोर थमता है और हम खुद के साथ होते हैं, तो हमारा मन शांत होने के बजाय एक अजीब-सी उथल-पुथल में फिर जाता है। हमारा मस्तिष्क अचानक एक जासूस की भूमिका निभाते हुए पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करने लगता है। वह बार-बार उसी एक पल पर अटक जाता है, जहां कुछ 'अधूरा' रह गया था- "मैं उस समय क्यों हिचकिचाया? क्या मैं और बेहतर बोल सकता था?" भले ही हमारी सफलता सौ फीसद रही हो, लेकिन दिमाग न जाने क्यों उस एक फीसद की 'खामी' को ढूँढ़ निकालता है। यह स्थिति एक ऐसे मानसिक भ्रम की रचना करती है, जो हमारी पूरी सफलता की चमक को सोखने लगती है। दरअसल, बरसों से हमारे दिमाग को गलतियाँ ढूढ़ने और जोखिमों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

जब हम दिन भर समस्याओं को सुलझाने और खुद को त्रुटिहीन बनाने की दौड़ में लगे रहते हैं, तो वही तेज दिमाग घर आने के बाद भी अपनी गति को नियंत्रित करना भूल जाता है। यह नकारात्मक चिंतन का एक चक्र है, जो हमारे निजी रिश्तों और खुशियों में दखल देने लगता है। हमें लगता है कि हम 'सुधार' के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह मन को थकाने वाला एक व्यर्थ चक्र है। इतिहास गवाह है कि बड़े-बड़े विद्वानों का मन भी कभी-कभी उनका साथ छोड़ देता था। आधुनिक विज्ञान के आधार स्तंभ सर आइज़ैक न्यूटन अक्सर छोटी-छोटी आलोचनाओं पर हफ्तों तनाव में रहते थे। न्यूटन का मस्तिष्क ब्रह्मांड के रहस्यों को तो सुलझा लेता था, लेकिन स्वयं की शांति बनाए रखना उनके लिए चुनौती थी। वे अपनी खोजों को दुनिया के सामने रखने से इतना डरते थे कि कहीं कोई उनमें कोई कमी न निकाल दे। इस तरह के उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि बुद्धि एक तेज औजार की तरह है। अगर इसे सही नियंत्रण के साथ नहीं संभाला गया, तो यह स्वयं को ही चोट पहुंचा सकती है। इसी तरह, महान सिल्विल इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया की रचना इतनी पैनी थी कि वे चलती रेलगाड़ी में केवल कंपन महसूस करके पटरी की दरार भांप लेते थे। कार्य के प्रति यह सजगता अद्भुत थी, पर इसका अर्थ यह भी था कि उनका मन हमेशा एक 'सतर्क भाव' में रहता था।

आज सब एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं। हम अक्सर अपनी छोटी-छोटी खुशियों को अनदेखी कर देते हैं। पहले हमारी अपने जीवन में जो मुकाम हासिल किया है, उसे बनाने में सालों की मेहनत लगी है। उस मेहनत का मूल्य समझना चाहिए और अपनी उपलब्धियों को केवल धन-दौलत के तराजू में नहीं तौलना चाहिए। हमारी बुद्धि एक वरदान है। इसे खुद को नुकसान पहुंचाने का हथियार नहीं बनने देना चाहिए। कमियां ढूढ़ने वाले मन को यह सिखाना हमारी जिम्मेदारी है कि उसे कब शांत होना है। हमारी भावनाएं कोई 'गलतियां' नहीं हैं, वे हमारे जीवित होने का प्रमाण हैं। दुनिया की तमाम सफलता एक तरफ है, लेकिन हमारा अतिरिक्त सुकून ही हमारी सबसे असली पूंजी है। हमें व्यर्थ की चिंताओं को त्यागना चाहिए और अपनी मेहनत काबालियन पर अडिग विश्वास बनाए रखना चाहिए।

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

व्यवस्था पर सवाल

हाल ही में पश्चिम बंगाल के मालदा में सात न्यायिक अधिकारियों को उग्र भीड़ द्वारा कई घंटे तक बंधक बना कर रखा जाना कानून-व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाता है। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन नागरिकों का अधिकार है, लेकिन जब यह विरोध हिंसक रूप ले ले, तब यह केवल राजनीतिक असहमति का मामला नहीं रह जाता, बल्कि प्रशासनिक विफलता का संकेत बन जाता है। चुनावी दौर में राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज होना सामान्य है, पर कानून-व्यवस्था बनाए रखना किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। यह अपेक्षा की जाती है कि प्रशासन निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से कार्य करे, ताकि आम नागरिकों का भरोसा कायम रहे। यदि प्रशासनिक निर्णय राजनीतिक समीकरणों से प्रभावित होते प्रतीत हों, तो यह लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है। बंगाल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध राज्य रहा है। ऐसे राज्य में कानून-व्यवस्था तथा सामाजिक सौहार्द बनाए रखना और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

– अश्विंद रावल, झाड़ुआ

संवाद का रास्ता
संकट बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। ऐसे समय में यह जरूरी है कि सभी पक्ष संवाद का रास्ता अपनाएं। भारत द्वारा शांति, संयम और कूटनीति पर जोर देना उसके संतुलित और जिम्मेदार दृष्टिकोण को दर्शाता है। युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। यदि विश्व समुदाय मिल कर संवाद और सहयोग को प्राथमिकता दे, तो स्थिरता और शांति सुनिश्चित हो जा सकती है।
– आशुतोष पांडेय, जम्मू

महंगी होती शिक्षा

पिछले कुछ वर्षों में स्कूली किताबों की कीमतों में लगातार वृद्धि ने अभिभावकों की आर्थिक स्थिति पर दबाव डाला है। सरकारी पर कोई स्थायी प्रश्नचिह्न। काम के बाद प्रकृति के करीब समय बिताना या शांत बैठना दिमाग को संदेश देता है कि अब दिमाग का समय है। खुद के प्रति उदार होना ही वह चाबी है जो हमें इस वैचारिक जेल से बाहर निकाल सकती है। हमने

संवाद के बजाय' (संपादकीय, 3 अप्रैल) पढ़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसे आक्रामक और दंभ भरे बयान देते रहते हैं, जिनसे स्थिति और जटिल हो रही है। उनके बयानों की वजह से ईरान की प्रतिक्रिया और अधिक आक्रामक रूप से सामने आती है। वह अमेरिकी और इजराइल के टिकानों पर लगातार मिसाइल हमले कर रहा है। लगता है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। प्रतिक्रिया की इस लड़ाई में दुनिया भर के देश इस संघर्ष की चपेट में आ रहे हैं और जिस प्रकार से ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है, उससे उद्योग धंधों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है। पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। ऐसे में वैश्विक संस्थाओं का मूक बने रहना ठीक नहीं। यह निश्चित है कि संघर्ष का अंत बातचीत से ही निकलेगा। मगर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, यह भविष्य बताएगा।

– वेद प्रकाश, गुहाग्राम

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि स्वैच्छक सेवानिवृत्ति नौकरी छोड़ने या काम बंद करने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी का विशिष्ट अधिकार है जो निर्धारित वर्षों की सेवा पूरी होने के बाद प्राप्त होता है। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 2019 के दो अलग-अलग आदेशों को चुनौती देने वाली अपीलों पर अपना फैसला सुनाया। एक बैंक ने यह अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय ने एक बैंक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने का निर्देश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि स्वैच्छक सेवानिवृत्ति के नोटिस में निर्दिष्ट तीन महीने की नोटिस अवधि पूरी होने के बाद या काम पर आना बंद करने की तारीख से, उसे स्वैच्छक रूप से सेवानिवृत्त माना जाए। उच्चतम न्यायालय ने गौर किया कि कर्मचारी की नियुक्ति सितंबर 1983 में हुई थी और अप्रैल 2007 में उसे प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया।

लोकसभा की संचार और प्रौद्योगिकी समिति ने की सिफारिश

पश्चिम एशिया संकट

कृत्रिम मेधा का दुरुपयोग रोकने के लिए कानून लाए सरकार

गिरने लगा स्वदेशी चिकित्सा उपकरण का उत्पादन

पंकज रोहिला

कृत्रिम मेधा (एआई) के गलत प्रयोग से नागरिकों को बचाने के लिए एक नए कानून की आवश्यकता है। इन कानून (विधेयक) की मदद से नागरिकों को वित्तीय धोखाधड़ी, डराने धमकाने अथवा डीपफेक आडियो वीडियो से बचाया जा सकेगा। इस कानून का विशेष लाभ इस जाल में फंस जाने वाले महिलाओं व बच्चों को हो सकेगा। केंद्र सरकार को इस विधेयक पर तत्काल काम करने की आवश्यकता है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने सरकार से इस विधेयक को तैयार करने की सिफारिश की है।

संसदीय समिति का मानना है कि एआई का प्रयोग नैतिक व जिम्मेदाराना तरीके से होना चाहिए। विश्व के अनेक देश इस दिशा में कई पहल कर चुके हैं और कानून तैयार कर चुके हैं। ये कानून बाध्यकारी हैं। इसी तर्ज पर भारत में भी ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने इस रपट को संसद में पेश किया है। समिति ने कहा कि इस विधेयक में ऐसा भी प्रावधान किया जाए, जिसमें कुछ सोशल प्लेटफॉर्म पर आने के लिए आयु सीमा को भी तय किया जाए ताकि नागरिकों को एआई के प्रयोग से रोका जा सके।

एआई दुपुयोग रोकने के लिए मानव संधान की विशाल मानव संसाधन की क्षमता को विकसित करने की सिफारिश संसदीय समिति की ओर से की गई है। इसमें विशेषतौर पर कालेज में एआई को लोकप्रिय बनाने और सभी विश्वविद्यालयों में फैलोशिप, अकादमी



गृह मंत्रालय जल्द लाएगा, एआई आधारित शिकायत प्रणाली

रपट में गृह मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी है कि वह आइ4सी 1930 साइबर अपराध सहायता के लिए एआई सहायता प्राप्त शिकायत पंजीकरण प्रणाली लागू की योजना पर काम कर रहा है। दावा किया है कि इस पहल से शिकायत दर्ज करने में लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा और उपयोगकर्ताओं के अनुभव के आधार पर इसमें सुधार किया जा सकेगा। हालांकि मंत्रालय ने बताया कि वह साइबरदोस्त के नाम से एक सोशल मीडिया हैंडल भी चला रहा है, जो मामले दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान बना रहा है। इसके अतिरिक्त एक 'एप्लीकेशन' भी भविष्य के लिए मंत्रालय की ओर से विकसित की जा रही है।

मांग

अनुसंधान (पीएचडी), डेटा केंद्र, एआई लैब और शिक्षण प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति योजना की भी सिफारिश सरकार को की गई है। इन योजनाओं मदद से भविष्य में एआई को अधिक प्रभावी तौर पर लागू करने में भी मदद मिलेगी। मंत्रालय के चुनाविक संबंधित धोखेबाज विभिन्न तरीकों से मौजूदा बुनियादी ढांचे का फायदा उठाते हैं, जिसमें बैंकिंग (म्यूचुअल अकाउंट, वचुअल अकाउंट, पेमेंट एग्रीग्रेटर, पेमेंट गेटवे, सीबीडीसी का दुपुयोग, क्रिप्टो करंसी आदि), टेलीकॉम (म्यूचुअल सिम, सिमबाक्स, एसएमएस हैंडल, काल) आदि का प्रयोग धोखेबाजी के लिए किया जाता है।

अवैध प्रवेश और डिजिटल सुरक्षा के लिए प्रयोग करें एआई : एक अप्रैल 2026 से शुरू हुई मिशन मोड परियोजना के तहत आप्रवासन, वीजा विदेशियों का पंजीकरण और ट्रैकिंग के लिए एआई आधारित मशीनों का प्रयोग करने की योजना है। इस आंकड़े का प्रयोग कर भविष्य में प्रामाणिकता और सुरक्षा बढ़ाने पर काम होगा। समिति के सामने यह भी आया है कि अभी तक दुनिया के किसी भी देश के साथ अफेडी साझा करने पर कोई सहयोग नहीं मिला है। इसलिए समिति ने इस कानून को और सख्त और मजबूत बनाने पर जोर दिया है।

जनसत्ता ब्यूरो

पश्चिम एशिया संकट के चलते देश में स्वदेशी चिकित्सा उपकरण का उत्पादन गिरने लगा है। कई छोटी इकाइयां बंद होने के कारण पर पहुंच गई है, जबकि काफी जगहों पर कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित होने से उत्पादन सुस्त होता जा रहा है। देश में हर दिन लाखों मरीजों के इलाज के लिए एक बार इस्तेमाल होने वाले चिकित्सा दस्ताने, 'सिरिज' और 'आइवी सेट', 'कैथेटर' सहित अन्य की जरूरत होती है। इस जरूरत का करीब 80 फीसद आपूर्ति भारत में निर्मित चिकित्सा उपकरण से ही होता है।

मौजूदा समय में देश की छोटी व मध्यम स्तर की कंपनियां इनकी आपूर्ति कर रही हैं, लेकिन युद्ध के कारण मार्च में इन कंपनियों का लाभ 15-25 फीसद तक कम हो गया। बावजूद इसके शुरुआत में अधिकांश कंपनियां लागत वहन करती रही, लेकिन अब कई निर्माताओं ने दीर्घकालिक अनुबंधों पर पुनर्विचार कर पिछले एक सप्ताह में गैर-अनुबंधित व्यवसाय के लिए कीमतों में 15-20 फीसद तक की वृद्धि कर दी है। इसका असर आने वाले दिनों में मरीजों के इलाज पर दिखेगा। चिकित्सा उपकरण के उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में हर साल पांच से सात अरब 'सिरिज' और सुइयों बनती हैं। भारत अभी भी 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की 'सिरिज' और सुइयों आयात करता है, जबकि 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की 'सिरिज' निर्यात भी करता है। भारत की



दाम बढ़ने के बाद भी बंद होने के कारण पर पहुंच रही छोटी इकाइयां, उपलब्ध नहीं हो पा रहा कच्चा माल, हर दिन लाखों मरीजों को होती हैं इनकी जरूरत।

80 फीसद आपूर्ति स्वदेशी उत्पादन से, निर्यात का सामान होता है बड़े निजी अस्पतालों में इस्तेमाल।

जरूरत को पूरा करने के लिए स्थानीय स्तर पर हो रहे उत्पादन से 70-80 फीसद मांग पूरी होती है। वहीं आयात प्रीमियम ब्रांड या ज्यादा व्यापार लाभ वाले कार्पोरेट अस्पतालों की जरूरतों को पूरा करते हैं। इसमें 30 फीसद 'कैथेटर' और 90 फीसद 'सिरिज/ आइवी सेट' घरेलू होते हैं।

देशभर के सरकारी सहित छोटे शहरों के निजी अस्पतालों में इन सामान को सस्ते दर पर उपलब्ध करवाने की मांग आती है। लेकिन मौजूदा समय में पालिम्बर की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी (60-70 फीसद), भू-राजनीतिक उथल-पुथल के कारण ऊर्जा की लागत में बढ़ोतरी (औद्योगिक इस्तेमाल वाले डीजल की कीमत 20 फीसद और पीएनजी की कीमत 60 फीसद से ज्यादा बढ़ी), जीएसटी दरों में विसंगति (इनपुट पर 18 फीसद बनाम आउटपुट पर 5 फीसद), और माल ढुलाई की लागत में बढ़ोतरी ने सस्ते दर पर उपलब्ध होने वाली सुविधा को प्रभावित कर दिया है।

इसके अलावा आपूर्ति को कच्चे माल की कीमतों में अचानक उछाल और अगली कीमत बढ़ोतरी की घोषणा से पहले खरीदारों द्वारा माल जमा करने की होड़ भी दिख रही है। साथ ही कुछ निर्माता नुकसान कम करने के लिए उत्पादन सीमित कर रहे हैं या युद्ध जल्द खत्म होने की उम्मीद में अनुबंध के तहत आपूर्ति में देरी कर रहे हैं।

सरकार से की है मदद की मांग : भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग संघ के संयोजक राजीव नाथ का कहना है कि इन चिकित्सा उपकरण के उत्पादन पर कुल खर्च कर 60 फीसद हिस्सा कच्चा माल और पैकेजिंग का होता है। ऊर्जा संकट के कारण पिछले पांच सप्ताह में पालिम्बर की कीमतों में अचानक तेजी आई है। इन समस्याओं से ही रही परेशानी के बारे में सरकार को बता दिया गया है। यदि सरकार आयात शुल्क माफ करने के साथ दूसरी मदद करती है तो बड़ी राहत मिलेगी।

बूचड़खाने को निगम क्षेत्र से बाहर करने पर हंगामा

सुनील दत्त पांडेय

तीर्थ नगरी हरिद्वार के नगर निगम क्षेत्र में अब कोई बूचड़खाना नहीं रहेगा। अब यह सब दुकानें नगर निगम क्षेत्र से बाहर सराय गांव में स्थानांतरित की जाएगी। हरिद्वार के नगर निगम की एक बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। तीर्थ नगरी हरिद्वार के उपनगर ज्वालापुर क्षेत्र में 1970 के लगभग से बूचड़खाने की दुकानें चल रही हैं। सोमवार को त्रिभुक्त आडिटोरियम में हुई नगर निगम बोर्ड महत्वपूर्ण बैठक में महापौर किरण जैसल की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित किया गया कि तीर्थ नगरी हरिद्वार के नगर निगम क्षेत्र में बूचड़खाना नहीं रहेगा और बूचड़खाने की सभी दुकानें नगर निगम क्षेत्र से बाहर सराय गांव में स्थानांतरित की जाएगी।

जब नगर निगम की महत्वपूर्ण बैठक में यह प्रस्ताव के पेश किया गया तो एक समुदाय विशेष के कुछ पार्षदों ने इसका विरोध किया और बोर्ड की बैठक में बवाल काटा। इस प्रस्ताव का कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने विरोध किया। परंतु नगर निगम में भाजपा पार्षदों के बहुमत के कारण यह प्रस्ताव पारित हो गया। हरिद्वार नगर निगम की महापौर किरण जैसल ने कहा कि ज्वालापुर उपनगर क्षेत्र की जनता की लगातार मांग आ रही थी कि इस उप नगरी से बूचड़खानों की दुकानों को तुरंत हटाया जाए, जिससे एक वर्ग विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है और बूचड़खाने से महामारी फैलने का भी लगातार खतरा बना रहता है।

हरिद्वार हर की पैड़ी की प्रबंधकारिणी संस्था श्री गंगा सभा के अध्यक्ष पंडित नितिन गौतम ने नगर निगम क्षेत्र से बूचड़खाने की दुकानों को हटाने के नगर निगम बोर्ड के फैसले का जोरदार स्वागत किया है उन्होंने कहा कि ज्वालापुर उपनगर में तीर्थ पुरोहितों के आवास बड़ी तादाद में हैं, जो सदियों से यहां पर रहते आ रहे हैं और इससे तीर्थ नगरी हरिद्वार की मर्यादा का मान बढ़ेगा और पुरोहितों और सनातनियों की भावनाओं को सम्मान मिलेगा। ज्वालापुर में पुरोहितों और सनातनियों के अलावा मुसलिम वर्ग भी काफी संख्या में रहते हैं। संभावित महामारी फैलने को ध्यान में

हरिद्वार के उपनगर ज्वालापुर क्षेत्र में 1970 के लगभग से बूचड़खाने की दुकानें चल रही हैं, लेकिन अब बूचड़खाने की सभी दुकानें नगर निगम क्षेत्र से बाहर सराय गांव में स्थानांतरित की जाएगी। कुछ पार्षदों ने बोर्ड की बैठक में किया विरोध, फिर भी पारित हुआ प्रस्ताव।

उत्तराखंड

रखते हुए हरिद्वार नगर निगम की महापौर किरण जैसल ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जैसल ने बताया कि काफी लंबे समय से ज्वालापुर के तीर्थ पुरोहितों और सनातनियों की ओर से लगातार यह मांग उठाई जा रही थी कि ज्वालापुर उपनगरी से बूचड़खाने की सभी दुकानों को नगर निगम क्षेत्र से बाहर किया जाए। यह फैसला जनहित में लिया गया है।

हरिद्वार नगर निगम के नगर आयुक्त नंदन कुमार का कहना है कि ज्वालापुर क्षेत्र में कच्चे मीट यानी बूचड़खाने की दुकानों को बंद करके नगर निगम क्षेत्र से बाहर सराय गांव में स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सराय में 56 दुकानों का निर्माण किया गया है, जहां पर बूचड़खानों की दुकानें स्थानांतरित की जानी है और जल्दी ही इसे अमल में लाया जाएगा। रेततरा और दाबों में पका हुआ मांस परोसने वालों पर भी आने वाले समय में विचार होगा। जीत पुरोहित संगठन के अध्यक्ष उज्वल पंडित ने कहा कि ज्वालापुर से बूचड़खाने की दुकानों को सराय में स्थानांतरित करने का फैसला स्वागत योग्य है। अखिल भारतीय परशुराम अखाड़े की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि नगर निगम का ज्वालापुर में स्थित बूचड़खाने को सराय क्षेत्र में स्थानांतरित करना सनातनियों का सम्मान है। दूसरी ओर, ज्वालापुर में बूचड़खाने की दुकानों का संचालन करने वालों ने नगर निगम हरिद्वार के इस फैसले का जबरदस्त विरोध किया है। बूचड़खाने की दुकानदारों के संगठन के प्रमुख मोहम्मद मौमिन ने कहा कि शहर से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर सराय गांव में बूचड़खाने की दुकानों को स्थानांतरित करने से उनका रोजगार छिन जाएगा।

सीप्लेन



ऋषिकेश के पशुलोक बैराज पर गंगा नदी के ऊपर एक डी हेलिपैड कनाडा डीएचसी-6 ट्विन ओटर सीप्लेन का परीक्षण किया गया।

विशेष बच्चों को करिअर चुनना होगा आसान

जनसत्ता ब्यूरो

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अब करिअर चुनना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान और व्यवस्थित होने जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने 'करिअर कार्ड' जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों को उनकी रुचि, क्षमता और संभावनाओं के अनुसार सही मार्गदर्शन देना है। ये करिअर कार्ड राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने यूनिसेफ के सहयोग से तैयार किए हैं और अब इन्हें विशेष बच्चों तक भी पहुंचाया गया है, जो समावेशी शिक्षा की दिशा

में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

इन करिअर कार्ड के माध्यम से विद्यार्थियों को करीब 500 अलग-अलग करिअर विकल्पों की विस्तृत जानकारी दी गई है, जिनमें कृषि, कला, मीडिया, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशिक्षण जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं। हर करिअर कार्ड में किसी एक पेशे से जुड़ी पूरी जानकारी सरल भाषा में दी गई है, जिसमें उस क्षेत्र के लिए जरूरी कौशल, पढ़ाई और कोर्स, प्रवेश प्रक्रिया, संभावित छात्रवृत्ति, शिक्षा ऋण, नौकरी के अवसर और शुरुआती वेतन से लेकर भविष्य में वृद्धि की संभावनाओं तक का विवरण शामिल है। इतना ही नहीं, प्रत्येक कार्ड में विशेषज्ञों की राय भी जोड़ी गई है, ताकि विद्यार्थी उस करिअर की वास्तविकता

और संभावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकें। यह पहल केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे व्यावहारिक रूप से उपयोगी बनाने के लिए स्कूलों में

करिअर मेले, चर्चाएं और काउंसिलिंग सत्र आयोजित करने की भी योजना है। शिक्षक और परामर्शदाता विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी रुचियों और क्षमताओं को समझेंगे और उसी आधार पर उन्हें उपयुक्त करिअर विकल्प चुनने में मदद करेंगे। विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहित किया गया है कि वे गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लें, अपनी पसंद और नापसंद खुलकर साझा करें और किसी भी प्रकार की उलझन होने पर शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करें।

बायो गैस व सीबीजी का हो सकता है वाहन व रसोई ईंधन में इस्तेमाल

सर्वेश कुमार

पश्चिम एशिया संकट के दौरान ऊर्जा स्रोतों को लेकर दूसरे देशों पर निर्भरता की वजह से पैदा हो रही स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत कृषि अवशेष खासकर पराली और रसोई से निकलने वाले अवशेषों से तैयार, बायोगैस, संपीडित बायो गैस (सीबीजी) और प्रोड्यूसर गैस के तौर पर ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनका इस्तेमाल वाहनों और रसोई गैस के तौर पर किया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि इसके लिए संसाधन मौजूद हैं, लेकिन नीतिगत बदलाव करने की जरूरत है। इससे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाने में सहूलियत बढ़ेगी और पेट्रोलियम के आयात पर निर्भरता भी धीरे धीरे कम होगी। फसलों के अवशेष यानी पराली से बायोगैस बनाए जा रहे हैं। इसे संपीडित करने के बाद सीबीजी तैयार किया जाता है, जिसे वाहनों वाहनों में सीएनजी या घरेलू पीएनजी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यूरोप के कुछ

कृषि अवशेष पराली और रसोई से निकलने वाले अवशेषों से तैयार, बायोगैस, संपीडित बायो गैस (सीबीजी) और 'प्रोड्यूसर' गैस के तौर पर ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनका इस्तेमाल ईंधन के रूप में वाहनों और रसोई गैस के तौर पर किया जा सकता है।

जिस तरह पेट्रोल में इथेनाल समिश्रण को सफलता मिली है, ठीक उसी तर्ज पर गैसों के लिए डीएमई समिश्रण को और बढ़ावा देना चाहिए।

देशों में इसे अपनाया भी जा रहा है जिसकी भूमिका प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिहाज से अहम हो सकती है। ऊर्जा विशेषज्ञ प्रो देबोजित पालित के मुताबिक, गैस के साथ डीएमई समिश्रण से पेट्रोलियम पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि देश में बायोगैस और कोयले



से गैस के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें हाइड्रोजन होता है, जिसे अलग कर डाइ मिथाइल ईथर (डीएमई) तैयार कर, एलपीजी के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि जिस तरह पेट्रोल में इथेनाल समिश्रण को सफलता मिली है, ठीक उसी तर्ज पर गैसों के लिए डीएमई समिश्रण को और बढ़ावा

देना चाहिए। इसकी मदद से 'प्रोड्यूसर' गैस तैयार कर, रसोई के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है जिसकी क्षमता कमोबेश एलपीजी की तरह ही है।

इससे जहां ऊर्जा संकट से निपटने में सहूलियत होगी तो दूसरी तरफ किसानों के लिए कृषि अवशेषों, खासकर पराली के जलाने से प्रदूषण को समस्या पर भी काफी हद तक नियंत्रण में मदद मिल सकती है। लेकिन, इसके लिए आपूर्ति शृंखला को और बेहतर करना होगा ताकि मांग के मुताबिक आपूर्ति भी की जा सके। इससे ऊर्जा स्रोतों के विकल्प बढ़ने के साथ दूसरे देशों पर निर्भरता भी कम होगी और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलने से भारत ऊर्जा विकल्पों के मामले में भी आत्मनिर्भर हो सकेगा।

कचरे से रसोई गैस बनाने के लिए आइआइटी ने तकनीक विकसित की : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बामबे ने कचरे से रसोई गैस बनाने के लिए एक तकनीक विकसित की है। इसके जरिए सूखे पत्तों और कचरे से रसोई ईंधन बनाया जा सकता है। इस तकनीक के इस्तेमाल से एलपीजी की कम खपत के साथ साथ पर्यावरण को भी फायदा मिल रहा है। आइआइटी ने बायोमास गैसीफायर मशीन तैयार किया है, जिसमें सूखे पत्तों और जैविक कचरे से रसोई गैस बनाया जा सकता है। संस्थान के इसके लिए पेटेंट तकनीक विकसित की है।

निर्वाचन आयोग ने कहा

चुनाव बाद शेष 22 प्रदेशों में भी होगा पुनरीक्षण

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

निर्वाचन आयोग इस महीने पांच विधानसभाओं के चुनाव के बाद दिल्ली सहित शेष 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का तीसरा और अंतिम चरण शुरू कर सकता है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने यह संकेत दिए। इस महीने केरल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और मतगणना चार मई को होगी।

आयोग के अधिकारियों ने बताया कि 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में दूसरे एवं अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के बाद पुनरीक्षण शुरू किया जा सकता है। एक और संभावना है कि चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद इस कवायद को बड़े पैमाने पर शुरू किया जाए। अब तक, पुनरीक्षण 10 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा चुका है। असम में मतदाता सूची का



द्विविध पुनरीक्षण किया गया है। जिन राज्यों में अब तक पुनरीक्षण किया गया, उनमें सिर्फ उत्तर प्रदेश में अब तक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित नहीं हुई है। अब तक के पुनरीक्षण में लगभग 99 करोड़ मतदाताओं में से 60 करोड़ मतदाताओं को कवर किया गया है। शेष लगभग 39 करोड़ मतदाताओं को 17 राज्यों और पांच केंद्र शासित प्रदेशों में प्रस्तावित पुनरीक्षण की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। बीते 19 फरवरी को निर्वाचन

आयोग के अधिकारियों ने बताया कि 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में दूसरे एवं अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के बाद पुनरीक्षण शुरू किया जा सकता है। एक और संभावना है कि चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद इस कवायद को बड़े पैमाने पर शुरू किया जाए। अब तक, पुनरीक्षण 10 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा चुका है। असम में मतदाता सूची का 'विशेष पुनरीक्षण' किया गया है।

आयोग ने दिल्ली सहित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा था कि वो पुनरीक्षण से संबंधित प्रारंभिक कार्य जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि यह कवायद अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है। एक बार इन राज्यों में यह कवायद पूरी होने के बाद पूरे देश में पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक,

लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा था। पत्र में आयोग ने कहा कि मतदाता सूची के अखिल भारतीय विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश पिछले साल जून में दिया गया था। विभिन्न कारणों से पुनरीक्षण से जुड़े कार्यक्रम में बार-बार बदलाव हुआ।

बिहार की तरह राजनीतिक दलों ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में पुनरीक्षण को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने व्यक्तिगत रूप से अपने राज्य में पुनरीक्षण के खिलाफ प्रधान न्यायाधीश की पीठ के समक्ष गुहार लगाई थी। जहां निर्वाचन आयोग बिहार में पुनरीक्षण की तैयारी कर रहा था तब इसके कई अधिकारियों ने दावा किया था कि उनके जमीनी स्तर के पदाधिकारियों को बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमा के कई नागरिक मिलें थे।

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मणिपुर में दो बच्चों की हत्या पर दुःख जताते हुए मंगलवार को कहा कि हालात के नियंत्रण से बाहर निकलने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठोस और तत्काल कदम उठाने चाहिए। ज्ञात हो कि मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने मंगलवार को बम से हमला किया, जिसमें दो बच्चों की मौत हो गई तथा उनकी मां घायल हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया।

राहुल गांधी ने 'एक्स' पर लिखा कि मणिपुर में बीएसएफ जवान के घर में सोते दो नन्हे बच्चों की हत्या की खबर दिल को चीर देने वाली है। मणिपुर में हिंसा की दहकती हुई आग में आज तीन साल बाद भी निर्दोष बच्चे झुलस रहे हैं,

शांति का कोई संकेत दूर-दूर तक नजर नहीं आता। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार इतनी संवेदनशील और पथ्यरदिल हो गई है कि मानो यह भूल चुकी है कि मणिपुर के बच्चे भी देश के बच्चे हैं, हमारा भविष्य हैं।

राहुल गांधी ने सवाल किया कि कब जागेगी ये सरकार। आखिर कब तक अपनों की लाशें गिनते-गिनते मणिपुर करता रहेगा ईतजार। उन्होंने कहा कि मैं बार-बार कहता आया हूँ कि शांति ही एकमात्र रास्ता है। सभी समुदायों को साथ लाकर, संवेदनशीलता से

ही इस संकट का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, मणिपुर सिर्फ एक राज्य नहीं है, जिम्मेदारी है। सिर्फ नाम का एक बयान काफी नहीं, सिर्फ दिखावे का एक दौरा काफी नहीं। आपको ठोस और तत्काल कदम उठाने ही होंगे, इससे पहले कि हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाएं।

देश के बड़े शहरों के 5,000 से अधिक लोग अध्ययन में शामिल सेहत को 42.5% भारतीय कम प्राथमिकता देते हैं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

वेलनेस प्लेटफार्म 'हेबिल्ड' की ओर से किया गया कि 42.5 फीसद भारतीय व्यस्त समय में अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं और 57.8 फीसद का कहना है कि उन्हें पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है, लेकिन वे इसका नियमित रूप से पालन करने में असमर्थ हैं। यह सर्वे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और वास्तव में अमल करने के बीच अंतर को उजागर करता है।

हेबिल्ड के इस अध्ययन में देश के महानगरों और बड़े शहरों से 5,000 से अधिक लोगों को उतर शामिल हैं। यह सर्वे विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर किया गया। अध्ययन में यह भी सामने आया कि 46 फीसद

अध्ययन में यह भी सामने आया कि 46 फीसद प्रतिभागी सक्रियता के माध्यम से फिट रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन नियमितता बनाए रखने में विफल रहते हैं। करीब 90 फीसद प्रतिभागी 45 वर्ष और उससे अधिक आयु की उमर से अधिक आयु की महिलाएं थीं।

प्रतिभागी सक्रियता के माध्यम से फिट रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन नियमितता बनाए रखने में विफल रहते हैं। करीब 90 फीसद प्रतिभागी 45 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं थीं। रपट के अनुसार 57.8 फीसद प्रतिभागियों ने कहा कि वे जानते हैं कि उनके स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है, लेकिन इसे कायम रखने में असमर्थ हैं। 46 फीसद सक्रिय स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर किया गया। अध्ययन में यह भी सामने आया कि 46 फीसद

अर्थ है कि चुनौती अब जागरूकता की नहीं, बल्कि स्वस्थ आदतों को रोजमर्रा के जीवन में शामिल करने की है। सर्वे में रोजमर्रा के समझौते जैसे व्यायाम छोड़ना, घर के काम के कारण टहलने में देरी करना, या नींद में कटौती करना स्वास्थ्य को प्राथमिकताओं की सूची में नीचे रखने के उदाहरण बताए गए हैं।

अध्ययन में लिंग विशिष्ट बाधाओं का भी खुलासा हुआ। महिलाओं में परिवार और घरेलू जिम्मेदारियों के कारण स्वास्थ्य को कम प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति अधिक पाई गई, जिससे उनकी दिनचर्या असंगत हो जाती है, जबकि पुरुषों के मामले में उच्च इच्छाशक्ति होने के बावजूद अनुशासन और पालन में कठिनाई आती है। जीवनशैली संबंधी दबाव स्वास्थ्य बनाए रखने में मुख्य बाधा बने हुए हैं। सर्वे में 28 फीसद प्रतिभागियों ने परिवार की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी।

प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस का शुभारंभ करेंगे : धामी

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून 7 अप्रैल।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबेडकर जयंती के दिन 14 अप्रैल को देहरादून में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। यह जानकारी मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है इसलिए उन्होंने उत्तराखंड के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू करवाई हैं और जिनमें से अधिकतर योजनाओं का कर्वा हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे से रोजगार, पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बड़ा बढ़ावा मिलेगा और राज्य के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में आगामी 14 अप्रैल को प्रस्तावित प्रधानमंत्री के उत्तराखंड आगमन एवं दिल्लीदेहरादून एक्सप्रेसवे के शुभारंभ कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में एक उच्चस्तरीय बैठक ली। मुख्यमंत्री ने इस अवसर को राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक चघाते हुए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस भव्य आयोजन में समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि यह कार्यक्रम जन-उत्सव का रूप ले सके।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में आगामी 14 अप्रैल को प्रस्तावित प्रधानमंत्री के उत्तराखंड आगमन एवं दिल्लीदेहरादून एक्सप्रेसवे के शुभारंभ कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में एक उच्चस्तरीय बैठक ली। मुख्यमंत्री ने इस अवसर को राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक चघाते हुए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस भव्य आयोजन में समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि यह कार्यक्रम जन-उत्सव का रूप ले सके।

**समारोह**

नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के 39वें दीक्षांत समारोह के दौरान उपराष्ट्रपिता राधाकृष्णन और वीसी प्रोफेसर उमा कांजीलाल।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूछा

बहुजन उद्यमी बड़े सरकारी ठेकों से बाहर क्यों

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में पूछे गए प्रश्न और उत्तर पर सरकार के उत्तर का हवाला देते हुए मंगलवार को सरकार से सवाल किया कि बहुजन उद्यमियों को देश के सबसे बड़े सार्वजनिक ठेकों से बाहर क्यों रखा जा रहा है।

राहुल ने बीते दो अप्रैल को लोकसभा में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित लिखित प्रश्न पूछे थे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया में यह सवाल सार्वजनिक किया। राहुल गांधी ने बताया कि संसद में सरकार से मैंने पूछा कि पिछले वर्ष 16,500 करोड़ रुपए के सार्वजनिक

कार्यों के ठेकों में से कितने ठेके दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के व्यवसायियों को मिले? उनका



फीसद खरीद एमएसएमई से होनी चाहिए, जिसमें से चार फीसद खरीद दलित और आदिवासी उद्यमियों से किया जाना निर्धारित है, लेकिन जब बात सबसे

बड़े और लाभकारी ठेकों और सार्वजनिक कार्यों की आती है, तो सरकार कहती है कि यह 'अनिवार्य' नहीं है। राहुल गांधी ने ने दावा किया कि यह केवल एक प्रशासनिक कमी नहीं है। यह मोदी सरकार की नीतियों के जरिये जानबूझकर बनाई गई बहिष्कार की व्यवस्था है जो सामाजिक और आर्थिक न्याय को कमजोर करती है। उन्होंने कहा कि सवाल सीधा है कि बहुजन उद्यमियों को देश के सबसे बड़े सार्वजनिक ठेकों से बाहर क्यों रखा जा रहा है? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री तोखन साहू ने राहुल गांधी के प्रश्न के उत्तर में पिछले पांच साल के दौरान प्रदान किए गए लोक निर्माण और अवसंरचना ठेकों की वर्ष-वार संख्या और मूल्य की सूची उपलब्ध कराई थी।

पेज 1 का बाकी

अदालत के निर्णय के बाद पहली सूची में 27 लाख नाम कटे

को मंजूरी देता है, तो उसे सूची में शामिल किया गया जाएगा। नई मतदाता सूची में कुल 60.06 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए थे, अंतिम सूची में करीब 32.68 लाख मतदाताओं के नाम सही पाए गए हैं, इन्हें राज्य की मतदाता सूची में शामिल किया गया है, जबकि 27.16 लाख अपात्र मतदाता पाए गए हैं। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, सबसे अधिक मतदाता बांग्लादेश सीमा से सटे इलाके मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना के इलाकों से हैं। मुर्शिदाबाद से सबसे अधिक 4,55,137 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इसी प्रकार उत्तर 24 परगना से 3,25,666 और

मालदा से 2,39,375 अवैध मत हटाए गए हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वी वर्धमान, दक्षिण 24 परगना, नादिया और मालदा से दो लाख से अधिक अवैध मतदाता हटाए गए हैं, जिन जिलों में एक लाख से अधिक मतदाताओं को हटाया गया है, उन जिलों में कुच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, हावड़ा और हुगली जैसे प्रमुख इलाके शामिल हैं।

निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक सबसे कम अवैध मतदाता झारखाम में हटाए गए हैं। यहां अवैध मतदाताओं की संख्या 1240 पाई गई है। इसी प्रकार कोलकाता दक्षिण में 28468 और कोलकाता उत्तर में 39164 मतदाताओं को हटाया गया है। राज्य में दो चरणों में कुल 294 सीटों के लिए मतदान कराया जाना है। कुल मिलाकर चुनाव आयोग द्वारा 28 फरवरी को जारी की गई अंतिम सूची के बाद अब 7.04 करोड़ मतदाता हैं। सूची से 60 लाख नाम इसलिए हटाए गए थे, क्योंकि या तो ये लोग मर चुके हैं और या अब पश्चिम बंगाल में नहीं रहते। अंतिम सूची से नाम हटाए जाने के बाद मतदाताओं के पास उच्चतम न्यायालय के आदेशों के तहत राज्य में विशेष रूप से गठित न्यायाधिकरणों में जाने का विकल्प है,

लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि न्यायाधिकरण के न्यायाधीशों द्वारा योग्य पाए गए मतदाता आगामी चुनावों में अपने मतदाताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं। आखिरी पूरक सूची जारी होने के साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदाता सूची सोमवार आधी रात के बाद नियमों के अनुसार अंतिम रूप दे दी गई है।

पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा की 152 सीटों पर 23 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा, जबकि शेष 142 सीटों पर 29 अप्रैल को दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के लिए मतदाता सूची को नौ अप्रैल को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस चरण में मतदाता सूची में कोई और नाम शामिल नहीं किया जाएगा। पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि के बाद सूची कानून के अनुसार आखिरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब किसी भी बदलाव का फैसला उच्चतम न्यायालय के संभावित निर्देशों पर निर्भर करेगा। एसआइआर मामले

पर उच्चतम न्यायालय अगली सुनवाई 13 अप्रैल को करेगा। शुद्धीकरण में 90 लाख से अधिक मतदाता हटे निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की सूची का शुद्धीकरण तीन चरणों में किया है।

इसके बाद 90, 83,345 लाख मतदाता सूची से हटाए गए हैं। दिसंबर 2025 में जब प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, तो उस समय आयोग ने 58.2 लाख और फरवरी 2026 में अंतिम सूची प्रकाशन तक 5.46 लाख मतदाता हटाए गए थे। वर्तमान में न्यायिक अधिकारियों के हस्तक्षेप और विस्तृत जांच के बाद 27 लाख से अधिक नामों को हटाने का फैसला लिया है। इन दोनों आंकड़ों के बाद सूची से हटाए गए नामों का आंकड़ा 90.83 लाख से अधिक मतदाताओं की संख्या को पार कर गया है।

आज एक संपूर्ण सभ्यता का अंत हो जाएगा

गई है। ईरानी अधिकारियों ने युवाओं से बिजली संयंत्रों की सुरक्षा के लिए मानव श्रृंखला बनाने की अपील की है। मौजान समाचार एजेंसी के अनुसार तेहरान में हुए हमले में 24 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि, तुरंत यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हमले में किस निशाना बनाया गया था।

पिछले कुछ समय से ईरान की राजधानी तेहरान पर लगातार तीव्र हवाई हमले हो रहे हैं, जिनमें पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित संभावित हथियार भंडार और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। इजराइल ने धर्मतंत्र और उसकी सेना में शीर्ष अधिकारियों को निशाना बनाने हुए हवाई हमले किए

हैं। घरेलू दबाव के बीच ट्रंप ने ईरान से जलमार्ग खोलने की मांग दोहराई है, अन्यथा बिजली संयंत्रों और पुलों को नष्ट करने की चेतावनी दी है। नागरिक ढांचे पर हमले की धमकी ने संभावित युद्ध अपराधों की चिंता बढ़ा दी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने ट्रंप से ऐसा कदम न उठाने की अपील करते हुए कहा कि ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि यह संघर्ष और न बढ़े। पुलों व नागरिक ढांचे पर बमबारी जैसे कदम अस्वीकार्य होंगे। ईरान ने इसके जवाब में युवाओं, खिलाड़ियों, कलाकारों व विद्यार्थियों से बिजली संयंत्रों के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाने का आह्वान किया।

असम पुलिस पवन खेड़ा के आवास पहुंची

को संवाददाता सम्मेलन कर आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिनीकी भुइयां शर्मा के पास तीन पासपोर्ट और विदेश में संपत्ति है, जिसे मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में घोषित नहीं किया गया है। सूत्रों ने बताया कि एक दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी पूर्वाह्न करीब 11 बजे मध्य दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित खेड़ा के आवास पर पहुंचे और लगभग दो घंटे बाद वहां से चले गए।

कांग्रेस ने शर्मा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह नौ अप्रैल के चुनावों में हार के कारण परेशान और विचलित हैं और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस खेड़ा को पाताल से भी दूढ़ निकालेगी और उनसे इन फर्जी दस्तावेजों के बारे में पूछताछ करेगी, जिनका इस्तेमाल उनके परिवार को निशाना बनाने के लिए किया था। आवास की तलाशी

ली गई और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। नाथ ने कहा कि कुछ दोष साबित करने वाली सामग्री मिली है, लेकिन जांच के इस स्तर पर इसकी विस्तृत जानकारी साझा नहीं की जा सकती। डीसीपी ने बताया कि गुवाहाटी की अपराध शाखा पुलिस स्थान ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की है।

शर्मा ने खेड़ा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। कांग्रेस प्रवक्ता खेड़ा ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन कर आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिनीकी भुइयां शर्मा के पास तीन पासपोर्ट और विदेश में संपत्ति है, जिसे मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में घोषित नहीं किया गया है। सूत्रों ने बताया कि एक दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी पूर्वाह्न करीब 11 बजे मध्य दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित खेड़ा के आवास पर पहुंचे और लगभग दो घंटे बाद वहां से चले गए।

दो बच्चों की मौत; सीआरपीएफ की चौकी पर धावा बोलने की कोशिश, दो लोग मारे गए

अपने घर छोड़ दिए क्योंकि जिस जगह हमला हुआ था, उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर एक जिंदा राकेट-प्रोपेलर्ड ग्रेनेड (आरपीजी) का खोल बरामद हुआ था। जैसे ही बच्चों की मौत की खबर फैली बिष्णुपुर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने ट्रॉंगलाओबी से लगभग 500 मीटर पूर्व में स्थित एक सीआरपीएफ चौकी पर धावा बोलने की कोशिश की, और इस बात पर अपना गुस्सा जाहिर किया कि वे ऐसे हमले को रोकने में असमर्थ रहे। कई लोग सड़कों पर उतर आए और टायर जलाकर नाकेबंदी कर दी।

भौड़ ने तीन टुकड़ों की भी आग के हवाले कर दिया, जिनमें दो तेल के टैंकर भी शामिल थे। अधिकारियों के अनुसार सीआरपीएफ जवानों को चौकी पर धावा बोलने की कोशिश कर रहे लोगों पर गोली चलानी पड़ी। गृह मंत्री गोविंददास चौधरी ने पुष्टि की कि सीआरपीएफ चौकी पर धावा बोलने की कोशिश के दौरान दो नागरिकों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य को गोली लगी है और उनका

इलाज चल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मोडरग पुलिस स्टेशन के गेट पर जलते हुए लठ्ठे जमा करके उसे भी बंद कर दिया। इंफाल में भी विरोध प्रदर्शन उभर हो गया, जहां कई लोगों ने सड़कों को बंद कर दिया, टायर जलाए और यातायात को बाधित किया। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। ओडिसम बिनित्ता गंभीर रूप से घायल हो गई।

फिलहाल उनका इलाज पास के एक अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बाद दिन में ट्रॉंगलाओबी के कुछ निवासियों ने अपने घर छोड़ दिए क्योंकि जिस जगह हमला हुआ था, उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर एक जिंदा राकेट-प्रोपेलर्ड ग्रेनेड (आरपीजी) का खोल बरामद हुआ था। जैसे ही बच्चों की मौत की खबर फैली बिष्णुपुर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने ट्रॉंगलाओबी से लगभग 500 मीटर पूर्व में स्थित एक सीआरपीएफ चौकी पर धावा बोलने की कोशिश की, और इस बात पर अपना गुस्सा जाहिर किया कि वे ऐसे हमले को रोकने में असमर्थ रहे।

एनएसए डोभाल ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री से द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के उपायों पर चर्चा की

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (भाषा)।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने मंगलवार को बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान की रात्रिभोज पर मेजबानी की। रहमान तीन दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचे, जिसका उद्देश्य 18 महीने से अधिक समय से चले आ रहे कूटनीतिक तनाव के बाद द्विपक्षीय संबंधों में सुधार लाना है।

रहमान बांग्लादेश में प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सरकार के फरवरी में सत्ता संभालने के बाद भारत की यात्रा और अपने वाले देश के पहले वरिष्ठ मंत्री हैं। घटनाक्रम से वाकिफ

अधिकारियों के मुताबिक, डोभाल और रहमान ने भारत-बांग्लादेश संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, जिसमें संबंधों को नई गति देने पर विशेष जोर रहा। हालांकि, इस बैठक को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। रहमान के प्रतिनिधिमंडल में प्रधानमंत्री के विदेश सलाहकार हुमायूं कबीर भी शामिल हैं। रहमान बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ विस्तृत वार्ता करेंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम मंत्री हरीद्वीप सिंह पुरी से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर कहा कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान का स्वागत किया गया।

जम्मू-कश्मीर में लश्कर के आतंकी तंत्र का भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के एक अंतरराज्यीय आतंकवादी तंत्र का भंडाफोड़ करते हुए पिछले 16 साल से फरार अब्दुल्ला उर्फ अबू हुरैरा समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार अब्दुल्ला के अलावा एक अन्य पाकिस्तानी आतंकी उस्मान उर्फ खुबैब को भी इस बड़े अभियान में गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय में स्थित एक सफेदपोश आतंकी तंत्र का भंडाफोड़ करने के छह महीने बाद हुई है जिसके तार कश्मीर, हरियाणा

यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय में स्थित एक सफेदपोश आतंकी तंत्र का भंडाफोड़ करने के छह महीने बाद हुई है।

और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि गत कुछ दिनों में जांचकर्ताओं ने जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और हरियाणा सहित 19 स्थानों पर छापेमारी की और चार एके असाएल राइफलों सहित बड़ी मात्रा में हथियार और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। उन्होंने बताया कि केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर की गई जांच के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को साजो-सामान और वित्तीय सहायता करने वाले एक विशाल नेटवर्क का पर्दाफास हुआ।

पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित हो रहा कारोबार, सरकार का एलान

छोटे उद्यमियों के लिए 2.5 लाख करोड़ की ऋण गारंटी योजना पर विचार

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (भाषा)।

सरकार पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित कारोबारों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यमों (एमएसएमई) को राहत देने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना लाने पर विचार कर रही है।

सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस योजना के तहत अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण उधारकर्ताओं द्वारा ऋण चुकाने में चूक होने की स्थिति में उधारदाताओं को 100 करोड़ रुपए तक के ऋणों पर करीब 90 फीसद की ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी। बैंक ऋण पर यह गारंटी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) देगी जो सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है। इस योजना के लिए सरकार को करीब 17,000 करोड़ से 18,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करना होगा।

इस योजना के तहत अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण उधारकर्ताओं द्वारा ऋण चुकाने में चूक होने की स्थिति में उधारदाताओं को 100 करोड़ रुपए तक के ऋणों पर करीब 90 फीसद की ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी।

सूत्रों ने बताया कि ऐसी ही योजना कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान भी लागू की गई थी, जो काफी सफल रही और विभिन्न क्षेत्रों के कई कारोबारों को काम जारी रखने एवं बकाया चुकाने में मदद मिली।

सरकार ने मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आपात ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) शुरू की थी। इसका उद्देश्य कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न व्यवधान के बीच पात्र एमएसएमई और अन्य कारोबारी इकाइयों को परिचालन देनदारियाँ पूरी करने और

सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बीवी नागरत्ना ने कहा किसी महिला को तीन दिन अछूत नहीं माना जा सकता

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बीवी नागरत्ना ने मंगलवार को कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी महिला को महीने में तीन दिन अछूत माना जाए और फिर चौथे दिन अछूत मानना बंद कर दिया जाए।

यह टिप्पणी तब आई जब नौ न्यायाधीशों की एक पीठ केरल के सबरीमला मंदिर सहित धार्मिक स्थलों पर महिलाओं से भेदभाव और विभिन्न धर्मों द्वारा पालन की जाने वाली धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे और सीमा से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इस संविधान पीठ में प्रधान न्यायाधीश सुर्यकांत, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, न्यायमूर्ति आगस्टिन जांच



सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भारत उतना पितृसत्तात्मक या लैंगिक रूढ़िवादिता वाला देश नहीं है जितना पश्चिम समझता है।

मसीह, न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले, न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति जायमाल्य बागवी शामिल हैं। सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें 2018 के सबरीमला फैसले में की गई उस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति है, जिसमें कहा गया है कि 10-50 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को मंदिर में

प्रवेश से रोकना अस्पृश्यता का एक रूप है, जो संविधान के अनुच्छेद 17 का उल्लंघन करता है।

सबरीमला मामले में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ का मत था कि उम्र या मासिक धर्म की स्थिति के आधार पर महिलाओं को केरल के सबरीमला मंदिर में प्रवेश से रोकना अस्पृश्यता का एक रूप है जो उन्हें अधीनस्थ स्थिति में रखता है, पितृसत्ता को कायम रखता है और उनकी गरिमा के लिए अपमानजनक है। मेहता ने कहा कि भारत उतना पितृसत्तात्मक या लैंगिक रूढ़िवादिता वाला देश नहीं है जितना पश्चिम समझता है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने तब कहा कि सबरीमला के संदर्भ में अनुच्छेद 17 पर बहस कैसे की जा सकती है, यह मुझे समझ नहीं आता। एक महिला होने के नाते, मैं कह सकती हूँ कि हर महीने तीन दिन अस्पृश्यता नहीं हो सकती और चौथे दिन कोई अस्पृश्यता नहीं होती।

रुपया 16 पैसे टूटकर 93.06 प्रति डालर पर पहुंचा

मुंबई, 7 अप्रैल (भाषा)।

रुपया मंगलवार को 16 पैसे टूटकर अमेरिकी डालर के मुकाबले 93.06 पर बंद हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होर्मुज्ज जलमार्ग को खोलने की समयसीमा और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले निवेशकों में चिंता बनी रही, जिससे घरेलू मुद्रा पर दबाव देखा गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, अस्थिर वैश्विक हालात के बीच विदेशी पूंजी की लगातार निकासी, मजबूत डालर और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण रुपया डालर के मुकाबले दबाव में बना हुआ है।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डालर के मुकाबले 93.05 पर खुला। इसके बाद इसमें गिरावट आई और यह 93.12 प्रति डालर तक नीचे चला गया। कारोबार के दौरान रुपया 92.86 प्रति डालर के उच्च स्तर तक भी गया। कारोबार के अंत में रुपया 93.06 प्रति डालर पर रहा, जो पिछले बंद भाव से 16 पैसे की गिरावट है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सट्टेबाजी पर रोक लगाने और मुद्रा में उतार-चढ़ाव कम

करने के लिए उठाए गए कदमों के बाद, सोमवार को रुपया अमेरिकी डालर के मुकाबले 28 पैसे मजबूत होकर 92.90 पर बंद हुआ था।

आरबीआइ ने सट्टेबाजी पर नियंत्रण के लिए नियम सख्त किए हैं और बैंकों की नेट ओपन पोजिशन (बैंकों के पास शुद्ध रूप से रखी जाने वाली विदेशी मुद्रा) की सीमा 10 करोड़ डालर तय की है। भारतीय रिजर्व बैंक की व्याज दर तय करने वाली समिति ने सोमवार से चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति पर तीन दिन की बैठक शुरू कर दी है। आरबीआइ के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का निर्णय बुधवार को घोषित किया जाएगा। इस बीच, दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डालर की स्थिति को दर्शाने वाला डालर सूचकांक 0.15 फीसद घटकर 99.83 पर आ गया। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 1.97 फीसद की गिरावट के साथ 107.61 डालर प्रति बैरल रहा। घरेलू शेयर बाजार की बात करें तो सूचकांक 509.73 अंक चढ़कर 74,616.58 अंक पर रहा, जबकि निफ्टी 155.40 अंक बढ़कर 23,123.65 अंक पर पहुंच गया।

‘बैंक खातों को धोखाधड़ी घोषित करने से पूर्व उधारकर्ता निजी सुनवाई के हकदार नहीं’

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (भाषा)।

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि बैंकों द्वारा खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले उधारकर्ता व्यक्तिगत सुनवाई का अनिवार्य रूप से अवसर दिए जाने के हकदार नहीं हैं। न्यायमूर्ति जेबी पाटील और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले को निरस्त कर दिया, जिसमें उधारकर्ता को धोखाधड़ी वाला खाता घोषित करने से पहले व्यक्तिगत सुनवाई देने का बैंक को निर्देश दिया गया था।

शीर्ष अदालत ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन से जुड़े नियमों की व्याख्या करते हुए कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कारण

बताओ नोटिस देना, जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराना, उधारकर्ता के जवाब पर विचार करना और कारण के साथ आदेश पारित करना पर्याप्त है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि बैंक किसी खाते को धोखाधड़ी घोषित करने में ऑडिट रपट (फॉरेंसिक ऑडिट समेत) पर निर्भर करते हैं, तो उसकी प्रति उधारकर्ता को देनी होगी ताकि वह उस पर अपनी आपत्ति या जवाब दे सके।

इसके साथ ही पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में निर्णय मुख्य रूप से दस्तावेजी साक्ष्यों- जैसे वित्तीय रिकार्ड, लेन-देन विवरण और ऑडिट रपट पर आधारित होता है इसलिए हर मामले में मौखिक सुनवाई जरूरी नहीं होती। पीठ ने कहा कि हर मामले में व्यक्तिगत सुनवाई अनिवार्य करने से प्रक्रिया में देरी होगी और धोखाधड़ी वाले खातों की समय पर पहचान और जांच प्रभावित हो सकती है।



उद्घाटन

ठाणे: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार और अन्य मंगलवार को ठाणे-बोरिवली दिवन टनल परियोजना के उद्घाटन के दौरान।

एअर इंडिया उड़ानों पर ईंधन अधिभार लगाएगा

मुंबई, 7 अप्रैल (भाषा)।

एअर इंडिया समूह घरेलू उड़ानों के लिए 299 रुपए से 899 रुपए तक और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 24 डालर से 280 डालर तक का ईंधन अधिभार लगाने जा रहा है।

हालांकि, कुछ मार्गों पर ईंधन अधिभार नहीं लगाया जाएगा। एअर इंडिया ने मंगलवार को बयान में कहा कि आठ अप्रैल से प्रभावी संशोधित ईंधन अधिभार एअरलाइन की किफायती सेवाएं देने वाली अनुषंगी कंपनी एअर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित उड़ानों पर भी लागू होगा।

बयान में कहा गया कि बांग्लादेश और जापान, हांगकांग और दक्षिण कोरिया जैसे सुदूर पूर्व गंतव्यों के लिए आने-जाने वाली उड़ानों पर ईंधन अधिभार में संशोधन की जानकारी

एअर इंडिया के सीईओ कैप्टेन विल्सन का इस्तीफा, उत्तराधिकारी की तलाश

एअर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक कैप्टेन विल्सन ने इस्तीफा दे दिया है। एअरलाइन ने उनके उत्तराधिकारी की तलाश के लिए एक समिति का गठन किया है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। न्यूजीलैंड मूल के विल्सन पिछले चार वर्ष से टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। एअरलाइन ने बयान में कहा कि विल्सन ने 2024 में ही एअर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को 2026 में पद छोड़ने की अपनी इच्छा से अगगत करा दिया था। तब से वह यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि संगठन और नेतृत्व दल बदलाव के लिए स्थिर स्थिति में हो। एअर इंडिया के निदेशक मंडल ने आज वाले महीनों में नए प्रमुख की नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन किया है, जो उनके उत्तराधिकारी की तलाश करेगी।

आवश्यक नियामकीय अनुमोदनों के अधीन उचित समय पर दी जाएगी।

एअरलाइन ने कहा कि सरकार द्वारा घरेलू विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में 25 फीसद

की अधिकतम वृद्धि तय करने के बाद समूह ने इस संतुलित दृष्टिकोण को अपनाया है और घरेलू स्तर पर एक समान अधिभार की जगह दूरी-आधारित अधिभार लगाने का फैसला लिया है।

न्यायिक कार्यों में कृत्रिम मेधा के इस्तेमाल पर लगाई रोक

चंडीगढ़, 7 अप्रैल (ब्यूरो)।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को फैसला लिखने और कानूनी शोध के लिए कृत्रिम मेधा (एआइ) उपकरणों का उपयोग न करने का निर्देश दिया है।

न्यायालय के महापंजीयक की ओर से सोमवार को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को जारी किए गए पत्र के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें अपने अधीन कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को यह निर्देश देने को कहा है कि वे फैसला लिखने

और कानूनी शोध के लिए चैटजीपीटी, जेमिनी, कोपायलट, मेटा सहित किसी भी एआइ उपकरण का उपयोग न करें। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इन निर्देशों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा। इससे पहले, गुजरात हाई कोर्ट ने किसी भी प्रकार के निर्णय लेने, न्यायिक तर्क, आदेश का प्रारूप तैयार करने, जमानत संबंधी सजा पर विचार करने या किसी भी महत्वपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया में एआइ जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को जारी किए गए पत्र के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें अपने अधीन कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को यह निर्देश देने को कहा है कि वे फैसला लिखने के उपयोग पर रोक लगा दी थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह कदम न्यायिक प्रक्रिया की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला।

ग्रामीण भारत में शीर्ष पांच फीसद परिवार 32 फीसद जमीन के मालिक

अध्ययन

जबकि शीर्ष एक फीसद परिवारों के पास 18 फीसद कृषि भूमि है

ग्रामीण भारत में 10 फीसद परिवारों के पास 44 फीसद जमीन

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (भाषा)।

देश के ग्रामीण इलाकों में शीर्ष 10 फीसद परिवारों के पास 44 फीसद जमीन है, जबकि 46 फीसद भूमिहीन हैं। ह्यूवर्ल्ड इनटैल्लिजेंटी लैब्स के एक अध्ययन में यह बात कही गई है। भारत में भूमि असमानता: प्रकृति, इतिहास एवं बाजार शीर्षक वाले इस कार्य-पत्र में कहा गया है कि ग्रामीण भारत में शीर्ष पांच फीसद परिवार 32 फीसद जमीन के मालिक हैं, जबकि शीर्ष एक फीसद परिवारों के पास 18 फीसद कृषि भूमि है।

यह अध्ययन नितिन कुमार भारती, डेविड ब्लेकस्ली और समरीन मलिक ने संयुक्त रूप से किया है। अध्ययन में करीब 65 करोड़ लोगों और 2.7 लाख गांवों के भूमि आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

रपट के मुताबिक, ग्रामीण स्तर पर भूमि असमानता का औसत गिनी सूचकांक (0 से 100 के पैमाने पर) भूमिहीन



परिवारों को शामिल करने पर 71 तक पहुंच जाता है जबकि 46 फीसद ग्रामीण परिवार पूरी तरह भूमिहीन हैं। अध्ययन रपट कहती है कि औसतन किसी गांव में सबसे बड़ा जमींदार लगभग 12 फीसद जमीन नियंत्रित करता है,

यह अध्ययन नितिन कुमार भारती, डेविड ब्लेकस्ली और समरीन मलिक ने संयुक्त रूप से किया है। अध्ययन में करीब 65 करोड़ लोगों और 2.7 लाख गांवों के भूमि आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। रपट के मुताबिक, ग्रामीण स्तर पर भूमि असमानता का औसत गिनी सूचकांक (0 से 100 के पैमाने पर) भूमिहीन परिवारों को शामिल करने पर 71 तक पहुंच जाता है जबकि 46 फीसद ग्रामीण परिवार पूरी तरह भूमिहीन हैं। अध्ययन रपट कहती है कि औसतन किसी गांव में सबसे बड़ा जमींदार लगभग 12 फीसद जमीन नियंत्रित करता है, जबकि कुछ गांवों में एक ही व्यक्ति के पास आधे से अधिक कृषि भूमि है।

जबकि कुछ गांवों में एक ही व्यक्ति के पास आधे से अधिक कृषि भूमि है। राज्यों के बीच असमानता के स्तर में भी बड़ा अंतर देखा गया है, जो वैश्विक स्तर पर देशों के बीच पाए जाने वाले अंतर के लगभग बराबर है। अध्ययन

के अनुसार, जिन क्षेत्रों में कृषि के लिए अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियाँ हैं, वहां भूमि का केंद्रीकरण अधिक देखने को मिलता है। ऐतिहासिक कारकों का भूमि वितरण पर गहरा असर बना हुआ है। ब्रिटिश शासन के सीधे नियंत्रण वाले क्षेत्रों में भूमि असमानता अपेक्षाकृत अधिक पाई गई, जबकि रियासतों के अधीन रहे इलाकों में भूमि असमानता कम रही है। इसके अलावा भूमि स्वामित्व पर सामाजिक संरचना का प्रभाव भी स्पष्ट है।

अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) की अधिक आवादी वाले गांवों में भूमिहीनता की दर ज्यादा है। हालांकि, लंबे समय तक वामपंथी शासन के अधीन रहे केरल एवं पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में यह प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम दिखती है।

अध्ययन रपट के मुताबिक, बाजार और बुनियादी ढांचे तक बेहतर पहुंच भी ऐतिहासिक रूप से बनी इस असमानता को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाई है।

खबर कोना



दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के पोपर में मंगलवार को एक किसान खराब हुई केसर की फसल को दिखाता हुआ।

शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी, सूचकांक 510 अंक चढ़ा

मुंबई, 7 अप्रैल (भाषा)।

स्थानीय शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में तेजी जारी रही और बीएसई सूचकांक 510 अंक चढ़ गया, जबकि एनएसई निफ्टी 23,000 अंक के पार पहुंच गया। कच्चे तेल के दाम में नरमी और दुनिया के अन्य बाजारों में तेजी से निवेशकों की धारणा मजबूत हुई। इसके अलावा, आइटी शेयरों में लिवाली से शुरुआती गिरावट के बाद बाजार में सुधार हुआ। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सूचकांक 509.73 अंक यानी 0.69 फीसद बढ़कर 74,616.58 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, यह ऊंचे में 74,686.32 अंक तक गया और नीचे में 73,282.41 अंक तक आया। इससे बाजार में 1,403.91 अंक का उतार-चढ़ाव आया। पचास शेयरों पर आधारित एनएसई निफ्टी 155.40 अंक यानी 0.68 फीसद चढ़कर 23,123.65 अंक पर बंद हुआ।

जमा वृद्धि के मामले में निजी क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन सार्वजनिक बैंकों से बेहतर

मुंबई, 7 अप्रैल (भाषा)।

निजी क्षेत्र के बैंकों ने जमा वृद्धि के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पीछे छोड़ते हुए मजबूत वृद्धि दर्ज की है। हालांकि, कुल मिलाकर बैंकों को जमा जुटाने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बैंकों के अस्थायी आंकड़ों को समग्र रूप से देखने पर पता चलता है कि वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में निजी बैंकों ने जमा में 12 से 17 फीसद की वृद्धि दर्ज की, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यह वृद्धि दो से 14 प्रतिशत रही। संकलित आंकड़ों के मुताबिक, कम लालत वाली जमाओं पर लगातार दबाव के कारण, बैंक हाल की तिमाहियों में जमा प्रमाणपत्र के माध्यम से कोष जुटाने पर अधिक निर्भर रहे हैं। जमा जुटाना विशेष रूप से चालू खाता एवं बचत खाता (सीएएसए) के मामले में चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

चीन ने 15 दिन में दूसरी बार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए गए

बेजिंग, 7 अप्रैल (भाषा)।

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में तेजी के बीच चीन ने करीब 15 में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। चीन की शीर्ष आर्थिक योजना संस्था राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग (एनडीआरसी) ने मंगलवार को कहा कि कीमतों में यह नई वृद्धि बुधवार से लागू होगी। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध को लेकर संभावित ईंधन संकट की आशंकाओं के बीच चीन ने इससे पहले 23 मार्च को भी पेट्रोल तथा डीजल की कीमतें बढ़ाई थीं। एनडीआरसी ने बयान में कहा कि मार्च के अंत में घरेलू तेल कीमतों में किए गए समायोजन के बाद अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया है।

रेल परिचालन क्षमता का विस्तार कर रहा उत्तर पश्चिम रेलवे

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (ब्यूरो)।

उत्तर पश्चिम रेलवे अपने ट्रैनों के रखरखाव अवसरचना को मजबूत करके अपनी रेल परिचालन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ट्रैनों के रखरखाव के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 22 रेल पिट लाइनें हैं। साथ ही अपने विभिन्न स्थानों पर रेल रखरखाव के लिए 20 नई रेल पिट लाइनों के निर्माण का कार्य शुरू किया है। इसमें मदार (एक लाइन), उमरा (दो लाइन), लालगढ़ (चार लाइन), श्रीगंगागंजर (दो लाइन), हिसार (दो लाइन), सूतगढ़ (दो लाइन), खातीपुरा (चार लाइन), बाड़मेर (एक लाइन) और जैसलमेर (दो लाइन) शामिल हैं। इस विस्तार से मौजूदा रखरखाव क्षमता लगभग दोगुनी होने की उम्मीद है।

This is only an advertisement for information purpose and not an offer document announcement. Not for publication, distribution or release directly or indirectly into the United States or otherwise outside India. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated March 24, 2026 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with stock exchange BSE Limited ("BSE") ("the "Stock Exchange"), and the Securities and the Exchange Board of India ("SEBI") for information and dissemination on the SEBI's website pursuant to Regulation 3 of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR Regulations").



GUJARAT COTEX LIMITED

(CIN: L46695DN1996PLC000116)

Registered Office: Shop No. 3, Shanti Complex, Opp. Patel Petrol Pump, Amli, Silvassa, Dadra & Nagar Haveli, India – 396230. Corporate Office: 2007, Shankar Plaza Nanpura, Timaliyawad, Surat, Gujarat, India – 395001. Email: info@gujcotex.co | Website: www.gujcotex.co | Phone: +91-0261 3100550;

Our Company was originally incorporated as "Gujarat Cotex Limited" under the provisions of the Companies Act, 1956, and received its Certificate of Incorporation from the Registrar of Companies, Gujarat, on August 24, 1992, commencing business on August 25, 1992. Pursuant to a Scheme of Amalgamation approved by the Hon'ble High Court of Gujarat on February 23, 1993, the Company took over the undertaking of Jayant Texturising Private Limited as a going concern, engaged in the yarn texturing business. Subsequently, the Company's Registered Office was relocated from State of Gujarat, located at Morbi Memon Jamatkhana Building, Tankshal Pole, Ranitalav, Surat – 395003, Gujarat, India to the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, located at 52, Government Industrial Estate, Phase-II, Piparia, Silvassa, Dadra and Nagar Haveli, India, as approved by an order of the Company Law Board and a fresh certificate was issued effective November 20, 1996. Thereafter, the name of the Company was changed from "Gujarat Cotex Limited" to "Octagon Industries Limited" pursuant to a fresh Certificate of Incorporation issued on May 26, 1997. Further, the Registered Office of the Company was shifted to Cassia-702, Garden City, Opposite Samarvani Panchayat, Khanvel Road, Silvassa, Dadra & Nagar Haveli – 396230, with effect from October 5, 2011. Subsequently, with effect from June 4, 2021, the Registered Office was relocated to Shop No. 4, 1st Floor, Shanti Complex, Opp. Patel Petrol Pump, Amli, Silvassa, Dadra & Nagar Haveli, India – 396230. Later, with effect from August 29, 2025, the Registered Office was shifted from Shop No. 4, 1st Floor, Shanti Complex, Opp. Patel Petrol Pump, Amli, Silvassa, Dadra & Nagar Haveli, India – 396230 to Shop No. 3, Shanti Complex, Opp. Patel Petrol Pump, Amli, Silvassa, Dadra & Nagar Haveli, India – 396230. Further, the name of the Company was reverted to its original name "Gujarat Cotex Limited" pursuant to a fresh Certificate of Incorporation issued on December 27, 2006. Please see "Summary of the Letter of Offer" on page 19 of the Letter of Offer.

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF GUJARAT COTEX LIMITED ("OUR COMPANY"/"THE ISSUER")

RIGHTS ISSUE OF UP TO 8,54,64,000 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5/- EACH OF OUR COMPANY ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 5/- (RUPEES FIVE ONLY) EACH PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO AN AMOUNT OF ₹ 4,273.20 LAKHS* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 6 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 FULLY PAID UP EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON APRIL 01, 2026 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS ONE TIME THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED 'TERMS OF THE ISSUE' ON PAGE 87 OF THE LETTER OF OFFER (LOF). (*Assuming full subscription)

NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

ISSUE PROGRAMME

ISSUE OPENS ON	LAST DATE FOR ON-MARKET RENUNCIATIONS**	ISSUE CLOSES ON#
April 10, 2026	May 05, 2026	May 08, 2026

**Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the Demat account of the Renouncee(s) on or prior to the Issue Closing Date.

#Our board will have the right to extend the Issue period as it may determine from time to time but not exceeding 30 (Thirty) days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). Further, no withdrawal of the Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.

ASBA*

Simple, Safe, Smart way of Application -
Make use of it!!!!

*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For further details, check section on ASBA below.

Facilities for Application in this Issue

In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, the SEBI Rights Issue Circulars and the ASBA Circulars, all investors desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details, see "Procedure for Application through the ASBA Process" on page 91 of the Letter of Offer, respectively.

APPLICATION THROUGH ASBA FACILITY

An investor, wishing to participate in this Issue through the ASBA facility, is required to have an ASBA enabled bank account with an SCSB, prior to making the Application. Investors desiring to make an Application in this Issue through ASBA process, may submit the Application Form to the Designated Branch of the SCSB or online/electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorizing such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts.

Please note that subject to SCSBs complying with the requirements of SEBI Circular CIR/CFD/DIL/13/2012 dated September 25, 2012, within the periods stipulated therein, ASBA Applications may be submitted at the Designated Branches of the SCSBs. Further, in terms of the SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/DIL/1/2013 dated January 2, 2013, it is clarified that for making Applications by SCSBs on their own account using ASBA facility, each such SCSB should have a separate account in its own name with any other SEBI registered SCSB/s. Such account shall be used solely for the purpose of making an application for the Issue and clear demarcated funds should be available in such account for such an application. SCSBs shall have a separate account in its own name with any other SEBI registered SCSBs. Such account shall be used solely for the purpose of making an application in the Issue and clear demarcated funds should be available in such account for such an application. SCSBs applying through ASBA shall submit their Applications to the Registrar.

CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN DEMAT ACCOUNTS OF ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS

pursuant to provisions of the SEBI ICDR Regulations and the SEBI Issue Circular, the Rights Entitlements shall be credited in dematerialized form in respective demat accounts of the Eligible Equity Shareholders before the Issue Opening Date. In case of demat accounts which are frozen or details of which are unavailable or the demat accounts the details of which could not be traced from the details provided by the Eligible Equity Shareholders, the Rights Entitlements shall be kept in suspense escrow demat account and shall be transferred to the demat account of the Eligible Equity Shareholder as and when such details are provided/rectified.

Prior to the Issue Opening Date, our Company shall credit the Rights Entitlements to (i) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders holding the Equity Shares in dematerialised form; and (ii) a demat suspense escrow account opened by our Company, for the Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in dematerialized form at least one day before the Issue Closing Date, to enable such Eligible Equity Shareholders to make an application in this Issue, and where the time to credit the Rights Entitlements or unblock the funds in the ASBA account expires post the Issue Closing Date, to enable such Eligible Equity Shareholders to make an application in this Issue. Eligible Equity Shareholders can obtain the details of their respective Rights Entitlements from the website of the Registrar (i.e., www.purvashare.com) by entering their DP ID and Client ID or Folio Number (in case of Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form) and PAN. The Registrar to the Issue will send/dispatch a serialised intimation letter, along with the Application Form, to any Eligible Equity Shareholder who has submitted a valid e-mail address, containing the link to download the Application Form. Such Eligible Equity Shareholders can make an Application only after downloading and printing the Application Form from the aforementioned link.

Prior to the Issue Opening Date, the Rights Entitlements of those Eligible Equity Shareholders, among others, who hold Equity Shares in physical form, and whose demat account details are not available with our Company or the Registrar, shall be credited in a demat suspense escrow account opened by our Company.

PROCEDURE FOR APPLICATION - In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, SEBI Rights Issue Circulars and ASBA Circulars, all investors desiring to make an application in this issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through ASBA. For details of procedure for application by the resident eligible shareholders holding equity shares in physical form as on record date, please see "Making of an application by eligible equity shareholders holding equity shares in physical form" on page 95 of the Letter of Offer.

Procedure for Application through the ASBA process: Investors desiring to make an Application in this Issue through ASBA process, may submit the Application Form to the Designated Branch of the SCSB or online/electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorizing such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts. Investors should ensure that they have correctly submitted the Application Form, or have otherwise provided an authorisation to the SCSB, via the electronic mode, for blocking funds in the ASBA Account equivalent to the Application Money mentioned in the Application Form, as the case may be, at the time of submission of the Application. For the list of banks which have been notified by SEBI to act as SCSBs for the ASBA process, please refer to <https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognise=yes&intMid=34>. For details on Designated Branches of SCSBs collecting the Application Form, please refer the above-mentioned link.

Application by eligible equity shareholders holding equity shares in physical form

Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two Working Days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date.

PLEASE NOTE THAT THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS WHO HOLD EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM AS ON RECORD DATE AND WHO HAVE NOT FURNISHED THE DETAILS OF THEIR RESPECTIVE DEMAT ACCOUNTS TO THE REGISTRAR OR OUR COMPANY PRIOR TO THE ISSUE CLOSING DATE SHALL NOT BE ELIGIBLE TO MAKE AN APPLICATION FOR RIGHTS EQUITY SHARES AGAINST THEIR RIGHTS ENTITLEMENTS WITH RESPECT TO THE EQUITY SHARES HELD IN PHYSICAL FORM.

Allotment of Rights Equity Shares in Dematerialised Form: Please note that the Rights Equity Shares applied for in this Issue can be allotted only in dematerialised form and to the same demat account in which the equity shares are held by such investors on the Record Date.

Dispatch of the Letter of Offer (LOF) and Application: The dispatch of the LOF and the Application Form was completed on April 07, 2026, by the Registrar for the Issue.

Credit of Rights Entitlements in Demat Accounts of Eligible Equity Shareholders:

In accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Prior to the Issue Opening Date, the Rights Entitlements shall be credited in (i) a demat suspense escrow account opened by our Company, for the Eligible Equity Shareholders holding the Equity Shares in dematerialised form, or (ii) a demat suspense escrow account pursuant to Regulation 40 of the SEBI ICDR Regulations, which would comprise Rights Entitlements relating to (a) Equity Shares held in demat suspense account pursuant to Regulation 39 of the SEBI ICDR Regulations; or (b) Equity Shares held in the account of any authority or (c) the demat account of the Eligible Equity Shareholder which are frozen or details of which are unavailable with our Company or with the Registrar on the Record Date, or (d) Equity Shares held by the Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on the Record Date where details of demat accounts are not provided by an Eligible Equity Shareholder to our Company or Registrar; or (e) credit of the Rights Entitlements returned/refunded/lapsed; or (f) the ownership of the Equity Shares under dispute, including any legal proceedings, as applicable or of ineligible equity shareholders in the United States.

Application on Plain Paper under ASBA:

An Eligible Equity Shareholders may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper. An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSB for authorising such SCSB to block Application Money in the said bank account maintained with them. Application on plain paper shall be accepted from applicants on an absolute basis.

Alternatively, Eligible Equity Shareholders may also fill the Application Form available online on the websites of our Company, the Registrar to the Issue or the Stock Exchange to provide requisite details.

Please note that the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall be entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation over what is received subsequently.

The application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with his bank, must reach the office of the Designated Branch of the SCSB before the Issue Closing Date and should contain the following particulars:

- Name of our Company, being **Gujarat Cotex Limited**.
- Name and address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders (in the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depository);
- Folio number (in case of Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as at Record Date) / DP and Client ID;
- PAN of the Eligible Equity Shareholders and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Rights Equity Shares applied for pursuant to this Issue;
- Number of Equity Shares held as at Record Date;
- Allotment option – only dematerialised form;
- Number of Rights Equity Shares entitled to;
- Number of Rights Equity Shares applied to;
- Number of Rights Equity Shares entitled for within the Rights Entitlements;
- Number of Additional Rights Equity Shares applied for, if any (applicable only if entire Rights Entitlements have been applied for);
- Total number of Rights Equity Shares applied for;
- Total amount payable at the rate of Rs. 5/- per Rights Equity Share;
- Details of the ASBA Account such as the SCSB account number, name, address and branch of the relevant SCSB;
- In case of non-resident Rights Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE / FCNR/NRO account such as the account number, name, address and branch of the SCSB with which the account is maintained;
- Authorization to the Designated Branch of the SCSB to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account;
- Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCSB);
- An approval obtained from any regulatory authority, if required, shall be obtained by the Eligible Equity Shareholders and a copy of such approval from any regulatory authority, as may be required, shall be sent to the Registrar to the issue at support@purvashare.com.
- All such Eligible Equity Shareholders shall be deemed to have made the representations, warranties and agreements set forth in "Restrictions on Purchases and Resale" on page no 118 and shall include the following:

"I (We) hereby make representations, warranties and agreements set forth in 'Restrictions on Purchases and Resale' on page no. 118.

I (We) acknowledge that the Company, its affiliates and others will rely upon the truth and accuracy of the representations, warranties and agreements set forth therein."

In cases where multiple Application Forms are submitted for Applications pertaining to Rights Entitlements credited to the same demat account or in demat suspense escrow account, including cases where an investor submits Application Forms along with a plain paper Application, such Applications shall be liable to be rejected.

Investors are requested to strictly adhere to these instructions. Failure to do so could result in an Application being rejected, with our Company and the Registrar not having any liability to the Investor. The plain paper Application format will be available on the website of the Registrar. Our Company and the Registrar shall not be responsible if the Applications are not uploaded by SCSB or funds are not blocked in the Investor's ASBA Account on or before the Issue Closing Date.

Last date for Application: The last date for submission of the duly filled Application Form or a plain paper Application is, May 08, 2026, i.e., Issue Closing Date. Our Board or any committee thereof reserves the right to extend the Issue period as it may determine from time to time, subject to the Issue Period not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Closing Date).

If the Application Form is not submitted with a SCSB or notification of the Stock Exchange or the Application Money is not blocked with the SCSB on or before the Issue Closing Date or such date as may be determined by our board or any committee thereof, the intention to offer consideration in the form of office shall be deemed to have been denied and our Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Rights Equity Share hereby offered, as provided in the section, "Terms of the Issue," on page 87.

Procedure for Renunciation: The Investor may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts, either in full or in part (a) by using the secondary market platform of the Stock Exchange or (b) through an off-market transfer, during the Renunciation Period. The Investors should hold the demat Rights Entitlement and may renounce by transferring the Rights Entitlements. The rules for On Market Renunciation and Off Market Renunciation shall be applicable. Renunciation by transferring the Rights Entitlements through the depository system may be subject to stamp duty or other tax or legal consequences as a matter of trading in the Rights Entitlements; investors who intend to trade in the Rights Entitlements should consult their tax advisers or stock-broker regarding any renunciation. In addition, the Nomination facility is available for the Rights Entitlements. Our Company accepts no responsibility to bear any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage), and such costs will be incurred solely by the Investor. Please note that the Rights Entitlements which are neither renounced nor subscribed by the Investors on or before the Issue Closing Date shall lapse and shall be extinguished after the Issue Closing Date.

a. On Market Renunciation

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts by trading/selling them on the secondary market platform of the Stock Exchange through a registered stock-broker in the same manner as the existing equity shares of our Company.

In this regard, in terms of provisions of the SEBI ICDR Regulations and the SEBI Rights Issue Circulars, the Rights Entitlements credited to the respective demat accounts of the Eligible Equity Shareholders shall be admitted for trading on the Stock Exchange under the ISIN: INE004C20010 subject to requisite approvals. Prior to the Issue Closing Date, our Company will obtain the approval from the Stock Exchange for the same. No assurance can be given regarding the volume or settlement for On Market Renunciation or the price at which the Rights Entitlements will trade. The details for trading in Rights Entitlements will be as specified by the Stock Exchange from time to time.

The Rights Entitlements are tradable in dematerialised form only. The market lot for trading of Rights Entitlements is 1 (one) Rights Entitlement.

The On Market Renunciation shall take place only during the Renunciation Period for On Market Renunciation, i.e., from April 10, 2026 to May 05, 2026 (both days inclusive).

The On Market Renunciation shall take place electronically on the secondary market platform of BSE under an automatic order matching mechanism and on a 'T+1' rolling settlement basis, where 'T' refers to the date of trading. The transactions will be settled on a trade-for-trade basis. Upon execution of the order, the stock-broker will issue a contract note in accordance with the requirements of the Stock Exchange and SEBI.

b. Off Market Renunciation

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts, by way of an off-market transfer through a depository participant. The Rights Entitlements can be transferred in dematerialised form only.

Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that consideration for an off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee on or prior to the Issue Closing Date to enable the Renouncee to subscribe to the Equity Shares in the Issue.

The Investors holding the Rights Entitlements who desire to transfer them will have to do so through their depository participant by issuing a delivery instruction slip, quoting the ISIN: INE004C20010 the details of the buyer, and the number of Rights Entitlements they intend to transfer. The buyer of the Rights Entitlements (unless already having given a standing receipt instruction) has to issue a receipt instruction slip to their depository participant. The Investors can transfer Rights Entitlements only to the extent available in their demat account.

The instructions for the transfer of Rights Entitlements can be issued during the working hours of the depository participant.

Please note that the Rights Entitlements which are neither renounced nor subscribed by the investors on or before the Issue Closing Date shall lapse and shall be extinguished after the Issue Closing Date.

Listing and Trading of the Equity Shares to be Issued Pursuant to this Issue: The existing Equity Shares are listed and traded on BSE (Scrip Code: 514386) under the ISIN: INE004C01028. The Rights Equity Shares shall be credited to a temporary ISIN which will be frozen until the receipt of the final listing/trading approvals from the Stock Exchange. Upon receipt of such approvals, the Rights Equity Shares shall be debited from such temporary ISIN and credited to the new ISIN for the Rights Equity Shares, after which they will be available for trading. The temporary ISIN shall then be permanently deactivated in the depository systems of CDSL and NSDL.

Disclaimer Clause of BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the Disclaimer Clause of BSE Limited."

Availability of Issue Materials: In accordance with the SEBI ICDR Regulations, the Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter, and other Issue material will be sent/dispached only to the Eligible Equity Shareholders who have provided an Indian address and who have made a request in this regard. For such Eligible Equity Shareholders who have provided a valid e-mail address, these documents will be sent electronically. For those who have not provided an e-mail address, the documents will be dispatched, on a reasonable effort basis, to the Indian addresses provided by them.

Investors can access the Letter of Offer and the Application Form (provided that the Eligible Equity Shareholder is eligible to subscribe for the Equity Shares under applicable laws) on the websites of:

- Our Company at www.gujcotex.co
- the Registrar to the issue at www.purvashare.com and
- the Stock Exchange at www.bseindia.com

Allotment Banker Account and Bankers to the Issue and Refund Banker – ICICI Bank Limited

For Risk Factors and other details, kindly refer to page no. 25 of the Letter of Offer.

Other important links and helpline

The investors can visit following links for the below-mentioned purposes:

- Frequently asked questions and online/ electronic dedicated investor helpdesk for guidance on the application process and resolution of difficulties faced by the Investor: www.sebi.gov.in
- Update of Indian address/ e-mail address/ phone or mobile number in the records maintained by the Registrar or our Company: www.purvashare.com
- Update of demat account details by Eligible Equity Shareholders holding shares in physical form: www.purvashare.com
- Submission of self-attested PAN, client master sheet and demat account details by non-resident Eligible Equity Shareholders: www.purvashare.com

REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER
<p>PURVA SHAREREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED Address: Unit No. 9, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Opp. Kasturba Hospital Lower, Mumbai, Maharashtra, India – 400 011 Contact No.: 022-49614132 Email id: support@purvashare.com Investor Grievance Email id: newissue@purvashare.com Website: www.purvashare.com Contact Person: Ms. DeepalDhuri SEBI Registration No.: INR000001112 CIN: U67120MH1993PTC074079</p>	<p>GUJARAT COTEX LIMITED Ms. Shweta Naresh Kumar Temani Registered Office: Shop No. 3, Shanti Complex, Opp. Patel Petrol Pump, Amli, Silvassa, Dadra & Nagar Haveli, India – 396230. CIN: L46695DN1996PLC000116 Email: info@gujcotex.co Contact No: +91-0261 3100550 Website: www.gujcotex.co</p>

Investors may contact the Registrar or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre issue or post issue related matter. All grievances relating the ASBA process may be addressed to the Registrar, with a copy to the SCSBs in case of ASBA process, giving full details such as name, address of the Applicant contact number(s), e-mail address of the sole first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked (in case of ASBA process), ASBA Account number, and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form or the plain paper applications as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip (in case of ASBA process).

For, Gujarat Cotex Limited
 Mr. Shaileshkumar Jayantkumar Parekh
 Managing Director
 (DIN: 01246270)

Date: April 08, 2026
 Place: Silvassa

खबर कोना

नेपाल ने छह देशों से अपने राजदूत वापस बुलाए

काठमांडो, 7 अप्रैल (भाषा)।

नेपाल ने भारत समेत छह देशों से अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं, जिन्हें केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के कार्यकाल में नियुक्त किया गया था। सरकार ने भारत, आस्ट्रेलिया, श्रीलंका, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका में कार्यरत राजदूतों को वापस बुला लिया है। जिन राजदूतों को वापस बुलाया गया है, उनमें शंकर प्रसाद शर्मा (भारत), चित्रलेखा यादव (आस्ट्रेलिया), सुमनिमा तुलाधार (डेनमार्क), पूर्ण बहादुर नेपाली (श्रीलंका), शिवमाया तुम्बाहर्मे (दक्षिण कोरिया) और कपिलमान श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रीका) शामिल हैं।



हर्नोई में वियतनाम के शीर्ष नेता तो लाम ने देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हुए।

बांग्लादेश की पूर्व महिला संसद अध्यक्ष गिरफ्तार

ढाका, 7 अप्रैल (भाषा)।

बांग्लादेश संसद की पूर्व अध्यक्ष शिरिन शरमीन चौधरी को मंगलवार को ढाका मेट्रोपालिटन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मीडिया में आई खबरों में यह जानकारी दी गई है। समाचार पत्र प्रथम आलो की खबर के अनुसार, चौधरी को ढाका मेट्रोपालिटन पुलिस की खुफिया शाखा (डीबी) ने लालबाग थाने में दर्ज एक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया। यह मामला जनआंदोलन के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं से जुड़ा है।

डीबी के एक सूत्र ने बताया कि चौधरी विभिन्न स्थानों पर छिप कर रह रही थीं। अभी वह धनमंडी में एक रिश्तेदार के घर में रह रही थीं, जहां से उन्हें मंगलवार सुबह हिरासत में लिया गया। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक, ढाका मेट्रोपालिटन पुलिस के मीडिया प्रभाग के उपयुक्त एम पन नसीरुद्दीन ने बताया कि चौधरी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा, 'जहां तक हमें जानकारी है, राजधानी के बनानी और उत्तरा थानों में जुलाई आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं को लेकर उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं।'

श्रीलंका से रिहा हुए 30 भारतीय मछुआरे स्वदेश लौटे

कोलंबो, 7 अप्रैल (भाषा)।

श्रीलंका से रिहा किए गए 30 भारतीय मछुआरों को मंगलवार को वापस भेज दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'भारत के 30 मछुआरों को आज श्रीलंका से वापस भेजा गया।' उन्होंने बताया कि ये मछुआरे स्वदेश लौटे रहे हैं। श्रीलंका की नौसेना के अनुसार, उसने इस साल अब तक मछली पकड़ने वाली 15 नौकाएं जब्त कीं और 102 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। उसने कहा कि 2025 में श्रीलंका के जल क्षेत्र में 346 मछुआरों को गिरफ्तार किया गया था। नौसेना के प्रवक्ता कमांडर बुद्धिका संजय ने बताया कि वह नहीं बता सकते कि रिहा किए गए 30 मछुआरे किस समूह से थे।

अल्बोर्ज प्रांत में हवाई हमले में 18 लोगों की मौत, बिजली संयंत्र बचाने की अपील अमेरिका ने ईरान के तेल उद्योग के अहम केंद्र खार्ग द्वीप पर फिर किया हमला

वाशिंगटन, 7 अप्रैल (एपी)।

अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के तेल उद्योग के लिए अति अहम खार्ग द्वीप पर हमला किया है। वाइट हाउस के एक अधिकारी ने पहचान गुप्त रखने की शर्त पर यह जानकारी दी। अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि अमेरिका ने द्वीप पर स्थित सैन्य टिकनों को निशाना बनाया। वहीं, ईरानी अधिकारियों ने युवाओं से बिजली संयंत्रों की सुरक्षा के लिए मानव शृंखला बनाने की अपील की।



सऊदी अरब ने उसके तेल समृद्ध पूर्वी प्रांत पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद बहरीन से जोड़ने वाले एकमात्र सड़क मार्ग को मंगलवार को बंद कर दिया।

ईरान की राजधानी तेहरान के उत्तर पश्चिमी अल्बोर्ज प्रांत में हुए एक हवाई हमले में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है। टूटने वाले द्वीप पर महत्वपूर्ण तेल अवसंरचना पर कब्जा करने के लिए जमीन पर सैनिकों को भी उतारने की धमकी दी है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के अभियान में कई अमेरिकी सैन्य कर्मियों की जान जाएगी और यह युद्ध को समाप्त करने की दिशा में निर्णायक कदम नहीं होगा।

वहीं सऊदी अरब ने उसके तेल समृद्ध पूर्वी प्रांत पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद बहरीन से जोड़ने वाले एकमात्र सड़क मार्ग को मंगलवार को बंद कर दिया। वहीं, ईरानी अधिकारियों ने युवाओं से बिजली संयंत्रों की

मेरे समेत 1.4 करोड़ ईरानी युद्ध में जान देने के लिए तैयार : मसूद पेजेशिकयन

दुर्बई, 7 अप्रैल (एपी)।

अमेरिका की आसन्न समयसीमा के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकयन ने मंगलवार को कहा कि उनके समेत 1.4 करोड़ ईरानी स्वयंसेवक युद्ध में अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति पेजेशिकयन ने यह टिप्पणी एक्स पर उस समय की, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वह समयसीमा करीब आ रही है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि यदि ईरान होमजु जलमार्ग



को दोबारा नहीं खोलता है तो उसके बिजली संयंत्रों और पुलों पर बमबारी की जाएगी। यह संख्या पहले सरकारी मीडिया द्वारा बताया गए स्वयंसेवकों के आंकड़ों से लगभग

दोगुनी है। सरकार युद्ध के दौरान संदेशों और मीडिया के जरिए लोगों से इस तरह के स्वयंसेवी अभियान में शामिल होने की अपील कर रही है। लगभग नौ करोड़ की आबादी वाले ईरान में कई लोग सरकार से नाराज भी हैं, खासकर देशभर में हुए प्रदर्शनों पर की गई सख्त कार्रवाई को लेकर। माना जा रहा है कि 1.4 करोड़ का यह आंकड़ा संभावित अमेरिकी हमले को रोकने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। पेजेशिकयन ने कहा, '1.4 करोड़ से अधिक ईरानी

लोगों ने अभियान में अपनी जान देने के लिए तैयार रहने का इरादा जताया है। मैं भी ईरान के लिए अपनी जान देने के लिए पहले भी तैयार था, अब भी हूँ और आगे भी रहूँगा।'

सुरक्षा के लिए मानव शृंखला बनाने की अपील की, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तय की गई समयसीमा नजदीक आ रही है, जिसमें ईरान से होमजु जलमार्ग को खोलने की मांग की गई है।

ट्रंप ने धमकी दी है कि यदि ईरान मंगलवार रात आठ बजे तक इस रणनीतिक जलमार्ग में जहाजों की आवाजाही पूरी तरह बहाल नहीं करता, तो वह ईरान के सभी बिजली संयंत्रों और पुलों पर बमबारी करेगा। ट्रंप ने कहा, 'पूरे देश को एक रात में खत्म किया जा सकता है।' इजराइल की सेना ने फारसी भाषा में ईरानियों को

दिनभर ट्रेनों से दूर रहने की चेतावनी दी, जो संभवतः रेल नेटवर्क पर हमलों का संकेत था। चेतावनी में कहा गया है, 'आपकी मौजूदगी आपके जीवन को खतरे में डालती है।'

ईरान ने 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद इस जलमार्ग में जहाजों की आवाजाही रोक दी थी, जिससे युद्ध शुरू हुआ। सोमवार को तेहरान ने 45 दिन के युद्धविराम प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि वह युद्ध का स्थायी अंत चाहता है। पिछले कुछ समय से ईरान की राजधानी तेहरान पर लगातार तीव्र हवाई हमले हो रहे हैं।



सुरक्षा

इस्तांबुल में मंगलवार को इजरायली वाणिज्य दूतावास की इमारत पर बंदूकधारियों के हमले के बाद तुर्की पुलिस इलाके को सुरक्षित करने की तैयारी में।

चंद्रमा के आसपास सबसे अधिक दूरी तय करने का बनाया रिकार्ड

ह्यूस्टन, 7 अप्रैल (एपी)।

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आर्टेमिस-2 मिशन के अंतरिक्ष यात्री सोमवार रात चंद्रमा के पिछले हिस्से से निकलकर पृथ्वी की ओर रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने चंद्रमा के उस हिस्से को देखा, जिसे पहले कभी इतने करीब से नहीं देखा गया था और मानव इतिहास में चंद्रमा के आसपास सबसे ज्यादा दूरी तय करने का नया रिकार्ड भी बनाया।

करीब सात घंटे का यह सफर इस मिशन का सबसे खस हिस्सा रहा। अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम के बाद पहली बार नासा ने मनुष्यों को फिर से चंद्रमा पर भेजा। इस मिशन में तीन अमेरिकी और एक कनाडाई अंतरिक्ष यात्री हैं। इसका लक्ष्य अगले दो साल में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास

मनुष्य को भेजना है। आर्टेमिस-2 ने अपोलो 13 का पुराना रिकार्ड तोड़ दिया। साल 1970 में अपोलो 13 मिशन में 4,00,171 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी, जिसे आर्टेमिस-2 मिशन के तहत पार कर लिया गया है।

कनाडाई अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हैनसेन ने कहा, 'बिना कोई उपकरण लगाए आंखों से चंद्रमा से जो दिख रहा है, वह रोमांचित करने वाला है। यह अविश्वसनीय है।' उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी को इस रिकार्ड को जल्द तोड़ना चाहिए। रिकार्ड तोड़ने के तुरंत बाद अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर दो नए गड्डों (क्रेटर) के नाम रखने की अनुमति मांगी। उन्होंने एक का नाम अपने कैप्टल के नाम पर 'इंटेग्रेटी' और दूसरे का नाम कमांडर रीड वाज्जमैन की पत्नी की याद में 'कैरल' रखने का प्रस्ताव दिया।

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की मामला

सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई छह मई से शुरू

नयायमूर्ति

नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय कर दी है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने अंतिम सुनवाई के लिए 6 और 7 मई की तारीख तय की है। इससे पहले कोर्ट ने सरकार सहित सभी पक्षकारों को मामले में लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया था।

याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कानून के मुताबिक तीन सदस्यीय समिति में तीसरे सदस्य के चयन में बदलाव किया जाना चाहिए। बता दें कि मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने अंतिम सुनवाई के लिए 6 और 7 मई की तारीख तय की है। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को मामले में लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया था।

संविधान पीठ ने फैसला दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधान न्यायाधीश की समिति की सलाह पर होनी चाहिए। यही कारण है कि प्रधान न्यायाधीश ने इस कानून पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि इसमें हितों का टकराव है। मुझ पर इसका आरोप लगाया जाएगा। अब यह मामला

मजाक में बोले ट्रंप, बेनेजुएला में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता हूँ



वाशिंगटन, 7 अप्रैल (भाषा)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वह वेनेजुएला में काफी लोकप्रिय हैं और अमेरिका में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद वहां राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने पर विचार कर सकते हैं। ट्रंप ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में मनाकिया अंदाज में कहा कि वह वेनेजुएला में अब तक किसी भी नेता से ज्यादा लोकप्रियता (पोल रेटिंग) हासिल कर सकते हैं।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब जनवरी में अमेरिकी बल वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिल्विया फ्लोरेस को गिरफ्तार करके मादक पदार्थ की तस्करी के मामलों का सामना करने के लिए अमेरिका लाए थे। ट्रंप ने कहा, 'वेनेजुएला के लोग कहते हैं कि अगर मैं वहां राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ूँ, तो मेरी लोकप्रियता अब तक किसी भी व्यक्ति से ज्यादा होगी। इसलिए जब मैं यहां (अमेरिका में) अपना काम खत्म कर लूँगा, तो वेनेजुएला जा सकता हूँ।'

उन्होंने कहा, 'मैं जल्दी ही स्पेनिश सीख लूँगा। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं भाषाओं के ज्ञान में अच्छा हूँ और मैं वेनेजुएला जाऊँगा। मैं राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ूँगा। लेकिन फिलहाल हम वहां के निर्वाचित राष्ट्रपति से बहुत खुश हैं।' वेनेजुएला में तीन जनवरी को निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदारी संभाली।

विक्रम मिसरी आज से अमेरिका की तीन दिवसीय यात्रा पर

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

विदेश सचिव विक्रम मिसरी बुधवार से वाशिंगटन डीसी की तीन दिवसीय यात्रा पर जाएंगे, जहां वह द्विपक्षीय व्यापार और रक्षा संबंधों की समीक्षा करेंगे तथा पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मिसरी की आठ से 10 अप्रैल तक की यह यात्रा भारत-अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक पहलुओं की समीक्षा करने और प्रमुख क्षेत्रों में जारी सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी।

यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब दोनों पक्ष अनिश्चितता और तनाव के दौर के बाद संबंधों को स्थिर करने के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका द्वारा भारत पर बंडात्मक शुल्क लगाए जाने और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पिछले

साल मई में भारत-पाकिस्तान सैन्य झड़पों को कम करने में अपनी भूमिका को लेकर विवादग्रस्त दावे किए जाने के बाद द्विपक्षीय संबंधों में बड़ी गिरावट आई थी।

बताया जा रहा है कि मिसरी की इस यात्रा के दौरान दोनों पक्ष प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने पर भी विचार-विमर्श कर सकते हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'यह यात्रा भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक पहलुओं की समीक्षा करने और प्रमुख क्षेत्रों में जारी सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर देगी।' विदेश मंत्रालय ने बताया कि विदेश सचिव अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापार, रक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वह, क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर भी बातचीत करेंगे जो दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

चुनाव की प्रक्रिया इसी महीने शुरू हो रही

संयुक्त राष्ट्र

कुल चार उम्मीदवार मैदान में

महासचिव पद की दौड़ में दो महिला नेता शामिल

संयुक्त राष्ट्र, 7 अप्रैल (भाषा)।

संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव पद की दौड़ में इस बार दो महिला नेताओं सहित कुल चार उम्मीदवार मैदान में हैं। यह चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब 80 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी महिला को इस वैश्विक संगठन का प्रमुख बनाए जाने की मांग तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव के चुनाव की प्रक्रिया इसी महीने शुरू हो रही है। चारों उम्मीदवार 21 और 22 अप्रैल को न्युयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में होने वाले संवाद सत्रों में भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंतोनियो गुतेर्रेस, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त रह चुके हैं। वह दिसंबर 2026 में अपना दूसरा पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। उन्होंने 2017 में पद



रेबेका ग्रिन्स्पैन



मिशेल बैचलेट

संभाला था और संगठन के 80 साल के इतिहास में अब तक इस पद पर कोई महिला नहीं रही है। इस पद के लिए प्रमुख दावेदारों में चिली की पूर्व राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों के लिए उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट, कोस्टा रिका की पूर्व उपराष्ट्रपति और व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की महासचिव रेबेका

संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंतोनियो गुतेर्रेस, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वह दिसंबर 2026 में अपना दूसरा पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। उन्होंने 2017 में पद संभाला था और संगठन के 80 साल के इतिहास में अब तक इस पद पर कोई महिला नहीं रही है।

ग्रिन्स्पैन, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रीसी और सेनेगल के पूर्व राष्ट्रपति मैकी साल शामिल हैं। इनमें बैचलेट को ब्राजील और मैक्सिको, ग्रिन्स्पैन को कोस्टा रिका, ग्रीसी को अजैटिना और साल को बुरुंडी ने नामित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष एनालना विअरबाक ने

बताया कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए 21 और 22 अप्रैल को तीन-तीन घंटे के संवाद सत्र आयोजित होंगे। महासचिव की नियुक्ति 193 सदस्यीय महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर की जाती है, जहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका वीटो शक्ति रखते हैं।

पिछले वर्ष सितंबर में पारित एक प्रस्ताव में इस बात पर खेद जताया गया कि अब तक कोई महिला महासचिव नहीं बनी और सदस्य देशों से महिलाओं को नामित करने का आग्रह किया गया। कई अधिकार संगठनों और अभियानों, जैसे वुमेन एसजी और 1 फार 8 बिलियन ने महिला उम्मीदवार के चयन की मांग करते हुए कहा है कि यह केवल प्रतीकात्मक कदम नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और भविष्य के लिए आवश्यक है।

भारत में अमेरिकी राजदूत गोर की वेंस से मुलाकात

वाशिंगटन, 7 अप्रैल (भाषा)।

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्गेई गोर ने यहां अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की और भारत के साथ संबंधों पर ध्यान देने के लिए उनका आभार जताया। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका में मौजूद गोर मंगलवार को रात्रिभोज पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। गोर ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, 'अभी-अभी उपराष्ट्रपति के साथ एक शानदार बैठक सम्पन्न हुई। अमेरिका-भारत संबंधों के मामले में निरंतर नेतृत्व और ध्यान के लिए उपराष्ट्रपति वेंस का आभार। राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में वाइट हाउस इस क्षेत्र पर पूरी तरह से ध्यान दे रहा है।'

इस बीच अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन बत्रा ने यहां गोर से मुलाकात की और कहा कि दोनों देश रणनीतिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

AUROBINDO PHARMA LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L24239TG1986PLC015190

Registered Office: Plot No. 2, Maithrivi, Ameerpet, Hyderabad- 500 038, Telangana, India

Corporate Office: Galaxy, Floors: 22-24, Plot No.83/1, Survey No.83/1, Hyderabad Knowledge City, Raidurg Panmakha, Ranga Reddy District, Hyderabad - 500032, Telangana, India

Tel.: +91 40 2373 6370/ 2374 7340; Fax: +91 40 2374 1080/ 2374 6833; Website: www.aurobindo.com; Email: cs@aurobindo.com

Contact Person: Mr. B. Adi Reddy, Company Secretary and Compliance Officer

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF AUROBINDO PHARMA LIMITED ("COMPANY") FOR THE BUYBACK OF EQUITY SHARES ON A PROPORTIONATE BASIS THROUGH TENDER OFFER ROUTE USING STOCK EXCHANGE MECHANISM AS PRESCRIBED UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED FROM TIME TO TIME ("BUYBACK REGULATIONS").

This public announcement ("Public Announcement"/ "PA") is being made pursuant to Regulation 7(i) of the Buyback Regulations, in relation to the buyback of fully paid-up equity shares, having a face value of ₹ 1/- (Rupee One only) each ("Equity Share"), by the Company from its Equity Shareholders/ Beneficial Owners through the Tender Offer route using the stock exchange mechanism in accordance with Securities and Exchange Board of India ("SEBI") circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with the circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016, circular SEBI/HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021 and circular SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/35 dated March 8, 2023, including any further amendments thereof ("SEBI Circulars"), and contains the disclosures as specified in Schedule II to the Buyback Regulations.

OFFER TO BUYBACK UP TO 54,23,728 (FIFTY FOUR LAKH TWENTY THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED AND TWENTY EIGHT) EQUITY SHARES AT A PRICE OF ₹ 1,475/- (RUPEES ONE THOUSAND FOUR HUNDRED AND SEVENTY FIVE ONLY) PER EQUITY SHARE, PAYABLE IN CASH, ON A PROPORTIONATE BASIS THROUGH THE TENDER OFFER ROUTE USING THE STOCK EXCHANGE MECHANISM FOR AN AGGREGATE CONSIDERATION OF UP TO ₹ 800,00,00,000/- (RUPEES EIGHT HUNDRED CRORE ONLY).

1 DETAILS OF THE BUYBACK OFFER AND BUYBACK PRICE

1.1 At the meeting held on Monday, April 6, 2026 ("Board Meeting"), the Board of Directors of the Company (hereinafter referred to as the "Board"), which expression shall include any committee constituted by the Board to exercise its powers, including the powers conferred by the resolution passed by the Board at the Board Meeting), subject to such approvals of regulatory and/or statutory authorities as may be required under applicable laws, has approved the buyback of up to 54,23,728 (Fifty Four Lakh Twenty Three Thousand Seven Hundred and Twenty Eight) Equity Shares, representing approximately 0.93% of the total number of outstanding Equity Shares of the Company, at a price of ₹ 1,475/- (Rupees One Thousand Four Hundred and Seventy Five Only) per Equity Share ("Buyback Price"), subject to any increase to the Buyback Price as may be approved by the Board, payable in cash for an aggregate amount up to ₹ 800,00,00,000/- (Rupees Eight Hundred Crore Only) ("Buyback Size"), excluding transaction costs, applicable taxes and other incidental and related expenses, from all of the equity shareholders/ beneficial owners of the Company, including the members of the promoter and promoter group of the Company ("Promoter & Promoter Group"), who hold Equity Shares as of the Record Date (as defined below) on a proportionate basis through the "Tender Offer" route in accordance with the provisions of the Buyback Regulations, Companies Act, 2013, as amended ("Companies Act"), rules framed thereunder including the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, as amended ("Share Capital Rules"), and the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended ("Management Rules"), the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations"), to the extent applicable, and the SEBI Circulars (hereinafter referred to as "Buyback").

1.2 The Buyback Size constitutes 3.93% and 2.62% of the aggregate of the total paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium) of the Company as per the latest audited standalone and consolidated financial statements of the Company as at March 31, 2025, respectively, and is within the statutory limit of 10% of the aggregate of the total paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium) of the Company based on the audited standalone and consolidated financial statements of the Company as at March 31, 2025, under the board approval route as per Section 68 and other applicable provisions of the Companies Act and Regulation 5 and other applicable provisions of the Buyback Regulations. Further, since the Equity Shares proposed to be bought back represent approximately 0.93% of the total number of outstanding Equity Shares of the Company as of March 31, 2025 and December 31, 2025, the same is within the 25% limit as per the provisions of the Companies Act and Regulation 4(i) of the Buyback Regulations.

1.3 The Buyback is in accordance with Article 40(b) of the Articles of Association of the Company and Sections 68, 69, 70 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, and rules framed thereunder, including the Share Capital Rules, the Management Rules, the Listing Regulations to the extent applicable, Buyback Regulations read with SEBI Circulars, subject to such other approvals, permissions, consents, exemptions and sanctions, as may be necessary and subject to any modifications and conditions, if any, as may be prescribed by SEBI, Registrar of Companies, Telangana at Hyderabad, National Stock Exchange of India Limited ("NSE"), BSE Limited ("BSE") and/ or other authorities, institutions or bodies, as may be necessary and subject to such conditions and modifications as may be prescribed or imposed while granting such approvals, permissions, sanctions and exemptions, which may be agreed by the Board.

1.4 In terms of Regulation 5(via) of the Buyback Regulations, the Board or the committee constituted by the Board, may till 1 (One) working day prior to the Record Date, increase the Buyback Price and decrease the number of Equity Shares proposed to be bought back, such that there is no change in the Buyback Size.

1.5 The Buyback Size does not include transaction costs viz. brokerage costs, fees, turnover charges, applicable taxes such as securities transaction tax, goods and services tax, stamp duty, etc., expenses incurred or to be incurred for the Buyback like filing fees payable to SEBI, advisors/ legal fees, public announcement publication expenses, printing and dispatch expenses for Letter of Offer and other incidental and related expenses, etc. ("Transaction Costs").

1.6 The Equity Shares of the Company are listed on NSE and BSE ("Stock Exchanges"). The Buyback shall be undertaken on a proportionate basis (subject to reservation for small shareholders) from all the equity shareholders/ beneficial owners of the Company, including the members of the Promoter & Promoter Group, who hold Equity Shares as at Friday, April 17, 2026 (the "Record Date") (such shareholders "Eligible Shareholders") through the Tender Offer process prescribed under Regulation 4(iv)(a) of the Buyback Regulations and shall be implemented using the stock exchange mechanism as specified in the SEBI Circulars. In this regard, the Company will request BSE to provide the acquisition window for facilitating tendering of Equity Shares under the Buyback and, for the purposes of this Buyback, BSE will be the designated stock exchange.

1.7 The Buyback from the Eligible Shareholders who are residents outside India including non-resident Indians, foreign nationals, foreign corporate bodies (including erstwhile overseas corporate bodies), foreign institutional investors/ foreign portfolio investors, shall be subject to such approvals, if any, and to the extent necessary or required from the concerned authorities including approvals from the Reserve Bank of India ("RBI") under the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations framed thereunder, and that such approvals shall be required to be taken by such non-resident shareholders.

1.8 In terms of the Buyback Regulations, under Tender Offer route, the members of the Promoter & Promoter Group and persons in control of the Company have the option to participate in the Buyback. In this regard, the members of the Promoter & Promoter Group vide their letters dated April 7, 2026, have expressed their intention to participate in the Buyback. The extent of their participation in the Buyback has been detailed in Paragraph 6.3 of this Public Announcement.

1.9 The Buyback will not result in any benefit to Promoter & Promoter Group or persons in control of the Company or any directors of the Company except to the extent of the cash consideration received by them from the Company pursuant to their respective participation in the Buyback in their capacity as equity shareholders of the Company, and the change in their shareholding as per the response received in the Buyback, as a result of the extinguishment of Equity Shares, which will lead to reduction in the equity share capital of the Company post Buyback. The Buyback would be subject to the condition of maintaining minimum public shareholding requirements as specified in Regulation 38 of the Listing Regulations. Any change in voting rights of the Promoter & Promoter Group of the Company pursuant to completion of Buyback will not result in any change in control over the Company.

1.10 Participation in the Buyback by Eligible Shareholders may trigger capital gains taxation in India and in their country of residence. The transaction of Buyback would also be chargeable to securities transaction tax in India. In due course, Eligible Shareholders will receive a letter of offer, which will contain a more detailed note on taxation. However, in view of the particularized nature of tax consequences, Eligible Shareholders are advised to consult their own legal, financial and tax advisors for the applicable tax implications prior to participating in the Buyback.

A copy of this Public Announcement is available on the website of the Company (www.aurobindo.com), the website of Manager to the Buyback (www.axiscapital.co.in) and is expected to be available on the website of SEBI (www.sebi.gov.in) during the period of the Buyback and on the website of NSE (www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com).

2 NECESSITY FOR THE BUYBACK

The Buyback is being undertaken, *inter-alia*, for the following reasons:

- The Buyback will help the Company to reward its shareholders and enhance the overall return to shareholders;
- The Buyback is expected to improve earnings per share and other key ratios such as return on net worth and return on assets over a period of time; and
- The Buyback, which is being implemented through the Tender Offer route as prescribed under the Buyback Regulations, would involve allocation of number of Equity Shares as per their entitlement or 15% of the number of Equity Shares to be bought back, whichever is higher, reserved for small shareholders. The Company

believes that this reservation for small shareholders would benefit a large number of public shareholders, who would get classified as "small shareholders" as per Regulation 2(i)(n) of the Buyback Regulations.

3 MAXIMUM NUMBER OF EQUITY SHARES THAT THE COMPANY PROPOSES TO BUYBACK

The Company proposes to buyback up to 54,23,728 (Fifty Four Lakh Twenty Three Thousand Seven Hundred and Twenty Eight) Equity Shares, representing 0.93% of the total number of outstanding Equity Shares of the Company as of March 31, 2025 and as of December 31, 2025.

4 MAXIMUM PRICE FOR BUYBACK OF THE EQUITY SHARES AND BASIS OF ARRIVING AT THE BUYBACK PRICE

4.1 The Equity Shares are proposed to be bought back at a price of ₹ 1,475/- (Rupees One Thousand Four Hundred and Seventy Five Only) per Equity Share.

4.2 The Buyback Price has been arrived at after considering various factors including, but not limited to the trends in the volume weighted average prices and the closing price of the Equity Shares at the Stock Exchanges.

4.3 The Buyback Price represents:

4.3.1 premium of 20.86% and 21.82% over the volume weighted average market price of the Equity Share on BSE and NSE, respectively, during the 3 (three) months preceding Tuesday, March 31, 2026, being the date of intimation to the Stock Exchanges for the Board Meeting to consider the proposal of the Buyback ("Intimation Date").

4.3.2 premium of 13.18% and 14.21% over the volume weighted average market price of the Equity Share on BSE and NSE, respectively, during the 2 (two) weeks preceding the Intimation Date.

4.3.3 premium of 13.18% and 13.08% over the closing price of the Equity Share on BSE and NSE, respectively, as on the trading day immediately preceding the Intimation Date, i.e., Monday, March 30, 2026.

4.3.4 premium of 10.09% and 10.04% over the closing price of the Equity Share on BSE and NSE, respectively, as on Monday, April 6, 2026, being the date of the Board Meeting.

4.4 The closing market price of the Equity Shares on the trading day immediately preceding the Intimation Date, i.e., Monday, March 30, 2026, was ₹ 1,303.20/- and ₹ 1,304.40/- and as on the date of the Board Meeting was ₹ 1339.80/- and 1340.40/- on BSE and NSE, respectively.

4.5 As required under Section 68(2)(d) of the Companies Act and Regulation 4(ii) (a) of Buyback Regulations, the ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owed by the Company will not be more than twice the paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium) after the Buyback based on standalone and consolidated financial statements of the Company as on March 31, 2025, whichever sets out a lower amount.

4.6 In terms of Regulation 5(via) of the Buyback Regulations, the Board may, till 1 (One) working day prior to the Record Date, increase the Buyback Price and decrease the number of Equity Shares proposed to be bought back, such that there is no change in the Buyback Size.

5 MAXIMUM AMOUNT OF FUNDS REQUIRED FOR THE BUYBACK, ITS PERCENTAGE OF THE TOTAL PAID-UP CAPITAL AND FREE RESERVES AND SOURCES OF FUNDS FROM WHICH BUYBACK WOULD BE FINANCED

5.1 The maximum amount required for the Buyback will not exceed ₹ 800,00,00,000/- (Rupees Eight Hundred Crore Only) (excluding Transaction Costs). The Buyback Size constitutes 3.93% and 2.62% of the aggregate of the total paid-up share capital and free reserves (including securities premium), as per the latest audited standalone and consolidated financial statements of the Company as at March 31, 2025, respectively, which is within the statutory limit of 10% of the total paid-up equity capital and free reserves (including securities premium) of the Company as at March 31, 2025, under the Board approval route as per Section 68 and other applicable provisions of the Companies Act and Regulation 5 and other applicable provisions of the Buyback Regulations.

5.2 The funds for implementation of the proposed Buyback will be sourced out of the free reserves (including securities premium) of the Company and/ or such other sources as may be permitted by Buyback Regulations or the Companies Act. Funds borrowed from banks and financial institutions, if any, will not be used for the Buyback.

5.3 The Company shall transfer from its free reserves and/ or such other sources as may be permitted by law, a sum equal to the nominal value of the Equity Shares bought back through the Buyback to the capital redemption reserve account and the details of such transfer shall be disclosed in its subsequent audited financial statements.

6 DETAILS OF HOLDING AND TRANSACTIONS IN THE EQUITY SHARES BY THE MEMBERS OF THE PROMOTER & PROMOTER GROUP, PERSONS IN CONTROL, DIRECTORS/ TRUSTEES OF MEMBERS OF THE PROMOTER & PROMOTER GROUP, DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL OF THE COMPANY AND INTENTION OF MEMBERS OF THE PROMOTER & PROMOTER GROUP AND PERSONS IN CONTROL OF THE COMPANY TO PARTICIPATE IN THE BUYBACK

6.1 The aggregate shareholding in the Company of (a) the members of the Promoter & Promoter Group and persons in control of the Company; (b) director(s)/ trustee(s) of the companies/ trusts forming part of the Promoter & Promoter Group; (c) the directors (other than members of the Promoter & Promoter Group) and key managerial personnel, as on the date of the Board Meeting, i.e., (Monday, April 6, 2026) and the date of this Public Announcement, are as follows:

6.1.1 Aggregate shareholding of the members of the Promoter & Promoter Group and persons in control of the Company in the Company:

Sr. No.	Name	Category	Number of Equity Shares held	% shareholding
1.	Venkata Ramprasad Reddy Penaka	Promoter	1,78,33,646	3.07
2.	K Nithyananda Reddy	Promoter	2,53,59,572	4.37
Total (A)			4,31,93,218	7.44
3.	M Sivakumaran	Promoter Group	1,43,57,432	2.47
4.	K Rajeshwari	Promoter Group	18,08,631	0.31
5.	Suneela Rani Penaka	Promoter Group	1,28,799	0.02
6.	Prasada Reddy Kambham	Promoter Group	2,98,373	0.05
7.	K Suryaprakash Reddy	Promoter Group	7,380	0.00
8.	M Sumanth Kumar Reddy	Promoter Group	15,85,214	0.27
9.	Kirithi Reddy Kambam	Promoter Group	2,00,62,852	3.45
10.	Kambam Spoorthi	Promoter Group	69,39,173	1.19
11.	Penaka Neha Reddy	Promoter Group	Nil	Nil
12.	Trident Chemphar Limited	Promoter Group	7,82,241	0.13
13.	Axis Clinicals Limited	Promoter Group	6,51,920	0.11
14.	RPR Sons Advisors Private Limited, Suneela Rani (joint holding)	Promoter Group	19,45,61,357	33.50
15.	Axis Clinicals Limited, Trident Chemphar Limited, RPR Sons Advisors Private Limited (joint holding)	Promoter Group	1,65,72,131	2.85
Total (B)			25,77,55,503	44.38
Total (A+B)			30,09,48,721	51.82

6.1.2 Aggregate shareholding of the director(s)/ trustee(s) of the companies/ trusts forming part of the Promoter & Promoter Group in the Company:

Sr No	Name of Company/ Trust forming part of the Promoter & Promoter Group	Name of the Director/ Trustee	No. of Equity Shares	% shareholding
1.	Axis Clinicals Limited	Jayachandra Reddy Atluri	29,000	0.01
2.	RPR Sons Advisors Private Limited	Venkata Ramprasad Reddy Penaka	1,78,33,646	3.07
		Suneela Rani Penaka	1,28,799	0.02

6.1.3 Aggregate shareholding of the directors and key managerial personnel of the Company (other than members of the Promoter & Promoter Group) in the Company:

Sr. No.	Name	Number of Equity Shares held	% shareholding
1.	S. Subramanian	7,063	Negligible
2.	M. Madan Mohan Reddy	2,010	Negligible
Total		9,073	Negligible

6.2 No Equity Shares or other specified securities in the Company were either purchased or sold by (a) the members of the Promoter & Promoter Group and persons who are in control of the Company; (b) the director(s)/ trustee(s) of the companies/ trusts forming part of the Promoter & Promoter Group; and (c) directors and key managerial personnel of the Company, during a period of 6 (six) months preceding the date of the Board Meeting where the Buyback was approved and until the date of this Public Announcement, except as set out below:

Name	Aggregate no. of Equity Shares allotted / transferred	Nature of transaction	Maximum price per Equity Share (₹)*	Date of maximum price	Minimum price per Equity Share (₹)*	Date of minimum price
Jayachandra Reddy Atluri	1,680	Sale	1,270	March 10, 2026	1,268	March 10, 2026

* Excluding transaction costs such as brokerage, securities transaction tax etc.

6.3 Intention of members of the Promoter & Promoter Group and persons in control of the Company to participate in the Buyback:

In terms of the Buyback Regulations, under Tender Offer route, the members of the Promoter & Promoter Group and persons in control of the Company have the option to participate in the Buyback. In this regard, the members of the Promoter & Promoter Group vide their letters dated April 7, 2026, have expressed their intention to participate in the Buyback and tender up to the number of Equity Shares set out in the table below, or such lower number of Equity Shares as permitted under the applicable law:

Sr. No.	Name	Number of Equity Shares held	Maximum number of Equity Shares intended to be tendered up to
1.	Venkata Ramprasad Reddy Penaka	1,78,33,646	3,22,000
2.	K Nithyananda Reddy	2,53,59,572	4,58,000
3.	M Sivakumaran	1,43,57,432	2,60,000
4.	K Rajeshwari	18,08,631	33,000
5.	Suneela Rani Penaka	1,28,799	3,000
6.	Prasada Reddy Kambham	2,98,373	6,000
7.	K Suryaprakash Reddy	7,380	Nil
8.	M Sumanth Kumar Reddy	15,85,214	29,000
9.	Kirithi Reddy Kambam	2,00,62,852	3,62,000
10.	Kambam Spoorthi	69,39,173	1,26,000
11.	Trident Chemphar Limited	7,82,241	15,000
12.	Axis Clinicals Limited	6,51,920	12,000
13.	RPR Sons Advisors Private Limited, Suneela Rani (joint holding)	19,45,61,357	35,07,000
14.	Axis Clinicals Limited, Trident Chemphar Limited, RPR Sons Advisors Private Limited (joint holding)	1,65,72,131	3,00,000
Total		30,09,48,721	54,33,000

6.4 The entire shareholding of the members of the Promoter & Promoter Group is in demat mode. The details of the date and price of acquisition of the Equity Shares proposed to be tendered in the Buyback by the members of the Promoter & Promoter Group and persons in control of the Company who intend to participate in the Buyback are set out below:

6.4.1 Venkata Ramprasad Reddy Penaka

Sr. No.	Date of Acquisition	Nature of transaction	Face Value (in ₹)	Number of Equity Shares acquired	Issue price/ transfer price per Equity Share (in ₹)
1	July 22, 2015 ⁽¹⁾	Bonus issue in the ratio of 1:1	1	3,22,000	Nil

Note: (1) Received a total of 90,00,000 equity shares pursuant to the bonus issuance, of which 1,66,354 equity shares have been accepted in the previous buyback undertaken by the Company which was settled on August 19, 2024.

6.4.2 K Nithyananda Reddy

Sr. No.	Date of Acquisition	Nature of transaction	Face Value (in ₹)	Number of Equity Shares acquired	Issue price/ transfer price per Equity Share (in ₹)
1	July 22, 2015 ⁽¹⁾	Bonus issue in the ratio of 1:1	1	4,58,000	Nil

Note: (1) Received a total of 1,37,62,350 equity shares pursuant to the bonus issuance.

6.4.3 M Sivakumaran

Sr. No.	Date of Acquisition	Nature of transaction	Face Value (in ₹)	Number of Equity Shares acquired	Issue price/ transfer price per Equity Share (in ₹)
1	July 22, 2015 ⁽¹⁾	Bonus issue in the ratio of 1:1	1	2,60,000	Nil

Note: (1) Received a total of 73,45,680 equity shares pursuant to the bonus issuance, of which 1,33,928 equity shares have been accepted in the previous buyback undertaken by the Company which was settled on August 19, 2024.

6.4.4 K Rajeshwari

Sr. No.	Date of Acquisition	Nature of transaction	Face Value (in ₹)	Number of Equity Shares acquired	Issue price/ transfer price per Equity Share (in ₹)
1	July 22, 2015 ⁽¹⁾	Bonus issue in the ratio of 1:1	1	33,000	Nil

Note: (1) Received a total of 8,87,750 equity shares pursuant to the bonus issuance, of which 16,869 equity shares have been accepted in the previous buyback undertaken by the Company which was settled on August 19, 2024.

6.4.5 Suneela Rani Penaka

Sr. No.	Date of Acquisition	Nature of transaction	Face Value (in ₹)	Number of Equity Shares acquired	Issue price/ transfer price per Equity Share (in ₹)
1	September 30, 2021 ⁽¹⁾	Gift from member of Promoter & Promoter Group	1	3,000	Nil

Note: (1) Received a total of 1,30,000 equity shares from Penaka Neha Reddy, a member of the Promoter & Promoter Group, of which 1,201 equity shares have been accepted in the previous buyback undertaken by the Company which was settled on August 19, 2024.

6.4.6 Prasada Reddy Kambham

Sr. No.	Date of Acquisition	Nature of transaction	Face Value (in ₹)	Number of Equity Shares acquired	Issue price/ transfer price per Equity Share (in ₹)
1	July 22, 2015 ⁽¹⁾	Bonus issue in the ratio of 1:1	1	6,000	Nil

Note: (1) Received a total of 2,00,578 equity shares pursuant to the bonus issuance, of which 2,783 equity shares have been accepted in the previous buyback undertaken by the Company which was settled on August 19, 2024.

6.4.7 M Sumanth Kumar Reddy

Sr. No.	Date of Acquisition	Nature of transaction	Face Value (in ₹)	Number of Equity Shares acquired	Issue price/ transfer price per Equity Share (in ₹)
1	July 22, 2015 ⁽¹⁾	Bonus issue in the ratio of 1:1	1	29,000	Nil

Note: (1) Received a total of 8,00,000 equity shares pursuant to the bonus issuance, of which 14,786 equity shares have been accepted in the previous buyback undertaken by the Company which was settled on August 19, 2024.

6.4.8 Kirthi Reddy Kambam

Sr. No.	Date of Acquisition	Nature of transaction	Face Value (in ₹)	Number of Equity Shares acquired	Issue price/transfer price per Equity Share (in ₹)
1	July 22, 2015 ⁽¹⁾	Bonus issue in the ratio of 1:1	1	3,62,000	Nil

Note: (1) Received a total of 1,03,50,000 equity shares pursuant to the bonus issuance, of which 1,87,148 equity shares have been accepted in the previous buyback undertaken by the Company which was settled on August 19, 2024.

6.4.9 Kambam Spoorthi

Sr. No.	Date of Acquisition	Nature of transaction	Face Value (in ₹)	Number of Equity Shares acquired	Issue price/transfer price per Equity Share (in ₹)
1	July 22, 2015 ⁽¹⁾	Bonus issue in the ratio of 1:1	1	1,26,000	Nil

Note: (1) Received a total of 38,00,000 equity shares pursuant to the bonus issuance, of which 60,827 equity shares have been accepted in the previous buyback undertaken by the Company which was settled on August 19, 2024.

6.4.10 Trident Chemphar Limited

Sr. No.	Date of Acquisition	Nature of transaction	Face Value (in ₹)	Number of Equity Shares acquired	Issue price/transfer price per Equity Share (in ₹)
1	March 18, 2020 ⁽¹⁾	Market purchase	1	15,000	392.82

Note: (1) Acquired a total of 1,30,000 equity shares through market purchase at a weighted average price of ₹ 392.82/-, of which 7,296 equity shares have been accepted in the previous buyback undertaken by the Company which was settled on August 19, 2024.

6.4.11 Axis Clinicals Limited

Sr. No.	Date of Acquisition	Nature of transaction	Face Value (in ₹)	Number of Equity Shares acquired	Issue price/transfer price per Equity Share (in ₹)
1	July 22, 2015 ⁽¹⁾	Bonus issue in the ratio of 1:1	1	12,000	Nil

Note: (1) Received a total of 26,18,745 equity shares pursuant to the bonus issuance, of which 6,080 equity shares have been accepted in the previous buyback undertaken by the Company which was settled on August 19, 2024.

6.4.12 RPR Sons Advisors Private Limited, Suneela Rani (Joint holding)

Sr. No.	Date of Acquisition	Nature of transaction	Face Value (in ₹)	Number of Equity Shares acquired	Issue price/transfer price per Equity Share (in ₹)
1	January 19, 2017 ⁽¹⁾	Contribution by partners through an off-market transfer	1	35,07,000	12.12

Note: (1) 19,63,76,250 Equity Shares of the Company were contributed by Suneela Rani Penaka, a member of the Promoter & Promoter Group, at a weighted average price of ₹ 12.12/- per equity share, of which 18,14,893 equity shares have been accepted in the previous buyback undertaken by the Company which was settled on August 19, 2024.

6.4.13 Axis Clinicals Limited, Trident Chemphar Limited, RPR Sons Advisors Private Limited (Joint holding)

Sr. No.	Date of Acquisition	Nature of transaction	Face Value (in ₹)	Number of Equity Shares acquired	Issue price/transfer price per Equity Share (in ₹)
1	March 30, 2017 ⁽¹⁾	Contribution by partners through an off-market transfer	1	3,00,000	32.64

Note: (1) 45,79,490 equity shares of the Company were contributed by Axis Clinicals Limited and 1,21,47,226 Equity Shares of the Company were contributed by Trident Chemphar Limited both members of the Promoter & Promoter Group, at a weighted average price of ₹ 32.64/- per equity share, of which 1,54,585 equity shares have been accepted in the previous buyback undertaken by the Company which was settled on August 19, 2024.

7 CONFIRMATIONS FROM THE COMPANY AS PER THE PROVISIONS OF THE BUYBACK REGULATIONS AND THE COMPANIES ACT

- 7.1 All the Equity Shares of the Company are fully paid up.
- 7.2 The Company shall not issue and allot any Equity Shares or other specified securities (including by way of bonus), from the date of the Board Meeting till the expiry of the Buyback period, i.e., the date on which the payment of consideration is made to the shareholders who have accepted the Buyback, except in discharge of subsisting obligations through conversion of warrants, stock option schemes, sweat equity or conversion of preference shares or debentures into equity shares. There are no subsisting obligations to issue or allot any Equity Shares or other specified securities through conversion of warrants, stock option schemes, sweat equity or conversion of preference shares or debentures into equity shares.
- 7.3 Unless otherwise specifically permitted by any relaxation issued by SEBI and/ or any other regulatory authority, the Company shall not raise further capital for a period of 1 (One) year, as prescribed under the provisions of Regulation 24(i)(f) of the Buyback Regulations, from the expiry of the Buyback period, i.e., the date on which the payment of consideration is made to the shareholders who have accepted the Buyback, except in discharge of its subsisting obligations.
- 7.4 The Company, as per the provisions of Section 68(8) of the Companies Act, will not make a further issue of the same kind of shares or other securities including allotment of new shares under Section 62(1)(a) or other specified securities within a period of 6 (Six) months except by way of a bonus issue or in the discharge of subsisting obligations such as conversion of warrants, stock option schemes, sweat equity or conversion of preference shares or debentures into equity shares.
- 7.5 The Company shall not withdraw the Buyback after the Public Announcement of the offer to Buyback is made.
- 7.6 The Company will ensure consequent reduction of its share capital post Buyback and the Equity Shares bought back by the Company will be extinguished and physically destroyed in the manner prescribed under the Buyback Regulations and the Companies Act within the specified timelines.
- 7.7 The Company shall not buyback locked-in Equity Shares and non-transferable Equity Shares until the pendency of the lock-in or till the Equity Shares become transferable.
- 7.8 The consideration for the Buyback shall be paid by the Company only by way of cash.
- 7.9 Funds borrowed from banks and financial institutions, if any, will not be used for the Buyback.
- 7.10 The Company shall not buyback its Equity Shares or other specified securities from any person through negotiated deals whether on or off the Stock Exchanges or through spot transactions or through any private arrangement in the implementation of Buyback.
- 7.11 There are no defaults (either in the past or subsisting) in the repayment of any deposits (including interest payable thereon), redemption of debentures or preference shares, payment of dividend or repayment of any term loans to any financial institution or banks (including interest payable thereon), as the case may be, and in case of defaults which have ceased to subsist, if any, a period of more than 3 (three) years has lapsed.
- 7.12 The Company has not undertaken a buyback of any of its securities during the period of 1 (One) year immediately preceding the date of the Board Meeting.
- 7.13 The Company has been in compliance with Sections 92, 123, 127 and 129 of the Companies Act.
- 7.14 The aggregate amount of the Buyback (i.e., up to ₹ 800,00,00,000/- (Rupees Eight Hundred Crore Only) does not exceed 10% of the aggregate of the total paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium) of the Company as per the latest audited standalone and consolidated financial statements of the Company as at March 31, 2025.
- 7.15 The maximum number of Equity Shares proposed to be purchased under the Buyback (i.e., 54,23,728 (Fifty Four Lakh Twenty Three Thousand Seven Hundred and Twenty Eight) Equity Shares) does not exceed 25% of the total number of outstanding Equity Shares of the Company as at March 31, 2025 and December 31, 2025.
- 7.16 The Company shall not make any offer of buyback within a period of 1 (One) year reckoned from the date of expiry of the Buyback period i.e., the date on which the payment of consideration is made to the shareholders whose equity shares have been accepted in the Buyback.
- 7.17 The Company shall comply with the statutory and regulatory timelines in respect of the Buyback in such manner as prescribed under the Companies Act and/ or the Buyback Regulations and any other applicable laws.
- 7.18 The Buyback shall be completed within a period of 1 (One) year from the date of passing of the Board resolution approving the Buyback.
- 7.19 There is no pendency of any scheme of amalgamation or compromise or arrangement pursuant to the provisions of the Companies Act, as on date.

7.20 The ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owed by the Company shall not be more than twice its paid-up capital and free reserves (including securities premium) after the Buyback, based on latest audited standalone and consolidated financial statements of the Company, as prescribed under the Companies Act and rules made thereunder and Buyback Regulations.

7.21 The Company is not buying back its Equity Shares so as to delist its shares or other specified securities from the Stock Exchanges.

7.22 The Company shall not directly or indirectly purchase its Equity Shares through any subsidiary company including its own subsidiary companies, or through any investment company or group of investment companies.

7.23 As per Regulation 24(i)(e) of the Buyback Regulations, the members of the Promoter & Promoter Group, and their associates, shall not deal in the Equity Shares or other specified securities of the Company either through the stock exchanges or off-market transactions (including inter-se transfer of Equity Shares among the members of the Promoter & Promoter Group) from the date of the Board resolution approving the Buyback till the closing of the Buyback offer.

7.24 In accordance with Regulation 6 of the Buyback Regulations, the Company shall reserve 15% of the number of Equity Shares which the Company proposes to buyback or such number of Equity Shares entitled as per the shareholding of small shareholders as on the Record Date, whichever is higher, for the small shareholders as part of the Buyback.

7.25 The Company shall transfer from its free reserves and/ or such other sources as may be permitted by law, a sum equal to the nominal value of the Equity Shares bought back through the Buyback to the capital redemption reserve account and the details of such transfer shall be disclosed in its subsequent audited financial statement.

7.26 The Company has outstanding facilities with its lenders. In accordance with Regulation 5(i)(c) and Clause (xii) of Schedule I of the Buyback Regulations, the Company shall not undertake the Buyback unless it has obtained prior consent of its lenders, in case of breach of any covenant with such lenders. The Company confirms that it has obtained the prior consent of its lenders, as necessary, for undertaking the Buyback.

8 CONFIRMATIONS FROM THE BOARD OF THE COMPANY

8.1 As required by Clause (x) of Schedule I of the Buyback Regulations, the Board has confirmed that it has made full enquiry into the affairs and prospects of the Company and has formed an opinion, that:

8.1.1 immediately following the date of the Board Meeting, i.e., Monday, April 6, 2026, approving the Buyback, there will be no grounds on which the Company could be found unable to pay its debts, if any;

8.1.2 as regards the Company's prospects for the year immediately following the date of Board Meeting and having regard to the Board's intention with respect to the management of the Company's business during that year and to the amount and character of the financial resources, which will, in the Board's view, be available to the Company during that year, the Company will be able to meet its liabilities as and when they fall due and will not be rendered insolvent within a period of 1 (One) year from the date of the Board Meeting; and

8.1.3 in forming its opinion aforesaid, the Board has taken into account the liabilities (including prospective and contingent liabilities) as if the Company were being wound up under the provisions of the Companies Act, or the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, as applicable.

9 REPORT ADDRESSED TO THE BOARD OF DIRECTORS BY THE COMPANY'S STATUTORY AUDITORS

The text of the report dated April 6, 2026, of M/s. Deloitte Haskins & Sells, Chartered Accountants, the statutory auditors of the Company, addressed to the Board of the Company is reproduced below:

Quote

To,
Board of Directors,
Aurobindo Pharma Limited
Galaxy, Floor 22-24; Plot No 1, Sy No 83/1
Hyderabad Knowledge City,
Raidurg Panmaktha Hyderabad,
Telangana – 500032

Re: Statutory Auditor's Report in respect of proposed buyback of equity shares by Aurobindo Pharma Limited (the "Company") in terms of Clause (xi) of Schedule I of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("the Buyback Regulations")

- This Report is issued in accordance with the terms of our engagement letter March 25, 2026.
- The Board of Directors of the Company have approved a proposal for buyback of Equity Shares by the Company at its meeting held on April 06, 2026, in pursuance of the provisions of Sections 68, 69 and 70 of the Companies Act, 2013, as amended (the "Act") and the Buyback Regulations.
- We have been requested by the Management of the Company to provide a report on the accompanying "Statement of Permissible Capital Payment for the year ended and as at March 31, 2025" ("Annexure A") (hereinafter referred to as the "Statement"). This Statement has been prepared by the Management, which we have stamped for the purposes of identification only.

Management's Responsibility:

- The preparation of the Statement in compliance with the proviso to Section 68(2) (b) of the Act and the proviso to Regulation 5(i)(b) of the Buyback Regulations and compliance with the Buyback Regulations, is the responsibility of the Management of the Company, including the computation of the amount of the permissible capital payment, the preparation and maintenance of all accounting and other relevant supporting records and documents. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal controls relevant to the preparation and presentation of the Statement and applying an appropriate basis of preparation; and making estimates that are reasonable in the circumstances.
- As the Buyback Regulations and the Act do not define the term "insolvent", the Company has applied the guidance provided in paragraphs 25 and 26 of Ind AS 1, Presentation of Financial Statements, which relate to the assessment of the Company's ability to continue as a going concern for a period of one year from April 06, 2026. The Board of Directors are responsible to make a full inquiry into the affairs and prospects of the Company and to form an opinion as specified in (x) of Schedule I to the SEBI Buyback Regulations and that the Company will not, having regard to its state of affairs, be rendered insolvent within a period of one year from April 06, 2026 (date of passing of the Board Meeting resolution).

Auditor's Responsibility:

- Pursuant to the requirements of the Buyback Regulations, it is our responsibility to provide a reasonable assurance that:
 - we have inquired into the state of affairs of the Company in relation to the annual audited standalone and consolidated financial statements for the year ended and as at March 31, 2025 which were approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on May 26, 2025, and adopted by the shareholders of the Company in the Annual General Meeting held on September 10, 2025.
 - the amount of permissible capital payment as stated in Annexure A, has been properly determined considering the annual audited standalone and consolidated financial statements for the year ended and as at March 31, 2025 in accordance with the proviso to Section 68(2)(b) of the Act and the proviso to Regulation 5(i)(b) of the Buyback Regulations; and
 - the Board of Directors of the Company, in their meeting held on April 06, 2026 have formed the opinion as specified in Clause (x) of Schedule I to the Buyback Regulations, on reasonable grounds and that the Company will not, having regard to its state of affairs, be rendered insolvent (as defined in management responsibility above) within a period of one year from the aforesaid date with regard to the proposed buyback is approved at Board meeting.
- The annual standalone and consolidated financial statements referred to in paragraph 6 above, have been audited by us, on which we have issued an unmodified audit opinion in our reports each dated May 26, 2025. We conducted our audit of the annual standalone and consolidated financial statements in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act and other applicable authoritative pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. Our audit was not planned and performed in connection with any transactions to identify matters that may be of potential interest to third parties.
- We conducted our examination of the Statement in accordance with the Guidance Note on Audit Reports and Certificates for Special Purposes (Revised 2016), issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "Guidance Note") and Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, in so far as applicable for the purpose of this report. The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
- We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements. Further our examination did not extend to any other parts and aspects of a legal or proprietary nature in the aforesaid Buyback.

Opinion

- Based on inquiries conducted and our examination as above, we report that:
 - We have inquired into the state of affairs of the Company in relation to its annual audited standalone and consolidated financial statements for the year ended and as at March 31, 2025, which have been approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on May 26, 2025.

ii. The amount of permissible capital payment towards the proposed buy back of equity shares as computed in the Statement attached herewith, as Annexure A, in our view has been properly determined in accordance with the proviso to Section 68(2)(b) of the Act and the proviso to Regulation 5(i)(b) of the Buyback Regulations.

iii. The Board of Directors of the Company, at their meeting held on April 06, 2026 have formed their opinion as specified in clause (x) of Schedule I to the Buyback Regulations, on reasonable grounds and that the Company having regard to its state of affairs, will not be rendered insolvent (as defined in management responsibility above) within a period of one year from the date of passing of the Board Resolution dated April 06, 2026.

Restriction on use

11. This report has been issued at the request of the Company solely for use of the Company

i. in connection with the proposed buyback of equity shares of the Company as mentioned in paragraph 2 above,

ii. to enable the Board of Directors of the Company to include in the Letter of offer and other documents pertaining to buyback to be filed with

a. the Registrar of Companies, Securities and Exchange Board of India, stock exchanges, and any other regulatory authority as per applicable law; and

b. the Central Depository Services (India) Limited, National Securities Depository Limited and

c. to share with the Manager to Buyback offer in connection with the proposed buyback of equity shares of the Company for onward submission to relevant authorities in pursuance to the provisions of Section 68 and other applicable provisions of the Act and the Buyback Regulations, and may not be suitable for any other purpose.

This report should not be used for any other purpose without our prior written consent. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

For Deloitte Haskins & Sells

Chartered Accountants

(Firm's Registration No.008072S)

Sd/-

C Manish Muralidhar

(Partner)

(Membership No. 213649)

(UDIN: 26213649FRKCFB8227)

Place: Denver, USA

Date: April 06, 2026

Annexure A - Statement of Permissible Capital Payment as at March 31, 2025:

Computation of amount of permissible capital payment towards buyback of equity shares in accordance with the proviso to Section 68(2)(b) of the Companies Act, 2013 ("the Act") and read with proviso to Regulation 5(i)(b) of Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended, based on annual audited standalone and consolidated financial statements as at and for the year ended March 31, 2025.

(Amount in ₹ millions)

Particulars	Amount - Standalone	Amount - Consolidated
Paid up Equity Share Capital as on March 31, 2025 (580,801,623 fully paid-up Equity Shares of ₹ 1 each)	(A) 580.8	580.8
Free Reserves as on March 31, 2025		
Securities Premium	-	751.1
General Reserve	2,013.9	2,257.0
Retained Earnings	200,904.0	302,216.5
Total Free Reserves	(B) 202,917.9	305,224.6
Total	C=(A+B) 203,498.7	305,805.4
Maximum amount permissible towards buyback of equity shares in accordance with the proviso to Section 68(2)(b) of the Companies Act, 2013 and read with proviso to Regulation 5(i)(b) of Buyback Regulations (10% of the total Paid-up equity capital and free reserves of standalone and consolidated financial statements)	C * 10%	20,349.9
Maximum amount permissible for buyback lower of Standalone and Consolidated amounts		20,349.9

Notes:

- The amount of paid-up equity share capital and free reserves as at March 31, 2025 have been extracted from the annual audited standalone and consolidated financial statements of the Company as at and for the year ended March 31, 2025.
- As the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended and the Act do not define the term "insolvent", the Company has applied the guidance provided in paragraphs 25 and 26 of Ind AS 1, Presentation of Financial Statements, which relate to the assessment of the Company's ability to continue as a going concern for a period of one year from April 06, 2026 as well as for a period of one year immediately following the date of passing of the Board Meeting resolution.

For and on behalf of Board of Directors of Aurobindo Pharma Limited

Sd/-

K. Nithyananda Reddy

Vice Chairman and Managing Director

Date : April 06, 2026

Unquote**10 RECORD DATE AND SHAREHOLDER ENTITLEMENT**

- As required under the Buyback Regulations, the Company has fixed Friday, April 17, 2026, as the Record Date for the purpose of determining the entitlement and the names of the Eligible Shareholders, who will be eligible to participate in the Buyback.
- In due course, Eligible Shareholders will receive a letter of offer in relation to the Buyback ("Letter of Offer") along with a Tender Offer form indicating the entitlement of the Eligible Shareholder for participating in the Buyback. Even if the Eligible Shareholder does not receive the Letter of Offer along with a tender form, the Eligible Shareholder may participate and tender shares in the Buyback.

As required under the Buyback Regulations, the dispatch of the Letter of Offer shall be through electronic mode only, within 2 (Two) working days from the Record Date and, if any Eligible Shareholder requires a physical copy of the Letter of Offer, a request has to be sent to the Company or the Registrar to the Buyback and the same shall be provided.
- The Equity Shares proposed to be bought back by the Company shall be divided into two categories: (a) reserved category for small shareholders; and (b) general category for all other Eligible Shareholders.
- As defined in Regulation 2(1)(n) of the Buyback Regulations, a "Small Shareholder" is a shareholder of the Company who holds Equity Shares whose market value, on the basis of the closing price of the Equity Shares on the Stock Exchanges having the highest trading volume as on the Record Date, is not more than ₹ 2,00,000/- (Rupees Two Lakh Only).
- In accordance with Regulation 9 of the Buyback Regulations, 15% of the number of Equity Shares which the Company proposes to buy back or the number of Equity Shares entitled as per the shareholding of Small Shareholders as on the Record Date, whichever is higher, shall be reserved for the Small Shareholders as part of this Buyback.
- Based on the shareholding on the Record Date, the Company will determine the entitlement of each Eligible Shareholder, including Small Shareholders, to tender their Equity Shares in the Buyback. This entitlement for each Eligible Shareholder will be calculated based on the number of Equity Shares held by the respective Eligible Shareholder as on the Record Date and the ratio of Buyback applicable in the category to which such Eligible Shareholder belongs to. The final number of Equity Shares that the Company shall purchase from each Eligible Shareholder will be based on the total number of Equity Shares tendered by such Eligible Shareholder. Accordingly, the Company may not purchase all of the Equity Shares tendered by an Eligible Shareholder.
- In accordance with Regulation 9(ix) of the Buyback Regulations, in order to ensure that the same Eligible Shareholder with multiple demat accounts/ folios do not receive a higher entitlement under the small shareholder category, the Company shall club together the Equity Shares held by such Eligible Shareholders with a common permanent account number ("PAN") for determining the category (small shareholder or general) and entitlement under Buyback. In case of joint shareholding, the Company will club together the Equity Shares held in cases where the sequence of PANs of the joint shareholders is identical. In case of Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form, where the sequence of PANs is identical or where the PAN of all joint shareholders are not available,

Contd.

the Company will check the sequence of the names of the joint holders and club together the Equity Shares held in such cases where the sequence of the PANs and the names of joint shareholders are identical. The shareholding of institutional investors like mutual funds, pension funds/ trusts, insurance companies etc. with common PAN will not be clubbed together for determining the category and will be considered separately, where these Equity Shares are held for different schemes and have a different demat account nomenclature based on information prepared by the registrar and transfer agent as per the shareholder records received from the depositories.

- 10.8 After accepting the Equity Shares tendered on the basis of entitlement, the Equity Shares left to be bought back, if any, in one category shall first be accepted, in proportion to the Equity Shares tendered over and above their entitlement in the offer by Eligible Shareholders in that category, and thereafter from Eligible Shareholders who have tendered over and above their entitlement in the other category.
- 10.9 The participation of Eligible Shareholders in the Buyback is voluntary. Eligible Shareholders holding Equity Shares of the Company can choose to participate and get cash in lieu of shares to be accepted under the Buyback or they may choose not to participate. Eligible Shareholders holding Equity Shares of the Company may also accept a part of their entitlement. Eligible Shareholders holding Equity Shares also have the option of tendering additional shares (over and above their entitlement) and participate in the shortfall created due to non-participation of some other shareholders, if any. Further, the Equity Shares held under the category of "clearing members" or "corporate body margin account" or "corporate body - broker" as per the beneficial position data as on Record Date with common PAN are not proposed to be clubbed together for determining their entitlement and will be considered separately, where these Equity Shares are assumed to be held on behalf of clients.
- 10.10 The maximum number of Equity Shares that can be tendered under the Buyback by any Eligible Shareholder cannot exceed the number of Equity Shares held by the Eligible Shareholder as on the Record Date. In case the Eligible Shareholder holds Equity Shares through multiple demat accounts, the tender through a demat account cannot exceed the number of Equity Shares held in that demat account.
- 10.11 The Equity Shares tendered as per the entitlement by Eligible Shareholders holding Equity Shares of the Company as well as additional shares tendered, if any, will be accepted as per the procedure laid down in the Buyback Regulations. If the Buyback entitlement for any shareholder is not a round number, then the fractional entitlement shall be ignored for computation of Buyback entitlement to tender Equity Shares in the Buyback. The settlement under the Buyback will be done using the mechanism notified under the SEBI Circulars.
- 10.12 Participation in the Buyback by Eligible Shareholders may trigger capital gains taxation in India and in their country of residence. The transaction of Buyback would also be chargeable to securities transaction tax in India. In due course, Eligible Shareholders will receive a letter of offer, which will contain a more detailed note on taxation. However, in view of the particularized nature of tax consequences, Eligible Shareholders are advised to consult their own legal, financial and tax advisors for the applicable tax implications prior to participating in the Buyback.
- 10.13 Detailed instructions for participation in the Buyback (tender of Equity Shares in the Buyback) as well as the relevant timetable will be included in the Letter of Offer to be sent to the Eligible Shareholder(s).

11 PROCESS AND METHODOLOGY FOR BUYBACK

- 11.1 The Buyback is open to all Eligible Shareholders holding Equity Shares either in physical and/ or in dematerialized form as on Record Date.
- 11.2 The Buyback shall be implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" as specified by the SEBI Circulars ("Stock Exchange Mechanism") and following the procedure prescribed in the Companies Act and the Buyback Regulations and as may be determined by the Board (including the committee of the Board authorized to complete the formalities of the Buyback) on such terms and conditions as may be permitted by law from time to time.
- 11.3 For implementation of the Buyback, the Company has appointed Axis Capital Limited as the registered broker to the Company ("Company's Broker") to facilitate the process of tendering of Equity Shares through the Stock Exchange Mechanism for the Buyback and through whom the purchases and settlements on account of the Buyback would be made by the Company. The contact details of the Company's Broker are as follows:



AXIS CAPITAL LIMITED

1st Floor, Axis House, P. B. Marg, Worli, Mumbai - 400 025
Tel: +91 22 4325 5517; Fax: +91 22 4325 3000
Contact Person: Ankit Gala
Email: apl.buyback@axiscap.in
SEBI Registration Number: IN2000189931

- 11.4 BSE will be the designated stock exchange for the purpose of this Buyback. The Company will request BSE to provide the separate acquisition window ("Acquisition Window") to facilitate placing of sell orders by Eligible Shareholders who wish to tender Equity Shares in the Buyback. The details of the Acquisition Window will be specified by BSE from time to time.
- 11.5 During the tendering period, the order for selling the Equity Shares will be placed in the Acquisition Window by Eligible Shareholders through their respective stock broker(s) ("Seller Member(s)") during normal trading hours of the secondary market. The Seller Member can enter orders for Equity Shares held in dematerialized form and physical form. In the tendering process, the Company's Broker may also process the orders received from the Eligible Shareholders.
- 11.6 In the event the Seller Member(s) of any Eligible Shareholder is not registered with BSE as a trading member/ stock broker, then that Eligible Shareholder can approach any BSE registered stock broker and can register themselves by using quick unique client code ("UCC") facility through the BSE registered stock broker (after submitting all details as may be required by such BSE registered stock broker in compliance with applicable law). In case the Eligible Shareholders are unable to register using UCC facility through any other BSE registered broker, Eligible Shareholders may approach Company's Broker i.e., Axis Capital Limited, to place their bids, subject to completion of KYC requirements as required by the Company's Broker.
- 11.7 Modification/ cancellation of orders and multiple bids from a single Eligible Shareholder will only be allowed during the tendering period of the Buyback. Multiple bids made by a single Eligible Shareholder for selling Equity Shares shall be clubbed and considered as "one bid" for the purposes of acceptance. The cumulative quantity tendered shall be made available on the website of BSE (www.bseindia.com) throughout the trading session and will be updated at specific intervals during the tendering period.
- 11.8 Further, the Company will not accept Equity Shares tendered for Buyback which are under restraint order of the court/ any other competent authority for transfer/ sale and/ or title in respect of which is otherwise under dispute or where loss of share certificates has been notified to the Company and the duplicate share certificates have not been issued either due to such request being under process as per the provisions of law or otherwise.
- 11.9 Procedure to be followed by Eligible Shareholders holding Equity Shares in dematerialized form:
- 11.9.1 Eligible Shareholders who desire to tender their Equity Shares held by them in dematerialized form under the Buyback would have to do so through their respective Seller Member by indicating to the concerned Seller Member, the details of Equity Shares they intend to tender under the Buyback.
- 11.9.2 The Seller Member(s) would be required to place an order/ bid on behalf of the Eligible Shareholders who wish to tender Equity Shares in the Buyback using the Acquisition Window of BSE. For further details, Eligible Shareholders may refer to the circulars issued by BSE and Indian Clearing Corporation Limited ("Clearing Corporation").
- 11.9.3 The details of the settlement number under which the lien will be marked on the Equity Shares tendered for the Buyback will be provided in a separate circular to be issued by BSE and the Clearing Corporation.
- 11.9.4 The lien shall be marked by the Seller Member in the demat account of the Eligible Shareholder for the shares tendered in Tender Offer. Details of shares marked as lien in the demat account of the Eligible Shareholder shall be provided by the depositories to the Clearing Corporation. In case, the Eligible Shareholder's demat account is held with one depository and clearing member pool and Clearing Corporation account is held with other depository, shares shall be blocked in the Eligible Shareholder's demat account at source depository during the tendering period. Inter depository Tender Offer ("IDT") instructions shall be initiated by the Eligible Shareholder at source depository to clearing member/ Clearing Corporation account at target depository. Source depository shall block the shareholder's securities (i.e., transfers from free balance to blocked balance) and send IDT message to target depository for confirming creation of lien. Details of shares blocked in the Eligible Shareholder's demat account shall be provided by the target depository to the Clearing Corporation.
- 11.9.5 For orders placed with respect to dematerialized Equity Shares, by clearing members entities who have been allocated a custodian participant code by the Clearing Corporation ("Custodian Participant"), early pay-in is mandatory prior to confirmation of order by custodian. The custodian shall either confirm or reject the orders not later than the closing of trading hours on the last day of the tendering period. Thereafter, all unconfirmed orders shall be deemed to be rejected. For all confirmed custodian participant orders, order modification by the concerned Selling Member shall revoke the custodian confirmation and the revised order shall be sent to the custodian again for confirmation.

11.9.6 Upon placing the bid, the Seller Member(s) shall provide a Transaction Registration Slip ("TRS") generated by the exchange bidding system to the Eligible Shareholder on whose behalf the bid has been placed. The TRS will contain the details of the order submitted like bid ID number, application number, DP ID, client ID, number of Equity Shares tendered etc. In case of non-receipt of the completed tender form and other documents, but lien marked on Equity Shares and a valid bid in the Exchange Bidding System, the bid by such Eligible Shareholder shall be deemed to have been accepted.

11.9.7 It is clarified that in case of dematerialized Equity Shares, submission of the tender form and TRS is not mandatory. After the receipt of the demat Equity Shares by the Clearing Corporation and a valid bid in the exchange bidding system, the Buyback shall be deemed to have been accepted, for Eligible Shareholders holding Equity Shares in demat form.

11.9.8 The Eligible Shareholders will have to ensure that they keep the depository participant ("DP") account active and unblocked to receive credit in case of return of Equity Shares due to rejection or due to prorated Buyback decided by the Company. Further, Eligible Shareholders will have to ensure that they keep the bank account attached with the DP account active and updated to receive credit remittance due to acceptance of Buyback of shares by the Company. In the event if any equity shares are tendered to Clearing Corporation, excess dematerialized equity shares or unaccepted dematerialized equity shares, if any, tendered by the Eligible Shareholders would be returned to them by the respective Clearing Corporation. If the securities transfer instruction is rejected in the depository system, due to any issue, then such securities will be transferred to the Seller Member's depository pool account for onward transfer to the eligible shareholder. On the date of the settlement, in case of Custodian Participant orders, excess dematerialized shares or unaccepted dematerialized shares, if any, will be returned to the respective custodian depository pool account.

11.9.9 Eligible Shareholders who have tendered their demat shares in the buyback shall also provide all relevant documents, which are necessary to ensure transferability of the demat shares in respect of the tender form to be sent. Such documents may include (but not be limited to): (i) duly attested power of attorney, if any person other than the Eligible Shareholder has signed the tender form; (ii) duly attested death certificate and succession certificate/legal heirship certificate, in case any Eligible Shareholder is deceased, or court approved scheme of merger/amalgamation for a company; and (iii) in case of companies, the necessary certified corporate authorizations (including board and/or general meeting resolutions).

11.10 Procedure to be followed by Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form:

In accordance with SEBI's circular dated July 31, 2020 (circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/ P/2020/144), shareholders holding Equity Shares in physical form are allowed to tender such shares in a buyback undertaken through the Tender Offer route. However, such tendering shall be as per the provisions of the Buyback Regulations. The procedure is as below:

11.10.1 Eligible Shareholders who are holding physical Equity Shares and intend to participate in the Buyback will be required to approach their respective Seller Member along with the complete set of documents for verification procedures to be carried out before placement of the bid. Such documents will include the (a) Tender Form duly signed by all Eligible Shareholders (in case shares are in joint names, in the same order in which they hold the shares), (b) original share certificate(s), (c) valid share transfer form(s)/ Form SH-4 duly filled and signed by the transferors (i.e. by all registered Shareholders in the same order and as per the specimen signatures registered with the Company) and duly witnessed at the appropriate place authorizing the transfer in favour of the Company, (d) self-attested copy of PAN card(s) of all Eligible Shareholders, (e) any other relevant documents such as power of attorney, corporate authorization (including board resolution/ specimen signature), notarized copy of death certificate and succession certificate or probated will, if the original shareholder is deceased, etc., as applicable. In addition, if the address of the Eligible Shareholder has undergone a change from the address registered in the register of members of the Company, the Eligible Shareholder would be required to submit a self-attested copy of address proof consisting of any one of the following documents: valid Aadhar card, voter identity card or passport.

11.10.2 Based on documents mentioned in paragraph 11.10.1 above, the concerned Seller Member shall place an order/ bid on behalf of the Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form who wish to tender Equity Shares in the Buyback, using the Acquisition Window of BSE. Upon placing the bid, the Seller Member shall provide a TRS generated by the exchange bidding system to the Eligible Shareholder. TRS will contain the details of order submitted like folio number, certificate number, distinctive number, number of Equity Shares tendered etc.

11.10.3 Any Seller Member/ Eligible Shareholder who places a bid for physical Equity Shares, is required to deliver the original share certificate(s) and documents (as mentioned above) along with TRS generated by exchange bidding system upon placing of bid, either by registered post, speed post or courier or hand delivery to the Registrar to the Buyback i.e., KFin Technologies Limited at the address mentioned at paragraph 14 below) on or before the Buyback closing date. The envelope should be super scribed as "Aurobindo Pharma Limited Buyback 2026". One copy of the TRS will be retained by Registrar to the Buyback and it will provide acknowledgement of the same to the Seller Member/ Eligible Shareholders.

11.10.4 The Eligible Shareholders holding physical Equity Shares should note that physical Equity Shares will not be accepted unless the complete set of documents are submitted. Acceptance of the physical Equity Shares for Buyback by the Company shall be subject to verification as per the Buyback Regulations and any further directions issued in this regard. The Registrar to the Buyback will verify such bids based on the documents submitted on a daily basis and till such verification, BSE shall display such bids as 'unconfirmed physical bids'. Once Registrar to the Buyback confirms the bids, they will be treated as 'confirmed bids'.

11.10.5 In case any Eligible Shareholder has submitted Equity Shares in physical form for dematerialization, such Eligible Shareholders should ensure that the process of getting the Equity Shares dematerialized is completed well in time so that they can participate in the Buyback before the closure of the tendering period of the Buyback.

11.10.6 An unregistered shareholder holding Equity Shares in physical form may also tender their Equity Shares in the Buyback by submitting the duly executed transfer deed for transfer of shares, purchased prior to the Record Date, in their name, along with the offer form, copy of their PAN card and of the person from whom they have purchased shares and other relevant documents as required for transfer, if any.

11.11 The Buyback from the Eligible Shareholders who are residents outside India including foreign corporate bodies (including erstwhile overseas corporate bodies), foreign portfolio investors, non-resident Indians, members of foreign nationality, if any, shall be subject to the Foreign Exchange Management Act, 1999 and rules and regulations framed thereunder, if any, Income Tax Act, 2025 and rules and regulations framed thereunder, as applicable, and also subject to the receipt/ provision by such Eligible Shareholders of such approvals, if and to the extent necessary or required from concerned authorities including, but not limited to, approvals from the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 and rules and regulations framed thereunder, if any.

11.12 The reporting requirements for non-resident shareholders under RBI, Foreign Exchange Management Act, 1999, as amended and any other rules, regulations, guidelines, for remittance of funds, shall be made by the Eligible Shareholders and/ or the Eligible Shareholder's broker through which the Eligible Shareholder places the bid.

11.13 Modification/cancellation of orders will only be allowed during the tendering period of the Buyback.

The cumulative quantity of Equity Shares tendered shall be made available on the website of BSE (www.bseindia.com) throughout the trading session and will be updated at specific intervals during the tendering period.

12 METHOD OF SETTLEMENT

Upon finalization of the basis of acceptance as per the Buyback Regulations:

- 12.1 The settlement of trades shall be carried out in the manner similar to settlement of trades in the secondary market.
- 12.2 The Company will pay the consideration to the Company's Broker who will transfer the funds pertaining to the Buyback to the Clearing Corporation's bank accounts as per the prescribed schedule. For Equity Shares accepted under the Buyback, the Clearing Corporation will make direct funds payout to respective Eligible Shareholders. If the Eligible Shareholders' bank account details are not available or if the funds transfer instruction is rejected by RBI/ bank, due to any reason, then such funds will be transferred to the concerned Seller Member's settlement bank account for onward transfer to such Eligible Shareholders.
- 12.3 Details in respect of shareholder's entitlement for Tender Offer process will be provided to the Clearing Corporation by the Registrar on behalf of the Company. On receipt of the same, the Clearing Corporation will cancel the excess or unaccepted blocked shares in the demat account of the Eligible Shareholder. On settlement date, all blocked shares mentioned in the accepted bid will be transferred to the Clearing Corporation.
- 12.4 In case the demat account of the Eligible Shareholder is held with one depository and the Clearing Member pool/ Clearing Corporation account is held with another depository, the Clearing Corporation that holds the Clearing Member pool and Clearing Corporation account of the Eligible Shareholder will cancel the excess or unaccepted shares in the depository that holds the demat account. Source depository will not be able to release the lien without a release of IDT message from target depository. Further, release of IDT message shall be sent by target depository either based on cancellation request received from Clearing Corporation or automatically generated after matching with bid accepted details as received from the Company or the Registrar to the Buyback. Post receiving the IDT message

from target depository, source depository will cancel/release excess or unaccepted blocked shares in the demat account of the Eligible Shareholder. Post completion of tendering period and receiving the requisite details viz., demat account details and accepted bid quantity, source depository shall debit the securities as per the communication/message received from target depository to the extent of accepted bid shares from Eligible Shareholder's demat account and credit it to the Clearing Corporation settlement account in target Depository on settlement date.

- 12.5 In relation to the Equity Shares in physical form:
- a) If Equity Shares in physical form tendered by Eligible Shareholders are not accepted, the share certificate would be returned to such Eligible Shareholders by registered post or by ordinary post or courier at the Eligible Shareholders' sole risk. The Company also encourages Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form to dematerialize their such Equity Shares.
- b) If however, only a portion of the Equity Shares in physical form held by an Eligible Shareholder is accepted in the Buyback, then the Company is authorised to split the share certificate and issue a Letter of Confirmation ("LOC") in accordance with SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 dated January 25, 2022 with respect to the new consolidated share certificate for the unaccepted Equity Shares tendered in the Buyback. The LOC shall be dispatched to the address registered with the Registrar and Transfer Agent of the Company ("RTA"). The RTA shall retain the original share certificate and deface the certificate with a stamp "Letter of Confirmation Issued" on the face/ reverse of the certificate to the extent of the excess Equity Shares. The LOC shall be valid for a period of 120 days from the date of its issuance, within which the Equity Shareholder shall be required to make a request to their depository participant for dematerializing the Equity Shares in physical form. In case the Equity Shareholder fails to submit the demat request within the aforementioned period, the RTA shall credit the Equity Shares to a separate demat account of the Company opened for the said purpose.
- 12.6 In case of certain client types viz. NRI, foreign clients etc. (where there are specific RBI and other regulatory requirements pertaining to funds pay-out) who do not opt to settle through custodians, the funds pay-out would be given to their respective Selling Member's settlement accounts for releasing the same to the respective Eligible Shareholder's account. For this purpose, the client type details would be collected from the depositories, whereas funds payout pertaining to the bids settled through custodians will be transferred to the settlement bank account of the custodian, each in accordance with the applicable mechanism prescribed by BSE and the Clearing Corporation from time to time.
- 12.7 Details in respect of shareholder's entitlement for Tender Offer process will be provided to the Clearing Corporation by the Company or Registrar to the Buyback. On receipt of the same, Clearing Corporation will cancel the excess or unaccepted blocked shares in the demat account of the shareholder. On settlement date, all blocked shares mentioned in the accepted bid will be transferred to the Clearing Corporation.
- 12.8 In the case of inter depository, Clearing Corporation will cancel the excess or unaccepted shares in target depository. Source depository will not be able to release the lien without a release of IDT message from target depository. Further, release of IDT message shall be sent by target depository either based on cancellation request received from Clearing Corporation or automatically generated after matching with bid accepted details as received from the Company or the Registrar to the Buyback. Post receiving the IDT message from target depository, source depository will cancel/ release excess or unaccepted block shares in the demat account of the shareholder. Post completion of tendering period and receiving the requisite details viz., demat account details and accepted bid quantity, source depository shall debit the securities as per the communication/ message received from target depository to the extent of accepted bid shares from shareholder's demat account and credit it to Clearing Corporation settlement account in target depository on settlement date.
- 12.9 The Equity Shares bought back in dematerialized form would be transferred directly to the demat escrow account of the Company opened for the Buyback ("Company Demat Escrow Account") provided it is indicated by the Company's Broker or it will be transferred by the Company's Broker to the Company Demat Escrow Account on receipt of the Equity Shares from the clearing and settlement mechanism of BSE.
- 12.10 Eligible Shareholders who intend to participate in the Buyback should consult their respective Seller Member(s) for details of any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) etc., that may be levied by the Seller Member(s) upon the selling shareholders for tendering Equity Shares in the Buyback (secondary market transaction). The Buyback consideration received by the Eligible Shareholders in respect of accepted Equity Shares could be net of such costs, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) and the Manager to the Buyback and Company accepts no responsibility to bear or pay such additional cost, charges and expenses (including brokerage) incurred solely by the Eligible Shareholders.
- 12.11 The Seller Member(s) would issue contract note and pay the consideration for the Equity Shares accepted under the Buyback and return the balance unaccepted Equity Shares to their respective clients/ will unblock the excess unaccepted Equity Shares. The Company's Broker would also issue a contract note to the Company for the Equity Shares accepted under the Buyback.
- 12.12 The Equity Shares accepted, bought and lying to the credit of the Company Demat Escrow Account and the Equity Shares bought back and accepted in physical form will be extinguished in the manner and following the procedure prescribed in the Buyback Regulations.

13 COMPLIANCE OFFICER

13.1 The Company has designated the following as the Compliance Officer for the Buyback:

Name : Mr. B. Adi Reddy
Designation : Company Secretary and Compliance Officer
Address : Galaxy, Floors: 22-24, Plot No. 1, Survey No.83/1, Hyderabad Knowledge City, Raidurg Panmaktha, Ranga Reddy District, Hyderabad - 500 032, Telangana, India.
Tel no. : +91 40 6672 5333
Email : cs@aurbindo.com

13.2 In case of any clarifications or to address investor grievance, the shareholders may contact the Compliance Officer, from Monday to Friday between 10:00 am (IST) to 5:00 pm (IST) on all working days except public holidays, at the above-mentioned address.

14 INVESTOR SERVICE CENTER AND REGISTRAR TO THE BUYBACK

14.1 The Company has appointed the following as the Registrar to the Buyback:

KFin Technologies Limited
Address: Selenium, Tower- B, Plot No 31 & 32 Gachibowli, Financial District Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Telangana - 500032
Tel. no.: +91 40 6716 2222
Fax no.: +91 40 6716 1563;
Contact person: M Murali Krishna
Toll Free number: 18003094001
Email: aurbindo.buyback2026@kfintech.com
Website: www.kfintech.com
Investor Grievance mail: einward.ris@kfintech.com
SEBI Registration Number: INR000000221
Validity: Permanent
CIN: L72400MH2017PLC444072



14.2 In case of any query, the shareholders may also contact the Registrar to the Buyback, from Monday to Friday between 10:00 am (IST) to 5:00 pm (IST) on all working days except public holidays at the above-mentioned address.

15 MANAGER TO THE BUYBACK

The Company has appointed the following as Manager to the Buyback:

AXIS CAPITAL LIMITED
1st Floor, Axis House
P. B. Marg, Worli, Mumbai - 400 025, Maharashtra, India
Tel. : +91 22 4325 2183; Fax: +91 22 4325 3000
Contact Person: Harish Patel/ Simran Gadh
Email: apl.buyback@axiscap.in
Website: www.axiscapital.co.in
SEBI Registration Number: INM000012029



16 DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

In terms of Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board accepts full and final responsibility for all the information contained in this Public Announcement and confirms that this Public Announcement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of Aurobindo Pharma Limited

K. Nithyananda Reddy Managing Director
DIN: 01284195
M. Madan Mohan Reddy Whole-time Director
DIN: 01284266
B. Adi Reddy Company Secretary and Compliance Officer
Membership No.: ACS 13709

Date : April 7, 2026
Place : Hyderabad



कांग्रेस का नए स्वायत्त क्षेत्र का दांव चला तो मिलेगा वित्तीय अधिकार

जनसत्ता ब्यूरो

असम में सत्ता पाने की कोशिश में जुटी कांग्रेस नए स्वायत्त क्षेत्र के गठन विचार को बड़ा मुद्दा बना रही है। असम में छठी अनुसूची के तहत तीन प्रमुख स्वायत्त जिला परिषदें-बोडोलैंड, कार्बी आंगलोग और उत्तर कछार हिस्से पहले से ही हैं। अब कांग्रेस ने सत्ता में आने पर चाय बागान वाले प्रमुख क्षेत्रों के लिए एक अलग से स्वायत्त क्षेत्र के गठन का दावा कर रही है। सांसद राहुल गांधी के इस विचार को कांग्रेस घोषणापत्र में भी शामिल किया गया है। स्वायत्त क्षेत्र के गठन से इन क्षेत्रों को विकास कार्य कराने के लिए कुछ वित्तीय अधिकार मिलेंगे।

इस बार विधानसभा चुनाव में संविधान का 244 ए लागू करने का मुद्दा कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। इस पहल का सबसे अधिक असर असम में चाय बागान वाले क्षेत्रों और ऊपरी असम के जिले शामिल हैं। इस दायरे में तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, और सोनितापुर जिले आते हैं। 0कार्बी आंगलोग और बोडोलैंड क्षेत्रीय क्षेत्र में भी आदिवासी मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं। यहां के मतदाताओं के लिए यह एक बड़ा मुद्दा है। यही वजह है कि कांग्रेस ने व्यवस्था को अपने चुनावी घोषणा पत्र की गारंटियों में प्रमुखता से शामिल किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में यह

असम

इस बार विधानसभा चुनाव में संविधान का 244 ए लागू करने का मुद्दा कांग्रेस पार्टी लेकर आई है।

घोषणापत्र जारी किया था। इसमें असम के छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिए जाने की भी घोषणा शामिल। इन मतदाताओं की राज्य में अधिक संख्या है और यह कांग्रेस पार्टी का पुराना वोट बैंक भी माना जाता है। राज्य में कांग्रेस पार्टी दूसरा बड़ा दल बनकर उभरी थी और वीते चुनाव में 60 एसी सीटें थीं, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। कम अंतर वाली इन सीटों पर ही पार्टी की नजर है। विशेषज्ञ पीडी आचार्य बताते हैं कि असम में जनजाति वनवासी आदिवासियों की आवादी वाले जिले हैं। संविधान का 244 ए असम में एक स्वायत्त राज्य बनाने का प्रावधान देता है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद विकास के कार्य इस निकाय के माध्यम से ही होते हैं। इस व्यवस्था को लागू करने से पहले इसके कानून व शक्तियां तय की जाती हैं। यह एक प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था होता है, जिसके पास राज्य के अधिकार से कम शक्ति होती है, लेकिन यह अपने विकास कार्य पूर्ण करने में सक्षम होती है। इसे लागू करने के लिए संसद से कानून बनाना होगा और इसे पारित करने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती।

स्वागत



पुदुचेरी में मंगलवार को भाजपा युवा मोर्चा की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को फूलों की माला पहनाने पार्टी नेता।

बंगाल में कांग्रेस ने किया महिलाओं को मुफ्त शिक्षा का वादा



जनसत्ता ब्यूरो

कांग्रेस ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी करते हुए महिलाओं के लिए स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा और एक वर्ष के भीतर सभी रिक्त सरकारी पदों पर युवाओं की भर्ती करने समेत कई वादे किए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पार्टी का घोषणापत्र जारी किया तथा पार्टी को लोगों के सामने तृणमूल कांग्रेस एवं भाजपा के अलावा तीसरे विकल्प के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा, बंगाल में अपने 15 वर्षों के शासनकाल में तृणमूल कांग्रेस ने राज्य के विकास के लिए कुछ खास नहीं किया है। निवेश और रोजगार सृजन की जरूरत है। भाजपा भी अर्थव्यवस्था या रोजगार सृजन की बात नहीं करती, बल्कि उसकी सिर्फ धुंधलीकरण में दिलचस्पी है। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में महिलाओं के लिए प्रति माह 2000 रुपये की सहायता, सहायता तक मुफ्त शिक्षा एवं मुफ्त परिवहन सेवा का वादा किया है।

चेन्नई की एगमोर सीट पर नई पीढी के बीच मुकाबला

सुशील राघव

चेन्नई की एगमोर विधानसभा सीट इस बार सिर्फ एक चुनावी मैदान नहीं, बल्कि 'नई राजनीति की प्रयोगशाला' बन गई है। यहां सभी बड़ी पार्टियों ने अपने पुराने चेहरों को किनारे कर, पहली बार चुनाव लड़ रहे युवा उम्मीदवारों पर दांव खेला है।

ड्रिविड मुनेत्र कषमम (द्रमुक) ने जहां तेज-तर्रार वकील और टीवी चर्चाओं में पहचान बना चुके तमिलन प्रसन्ना को उतारा है, वहीं अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कषमम (अन्नाद्रमुक) ने युवा उद्यमी अभिषेक रंगासामी पर भरोसा जताया है। अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा चेट्टी कषमम (टीवीके) ने

तमिलनाडु

द्रमुक ने तमिलन प्रसन्ना को मैदान में उतारा है, जबकि एआइएद्रमुक ने अभिषेक रंगासामी को उम्मीदवार बनाया है। टीवीके ने राज मोहन को चुना है और एनटीके ने सरन्या को मैदान में उतारा है। एगमोर निर्वाचन क्षेत्र पारंपरिक रूप से द्रमुक का गढ़ माना जाता रहा है। मौजूदा विधायक परंतमन को इस बार टिकट नहीं दिया गया है, क्योंकि पार्टी ने एक नए चेहरे को चुना है।

यूट्यूबर राज मोहन को मौका दिया है, तो नाम तमिलर काची (एनटीके) ने सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) पेशेवर सरन्या को मैदान में उतारा है। इस सीट पर चतुष्कोणीय मुकाबला मुकाबला देखने को मिल रहा है। इन चारों उम्मीदवारों में कुछ खास समानता है। वे सभी युवा हैं, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और अपनी-अपनी पार्टियों में नेतृत्व की एक नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रसन्ना लंबे समय से द्रमुक से जुड़े हैं और प्रवक्ता के तौर पर टेलीविजन चर्चाओं में एक जाना-पहचाना चेहरा हैं। उनका कहना है कि चारों उम्मीदवारों में कुछ खास समानता है। वे सभी युवा हैं, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और अपनी-अपनी पार्टियों में नेतृत्व की एक नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रसन्ना लंबे समय से द्रमुक से जुड़े हैं और प्रवक्ता के तौर पर टेलीविजन चर्चाओं में एक जाना-पहचाना चेहरा हैं। उनका कहना है कि चारों उम्मीदवारों में कुछ खास समानता है। वे सभी युवा हैं, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और अपनी-अपनी पार्टियों में नेतृत्व की एक नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के बीच

महिला आरक्षण बिल पर तेज हुई सियासी जंग

राकेश शर्मा

देश के पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच एक बार फिर से महिला आरक्षण बिल चुनावी बहस के केंद्र में आ गया है। इस बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता समर्थन करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दबी जुबान में विपक्ष बिल पेश करने के समय पर सवाल उठा रहा है। इन दलों का मानना है कि सरकार ने चुनाव में फायदा लेने के लिए वह समय चुना जब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार भी चल रहा होगा। जबकि सरकार इसे बाद में भी ला सकती थी।

नेताओं की मानें तो सरकार 16 अप्रैल से शुरू हो रहे संसद के सत्र में इस बिल को पेश कर सकती है। महिला आरक्षण बिल का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसद सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करना है। बिल के पारित होने के बाद भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि देखने को मिलेगी। वर्तमान में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है, जिसे बढ़ाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। ऐसे में यह बिल पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। सत्तारूढ़ दल इसे महिला

राजनीति

सोलह अप्रैल से शुरू हो रहे संसद के सत्र में रखा जा रहा है विधेयक, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में दिख सकता है असर।

सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताकर पेश कर सकती है। इस बिल का असर खासतौर पर महिला मतदाताओं पर पड़ सकता है, जो हाल के वर्षों में चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी ने महिलाओं को ध्यान में रखकर पहले ही कई योजनाएं शुरू की हैं। ऐसे में वह इस बिल का समर्थन कर महिलाओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास करेगी। इस संबंध में केरल से कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने कहा कि कांग्रेस इस बिल का समर्थन करती है। संसद में बिल के पक्ष में अपना मत रखेगी। पार्टी ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। पार्टी ने नेता सोनिया

विपक्ष बिल के समय को लेकर सवाल उठा रहा

भाजपा के तमिलनाडु के राज्य सचिव विनोद पी सेल्वम ने कहा कि विपक्ष बिल के समय को लेकर सवाल उठा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को विकास को लेकर काम कर रहे हैं। देश में हर साल चुनाव होते ही रहते हैं। ऐसे में संसद में लाने का सभी समय उचित है। भाजपा ने महिलाओं के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया। अब इस बिल को पास करवाकर महिलाओं को उनका उचित अधिकार भी देगे। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में पहले चरण का प्रचार 21 अप्रैल को थम जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का प्रचार 27 अप्रैल को थमगा। ऐसे में संभावना है कि 16 अप्रैल से शुरू होने वाले संसद के दौरान इस बिल का असर चुनावी चर्चाओं में देखने को मिल सकता है।

गांधी ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) अजित पवार गुट के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव ने कहा कि इस बिल से सदन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। हालांकि बिल को पूरी तरह से प्रभावी व लागू होने में दस साल का समय लग जाएगा।

इससे पहले स्थायी निकाय में इस आरक्षण को लागू किया गया था, जिसे जमीन पर उतारने में दस साल लग गए थे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओल्हायन ने कहा कि महिला बिल पर भाजपा ने कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी है। वह केवल चुनावी बयान बाजी कर रही है, भाजपा लोगों के हित में कुछ नहीं करती।

तीन राज्यों में चुनाव प्रचार खत्म

कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर

जनसत्ता ब्यूरो

असम, पुदुचेरी और केरल में मंगलवार शाम को चुनाव प्रचार का समापन हो गया। तीनों ही प्रदेशों में नौ अप्रैल को मतदान होना है। यहां चुनाव मैदान में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। असम में बड़ा चेहरा वर्तमान में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा हैं, जबकि केरल में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन व पुदुचेरी में मुख्यमंत्री एन रंगासामी हैं। नौ अप्रैल को इन दिग्गजों की किस्मत इवीएम में कैद हो जाएगी।

हिमंत सरमा जालुकवाड़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस ने इस सीट पर बिदिशा नियोग को टिकट दिया है। वहीं दूसरी ओर असम कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष के अध्यक्ष गौरव गोरोई जोरहाट विधानसभा से अपना भाग्य अजमा रहे हैं। जोरहाट सीट पर चार उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां भाजपा ने हितेंद्रनाथ गोस्वामी को टिकट दिया है। असम की दिसपुर सीट से प्रद्युत बोरदोलाइ चुनाव मैदान में हैं। विधानसभा में विपक्ष के

मतदान कल

नेता देबब्रत सैकिया, विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत हैमारी और कई मंत्रिमंडल सहयोगी मैदान में हैं। केरल के मुख्यमंत्री और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख नेता पिनरई विजयन अपनी पारंपरिक सीट धर्मदम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजापुरावरु विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। इसी प्रकार वीडो सीतानन परवूर सीट से चुनाव मैदान में हैं, इसके लिए खुद राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया था। राजीव चंद्रशेखर और के सुरेंद्रन दोनों राजग गठबंधन के दो बड़े चेहरे हैं। राजीव चंद्रशेखर नेमोम से और के सुरेंद्रन मंजेश्वरम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त मार्क्सवादी पार्टी से बागवत करने वाले नेता जी सुधाकरन अंबलपुड़ा सीट से मैदान में हैं। इनका सीधा मुकाबला माकपा के एच सलाम से है। यहां कांग्रेस समर्थन वाली यूडीएफ का कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है।

इन दिग्गजों ने किया प्रचार

असम, केरल और पुदुचेरी में सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारकों ने मंगलवार को अपने पाले में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि ये दिग्गज पूरे महीने एक के बाद एक रैलियां कर मतदाताओं को रिझाने की पूरी कोशिश की। भाजपा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा समेत आला नेताओं ने प्रचार का जिम्मा संभाला तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पवन खेड़ा, गौरव गोरोई ने तीनों राज्यों में जमकर प्रचार किया। पुदुचेरी में मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने राजग के लिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने केरल व पुदुचेरी में कांग्रेस के लिए और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के लिए जमकर प्रचार किया।

ऐे भाई...



वायनाड के पंडिजराथारा में मंगलवार को एक चुनावी नुकड़ सभा को संबोधित करती सांसद प्रियंका गांधी।

'आवासीय योजना में देरी के लिए सरकार जिम्मेदार'

कां

ग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि केरल में मुंडक्कई-चूरलमाला भूखलन की घटना के पीड़ितों के लिए पार्टी की आवासीय परियोजना में राज्य की वाम सरकार से मंजूरी समय पर न मिलने की वजह से देरी हुई। प्रियंका ने यहां कलपेट्टा में यूडीएफ गठबंधन की एक नुकड़ सभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि एलडीएफ की टाउनशिप के उद्घाटन के बाद ही कांग्रेस की परियोजना को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में मेरे साथियों को भी ये ही दिक्कतें हुई होंगी। प्रियंका की यह दलील वायनाड आवासीय परियोजना के लिए धन इकट्ठा करने और पैसे के इस्तेमाल के संबंध में कांग्रेस पर अनियमितताओं के आरोपों के बीच आई है। कांग्रेस महासचिव ने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन पर भी हमला किया और सवाल किया कि भ्रष्टाचार के कई आरोपों का सामना करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई मामला क्यों नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का विरोध करने वालों के खिलाफ केंद्रीय एफआईए जांच कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया, तो, यह साफ है कि उनके बीच एक गुप्त समझौता है। प्रियंका ने यह आरोप भी लगाया कि केरल में पिछले 10 सालों के एलडीएफ राज में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है, राज्य पर बहुत ज्यादा कर्ज है। (ए)

'केरल चुनाव में एलडीएफ को मजबूत जनादेश का भरोसा'

के

रल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने नौ अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में पहले प्रचार समाप्त होने के साथ ही मंगलवार को विश्वास जताया कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेतृत्व वाले मोचे को एक दशक तक सत्ता में रहने के बावजूद जनता का समर्थन प्राप्त है। माकपा के वरिष्ठ नेता ने जनता से हाल में हुए संवाद के आधार पर यह दावा किया कि लोगों का रुझान वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के पक्ष में है। कन्पूरे में उन्होंने कहा, हमारी जनता से बातचीत से यह समझ में आया है कि केरल की सोच एलडीएफ के साथ है। विभिन्न स्तरों पर यूडीएफ को नकारा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एलडीएफ 2021 के मुकाबले अधिक सीटें जीतकर पहले से मजबूत जनादेश के साथ सत्ता में वापसी करेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राज्य में खाता भी नहीं खोल पाएगा। आलोचनाओं को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि वे व्यापक जनविरोध में नहीं बदली हैं। विजयन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस आरोप को भी खारिज किया, जिसमें उन्होंने केरल में माकपा और भाजपा के बीच समझौते की बात कही थी। उन्होंने कहा, यह बेवुनियाद आरोप है और गांधी को जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। कांग्रेस की राजनीति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं का उदाहरण दिया। (ए)

'पुदुचेरी भाजपा की जनविरोधी नीतियों का परीक्षण स्थल बनी'

त

मिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने मंगलवार को दावा किया कि भाजपा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी पर उसी तरह पूर्ण नियंत्रण चाहती है, जैसे वह एडम्पाडी के. पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली अन्नाद्रमुक के माध्यम से तमिलनाडु पर नियंत्रण हासिल करना चाहती है। द्रविड मुनेत्र कषमम (द्रमुक) के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन (एसपीएफ) के उम्मीदवारों के लिए चुनावी प्रचार करते हुए उदयनिधि ने कहा कि पुदुचेरी की जनता ने इस प्रेम की भूमि में कभी नफरत की राजनीति करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा, आज इस केंद्र शासित प्रदेश में फासीवादी भाजपा से जुड़ी ताकतों की घुसपैट काफ़ी बढ़ गई है। यह प्रदेश भाजपा की सभी जनविरोधी नीतियों का परीक्षण स्थल बन गया है। यहां भाजपा एआइएनआरसी के कंधों पर टीक उसी तरह सवार है, जैसे तमिलनाडु में पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली अन्नाद्रमुक के कंधों पर। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की जनविरोधी नीतियों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी शामिल है और इसके माध्यम से जाति आधारित शिक्षा प्रणाली लागू की गई है। उदयनिधि ने कहा, वे ऐसी योजनाएं लागू कर रहे हैं जो पुदुचेरी में आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देंगी, लेकिन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भाजपा की साजिशों को राज्य में प्रवेश करने से प्रभावी ढंग से रोक दिया है। (ए)

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी बण्डा, शाहजहाँपुर।

पत्रांक: 37/आकिंक/क्षे0पं0/नि0का0/नि0 प्रकाशन/2026-27

दिनांक: 07.04.2026

अल्पकालीन निविदा सूचना

समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि विकास खण्ड बण्डा, शाहजहाँपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में "पंचम राज्य वित्त आयोग/15वें केन्द्रीय वित्त आयोग (अनटाइड फण्ड / टाइड फण्ड)" के अन्तर्गत नीचे दिये जा रहे विवरण के अनुसार कार्य किये जाने हैं जिसके लिये सीलबन्ध निविदायें दिनांक: 07.04.2026 से दिनांक 21.04.2026 तक आमंत्रित की जाती हैं प्राप्त होने वाली निविदायें दिनांक 21.04.2026 को अपराह्न 03:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा सम्बन्धी फार्म दिनांक- 07.04.2026 से दिनांक 21.04.2026 तक प्रातः 12 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में निविदा धनराशि प्रति कार्य जमा कर कार्यालय से क्रय किया जा सकता है। निर्धारित दिनांक समय के उपरान्त प्राप्त होने वाली निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी। निविदा के सम्बन्धित नियम व शर्तें विकास खण्ड पर निविदा प्रकाशन के उपरान्त किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम स्थान सहित	कार्य की माप लम्बाई	कार्य की प्रकृतित लागत (लाख)	निविदा मूल्य	अर्नेस्ट मनी (2 प्रतिशत)	कार्य प्रारम्भ होने से कार्य पूर्ण होने की अवधि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

(पंचम राज्य वित्तआयोग से स्वीकृत कार्य)

1.	महेन्द्र सिंह के मकान से रनवीर के खेत तक खण्डजा निर्माण कार्य।	450.00 मी०	9.51	600	19020.00	3 माह
2.	आवां बुजुर्ग मे मेन रोड से पुनित मिश्रा के मकान तक खण्डजा निर्माण कार्य	185.00 मी०	3.94	600	7880.00	3 माह
3.	मुनेश वर्मा के खेत से ढका की सीमा तक खण्डजा निर्माण कार्य	450.00 मी०	9.51	600	19020.00	3 माह
4.	बिहार की सीमा से दुकुरी की सीमा तक खण्डजा निर्माण कार्य।	450.00 मी०	9.51	600	19020.00	3 माह
5.	मुडिया बनिगवां मार्ग से गुरुदीप सिंह के मकान तक खण्डजा निर्माण कार्य	450.00 मी०	9.53	600	19060.00	3 माह
6.	शेर बहादुर के खेत से बिहार की सीमा तक खण्डजा निर्माण कार्य।	450.00 मी०	9.53	600	19060.00	3 माह
7.	मनोज के मकान से तिन्दुआ की सीमा तक खण्डजा निर्माण कार्य	450.00 मी०	9.53	600	19060.00	3 माह
8.	नईम के मकान से पितम के मकान तक खण्डजा निर्माण कार्य।	450.00 मी०	9.55	600	19820.00	3 माह
9.	सडिया मे सरदुल सिंह के मकान से नहर तक खण्डजा निर्माण कार्य	250.00 मी०	5.31	600	10620.00	3 माह
10.	अल्हादादपुर मे सोहनलाल के मकान से श्यामलाल के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	88.00 मी०	4.42	600	8840.00	3 माह
11.	सडिया मे झरमल सिंह के मकान से लिंक रोड तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	180.00 मी०	8.99	600	17980.00	3 माह
12.	बलवीर सिंह के मकान से पी०डब्ल्यू०डी० रोड तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	150.00 मी०	7.50	600	15000.00	3 माह
13.	श्रीकान्त वाजपेई के मकान से बाजार तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	180.00 मी०	8.99	600	17980.00	3 माह
14.	गुरुद्वारा से मेन रोड तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	150.00 मी०	7.50	600	15000.00	3 माह
15.	धर्मापुर मे बलवीर इन्द्रसिंह के घर से गुरुद्वारा तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	170.00 मी०	8.49	600	16980.00	3 माह
16.	आवां बुजुर्ग मे सोनपाल के घर से बंसतलाल पांसी के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	70.00 मी०	3.52	600	7040.00	3 माह
17.	तिन्दुआ नगरिया मे मेन रोड से चरनजीत के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	150.00 मी०	7.50	600	15000.00	3 माह
18.	खपाल के घर से जसपाल के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	100.00 मी०	4.99	600	9980.00	3 माह
19.	बिरहना बुजुर्ग मे रामकिशोर के मकान से प्राइमरी स्कूल तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	150.00 मी०	7.50	600	15000.00	3 माह

(15वें केन्द्रीय वित्त आयोग, अनटाइड फण्ड से स्वीकृत)

1.	कुडिया महोलिया मे मैन रोड से अजायब सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	95.00 मी०	4.77	600	9540.00	3 माह
2.	दुकुरी बुजुर्ग मे रविन्द्र के घर से विनय मदीरिया की जगह तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	180.00 मी०	8.99	600	17980.00	3 माह
3.	रुआ मे तिराहे से मुजीम के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	180.00 मी०	8.99	600	17980.00	3 माह
4.	ढका मे मेन रोड से अमिल वर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	55.00 मी०	2.78	600	5560.00	3 माह
5.	प्राइमरी स्कूल से होली स्थान तक इण्टरलाकिंग का अवशेष कार्य व प्रा०वि० के उत्तर कोने से दक्षिण कोने कन्यापुर धरमाई रोड तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	180.00 मी०	7.99	600	15980.00	3 माह
6.	आवां मे मैन रोड से सुखदेव के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य	100.00 मी०	5.02	600	10040.00	3 माह
7.	बसत्तापुर मे मनोज के मकान से धमेन्द्र कुमार के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	50.00 मी०	2.53	600	5060.00	3 माह

(15वें केन्द्रीय वित्तआयोग, टाइड फण्ड से स्वीकृत)

1.	बेलावली मे रघुवीर के घर से नाला तक नाला निर्माण कार्य	240.00 मी०	6.40	600	7300	3 माह
2.	बरगदा मे मुण्शी के घर से शमशान घाट तक नाला निर्माण कार्य	374.00 मी०	9.94	600	9200	3 माह
3.	कैथ भगीतीपुर मे सुबोध कुमार के मकान के पास पेयजल व्यवस्था कार्य	1 नग	2.29	600	4580	3 माह
4.	तिन्दुआ मे साधू के मकान के पास पेयजल व्यवस्था कार्य	1 नग	2.29	600	4580	3 माह
5.	चिकटिया में बागीश के घर के पास पेय जल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
6.	बरीबरा में गुरुद्वारा में पेयजल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
7.	वैवहा में रामासरे पासी के घर पेयजल के पास पेयजल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
8.	भितिया श्याम में शिव मन्दिर के पास पेयजल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
9.	दुकुरी बुजुर्ग में चौराहे से रवि के मकान तक नाला निर्माण कार्य।	200 मी०	10.00	1000	20000	3 माह
10.	ग्राम पं० मशिंगई जमुनिया नवदिया में कलक्टर दीक्षित के मकान के पास पेयजल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
11.	चरकी देवरी में पंचायत भवन के पास पेयजल व्यवस्था	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
12.	पटना में गुडडु बी०डी०सी० के घर के पास पेयजल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
13.	नवादा ढाह में शेर सिंह के मकान के पास पेयजल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
14.	बरीबरा में जितेन्द्र के मकान के पास पेयजल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
15.	दुकुरी बुजुर्ग में देवराज के मकान के पास पेयजल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
16.	आवा बुजुर्ग में आलोक शुक्ला के मकान के पास पेय जल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
17.	भगवत्तापुर में प्रमोद मिश्रा के मन्दिर के पास पेय जल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
18.	उदयपुर में हरीश वर्मा के मकान के पास पेय जल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
19.	मशिंगई में नवीन प्रधान के घर के पास पेय जल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
20.	कुवा में बलजीत बी०डी०सी० के मकान के पास पेयजल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
21.	ग्राम धर्मापुर में टीकराम व लोकराम के मकान के पास सिसोरा रोड नाला तक नाला निर्माण कार्य।	225 मी०	10.00	10000	20000	3 माह
22.	नवाबपुर में अखिलेश कुमार के स्कूल के पास पेयजल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
23.	लालपुर में कृष्णा महाविद्यालय के पास पेयजल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
24.	हंसापुर में विपिन के मकान के पास पेयजल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
25.	बालेमऊ में अम्बेडकर पार्क के पास पेयजल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
26.	ढकाधनधामपुर में रामू बी०डी०सी० के मकान के पास पेयजल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
27.	आवां बुजुर्ग में प्राथमिक विद्यालय के पास पेयजल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
28.	सार्वजनिक स्थलों के पास पेयजल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह

नियम व शर्तें-

- प्रत्येक निविदा के साथ 2 प्रतिशत धरोहरा राशि की बैंक ड्राफ्ट/एन०एस०सी०/ एफ०डी०आर० खण्ड विकास अधिकारी बण्डा, शाहजहाँपुर के पक्ष में बन्धक करवा कर निविदा के साथ सलंगन किया जाना एवं निविदा खोले जाने के पूर्व मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
- जमानत की धनराशि निविदा की 10 प्रतिशत होगी जो निविदा स्वीकृत के उपरान्त सम्बन्धित ठेकेदार को अवशेष 8 प्रतिशत जमानत धनराशि का बैंकड्राफ्ट/ एन०एस०सी०/एफ०डी०आर० खण्ड विकास अधिकारी बण्डा, शाहजहाँपुर के पक्ष में अनिवार्य रूप से बन्धक करवा कर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। जिससे कार्य पूर्ण होने के 06 माह बाद वापस कर दिया जायेगा।
- पंजीकृत ठेकेदारों की ही निविदा मान्य होगी।
- किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी व मा० अय्यक्ष क्षेत्र पंचायत बण्डा, शाहजहाँपुर को होगा।
- सशर्त निविदा/ओवर राईटिंग करिया निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- एकल निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- ठेकेदार को आयकर जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन, हैसियत प्रमाणपत्र, जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त चित्र प्रमाणपत्र, श्रम विभाग का प्रमाणपत्र, कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र इसके अतिरिक्त कार्य प्रारम्भ से पूर्व व पूर्ति के पश्चात स्थलचित्र दिया जाना होगा।
- कार्य गुणवत्ता के साथ 3 माह में पूर्ण कराया जाना होगा तथा गुणवत्ता के सत्यापन के उपरान्त कार्य संतोषजनक पाये जाने पर तथा धन की उपलब्धता के आधार पर ही ठेकेदार को भुगतान किया जायेगा।
- निविदा के साथ रु० 100/- के स्टाम्प पेपर अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।
- निविदादाता को प्रतिकार्य के साथ रु० 100/- का स्टाम्प पेपर निष्पादित करना होगा।
- समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेश/शर्तें ठेकेदारों को मान्य होंगे।
- ब्लेक लिस्टेड तथा अन्य कारणों से बहिष्कृत ठेकेदारों की निविदा मान्य नहीं होगी।
- निविदा खुलने की तिथि पर अक्काश होने पर निविदा अगले कार्य दिवस पर खोली जायेगी।
- प्रत्येक कार्य में प्रयुक्त होन वाली सामग्री की राजकीय प्रमाणित प्रयोगशाला प्रमाण पत्र कार्यालय मे उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- कार्य आदेश धन की उपलब्धता होने पर दिया जायेगा।

खण्ड विकास अधिकारी
बण्डा, शाहजहाँपुर।



बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

शाखा,
नई सब्जी मंडी आज़ादपुर,
नई दिल्ली-110033



अचल संपत्तियों की बिक्री की सूचना
परिशिष्ट IV-ए में | नियम 8(6) और 9(1) के पर्युक्त देखें।
2002 के नियम 8(6) के पर्युक्त के साथ पठिए।

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं सुस्थापित अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना, सुस्थापित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के पर्युक्त के साथ पठिए।

एतद्वारा आम जनता को, और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं), बंधककर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका कब्जा सुरक्षित लेनदार - बैंक ऑफ़ बड़ौदा के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे नीचे उल्लिखित खाते/खातों में बकाया राशि की वसूली के लिए 'जैसा है जहाँ है', 'जैसा है वसा है', और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जाएगा। उधारकर्ता/ओं बंधककर्ता/ओं गारंटर/ओं / सुरक्षित संपत्ति/ बकाया राशि/ अरक्षित मूल्य/ ई-नीलामी की तिथि और समय, ईंपनडी और बोली बुद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है-

क्र. सं.	उधारकर्ता(ओं) / गारंटर (ओं)/ बंधककर्ता(ओं) का नाम और पता	अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण है, जिसमें यदि कोई बात न हो, तो उनका भी उल्लेख करें (जैसे बैंक ऑफ़ बड़ौदा के पास निरखी)।	कुल देय राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	1 अरक्षित मूल्य 2 बयाना राशि जमा (ईंपनडी) 3 बोली बुद्धि राशि	कच्चे की स्थिति (रचनात्मक/ नौतिक)	संपत्ति निरीक्षण की तिथि और समय
1	1. उधारकर्ता- मेसर्स श्रीजी एंटरप्राइजेज रजि. कार्यालय- 714, 7वीं मंजिल, अग्रवाल साइबर, प्लाजा-1, नेताजी सुभाष प्लेस, दिल्ली-110034। बंधककर्ता - श्रीमति मीनाक्षी गर्ग निवासी मकान नं. 38, दूसरी मंजिल, पॉकेट-14, सेक्टर-24, रोहिणी, दिल्ली-110085	क्रोहलड संग्रही का न्यायसंगत बंधक संपत्ति की पूरी दूसरी मंजिल (खत के अधिकारों के बिना) जिसका भवन संख्या 38, पॉकेट-14, सेक्टर-24 है और जिसका क्षेत्रफल 60.00 वर्ग मीटर है। यह संपत्ति रोहिणी आवासीय योजना, रोहिणी, दिल्ली-110085 के अंतर्गत प्लान में स्थित है। जो संपत्ति श्रीमती मीनाक्षी गर्ग, पत्नी श्री अमित गर्ग की है।	रुपये 89,99,987.73 (केवल नवासी लाय, निन्यानवे हजार नौ सौ सत्तासी रुपये और तिहतर पैसे) दिनांक 11.06.2025 तक +इस पर आगे का ब्याज, लागत, शुल्क और व्यय।	21.05.2026 दोपहर 12:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	अरक्षित मूल्य रु. 54,12,000/- रु. 34,36,749/- ईंपनडी रु. 5,41,200/- बोली बुद्धि राशि रु. 10,000/-	नौतिक कच्चा	16.05.2026 दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट लिंक <https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm> और <https://baanknet.com> देखें। इच्छुक बोलीदाता अधिकृत अधिकारी/शाखा प्रबंधक से मोबाइल नंबर 8130999110 पर संपर्क कर सकते हैं।
दिनांक: 06.04.2026, स्थान: दिल्ली, अधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ़ बड़ौदा



THE BIGGEST CAPITAL ONE CAN POSSESS KNOWLEDGE



ASIAN FERTILIZERS LIMITED
CIN: L99999UP1986PLC007621
Regd. office: Flat No. 202, Preet Garden, 3A/172, Azad Nagar, Kanpur, 208002
Corporate office: P.W.D. officer's colony, Near Sahara Press, Park road, Gorakhpur-273001
E-mail: af@asianfertilizers.com
Phone: (0551) 2203421, 2202436, Website: www.asianfertilizers.com

NOTICE

The amendment to Regulation 40 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 vide Gazette notification dated June 8, 2018 has mandated that transfer of securities would be carried out in dematerialized form only w.e.f. 01/04/2019.

Pursuant to the above amendment, Asian Fertilizers Limited (ISIN: INE010Y01018) is requesting to all its shareholders to get their shares converted into dematerialized form. It is requested to kindly approach Company at af@asianfertilizers.com and your concerned Depository Participant with application letter along with original Share certificates, self-attested copy of Pan Card, self-attested Latest address proof, self-attested copy of Bank Passbook/ cancelled cheque leaf and bank verified signatures, as earliest possible.

SEBI vide circular no. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73 dated April 20, 2018 has mandated the submission of copy of Permanent Account Number (PAN) by every participant in securities market. Therefore, members are requested to submit copy of their PAN and bank account details (original cancelled cheque leaf/ attested bank passbook showing name of account holder) to Company / RTA.

In the support of Green Initiative in Corporate Governance, members are requested to register their e-mail address(es) and changes therein from time to time, by directly sending the relevant e-mail address along with details of name, address, Folio No., shares held: i) To the registrar and share transfer agent, M/s Skyline Financial Services Pvt. Ltd or Company for shares held in physical form /Demat; Upon registration of the email address (es), the Company proposes to send Notices, Annual Report and such other documents to those Members via electronic mode/e-mail.

For Asian Fertilizers Limited
Sd/- Ashok Kumar Matanheila
Managing Director
DIN:01763776

Date:08-04-26



CLASSIFIED AD DEPOT (CAD)
Book classified ads at your nearest Express Group's authorised Classified Ad Depots

EAST

PATPARGANJ : CHAVI ADVERTISERS, Ph.: 9899701024, 22090987, 22235837, PREET VIHAR : AD BRIDGE COMMUNICATION, Ph.: 9810029747, 42421234, 22017210, SHAKARPUR : PARICHAY ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9350309890, 22519890, 22549890

WEST

JANAKPURI : TRIMURTI ADVERTISERS, Ph.: 9810234206, 25530307, KAROL BAGH (REGHARPURA) : K R ADVERTISERS, Ph.: 9810316618, 9310316618, 41547697, KARAMPURA : GMJ ADVERTISING & MARKETING PVT. LTD., Ph.: 9310333777, 9211333777, 9810883377, NEW MOTI NAGAR : MITTAL ADVERTISING, Ph.: 25178183, 9810538183, 9555945923, MOTI NAGAR : UMA ADVERTISERS, Ph.: 9312272149, 8800276797, RAMESH NAGAR : POSITIVE ADS, Ph.: 9891195327, 9310067777, 65418908, TILAK NAGAR : SHIVA ADVERTISERS, Ph.: 9891461543, 25980670, 20518836, VIKAS PURI : AAKAR ADVT. MEDIA Ph.: 9810401352, 9015907873, 9268796133

CENTRAL

CHANDNI CHOWK : RAMNIWAS ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9810145272, 23912577, 23928577, CONNAUGHT PLACE : HARI OM ADVERTISING COMPANY Ph.: 9811555181, 43751196

NORTH

TIS HAZARI COURT : SAI ADVERTISING, Ph.: 9811117748, KINGWAY CAMP : SHAGUN ADVERTISING, Ph.: 9818505505, 27458589, PATEL CHEST (OPP. MORRIS NAGAR POLICE STATION) : MAHAN ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9350304609, 7042590693, PITAMPURA (PRASHANT VIHAR) : PAAVAN ADVERTISER Ph.: 9311564460, 9311288839, 47057929

SOUTH

CHATTARPUR : A & M MEDIA ADVERTISING, Ph.: 9811602901, 65181100, 26301008, KALKAJI : ADWIN ADVERTISING, Ph.: 9811111825, 41605556, 26462690, MALVIYA NAGAR : POOJA ADVERTISING & MARKETING SERVICE, Ph.: 9891081700, 24331091, 46568866, YUSUF SARAI : TANEJA ADVERTISEMENT & MARKETING Ph.: 9810843218, 26561814, 26510090

NCR

FARIDABAD (NEELAM FLYOVER) : AID TIME (INDIA) ADVERTISING, Ph.: 9811195834, 0129-2412798, 2434654, FARIDABAD (NIT, KALYAN SINGH CHOWK) : PULSE ADVERTISING, Ph.: 9818078183, 9811502088, 0129-4166498, FARIDABAD : SURAJ ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9810680954, 9953526681, GURGAON : SAMBODHI MEDIA PVT. LTD., Ph.: 0124-4065447, 9711277174, 9910633399, GURGAON : AD MEDIA ADVERTISING & PR, Ph.: 9873804580, NOIDA (SEC. 29) : RDX ADVERTISING, Ph.: 9899268321, 0120-4315917, NOIDA (SEC. 65) : SRI SAI MEDIA, Ph.: 0120-4216117, NOIDA (SEC. 58) : JAI LAKSHMI ADVERTISERS, Ph.: 9873807457, 9911911719, GHAZIABAD (HAPUR ROAD TIRAHA, NR GURUDWARA) : TIRUPATI BALAJI ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9818373200, 8130640000, 0120-4561000

EDUCATION (IAS & PMT ACADEMIES)

FRIENDS PUBLICITY SERVICE 23287653, 23276901, 9212008155
For CAD enquiries please contact :
ROHIT JOSHI 9818505947, ABHINAV GUPTA 9910035901
For booking classified ads, please contact 011-23702

पूर्वांतर रेलवे

ई-टेंडरिंग निविदा सूचना

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (समाधि), पूर्वांतर रेलवे, इण्डियन रेलवे द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से निविदा सूचना सं. **M_249_2_1_CW_Pneumatic** के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य के लिए माध्यम से 'सिग्नल पेंटिंग सिस्टम' के आधार पर खुली ऑनलाइन निविदा सूचना है। इस निविदा सूचना में 'सिग्नल पेंटिंग सिस्टम' के आधार पर खुली ऑनलाइन निविदा सूचना है। इस निविदा सूचना में 'सिग्नल पेंटिंग सिस्टम' के आधार पर खुली ऑनलाइन निविदा सूचना है। इस निविदा सूचना में 'सिग्नल पेंटिंग सिस्टम' के आधार पर खुली ऑनलाइन निविदा सूचना है।

नमसदा में 09.04.2026 को छप्पे ई-ऑनलाइन सेल नोटिस के अनुसार, ऑनलाइन की तारीख 11.04.2026 थी। इस नोटिस में, उपर लेने वाले का नाम वेद पाल पुत्र पीएम सिंह, है। इस ई-ऑनलाइन सेल नोटिस में हिंदी प्रतिक्रिया में बतवाई गई ऑनलाइन पेंटिंग सिस्टम और ईमेल चक्रवर्ती से मेल प्रिंट हो गई है। सही ऑनलाइन पेंटिंग सिस्टम वेबसाइट <https://xpertauction.com> है और सही ईमेल ID eauctions@xpertauction.com है और ऑनलाइन की तारीख भी 11.04.2026 है। अपेक्षित अखबार के प्रतिक्रिया में भी यही बात सही लिखी गई थी। सेल नोटिस के बाकी सभी नियम और शर्तें वेबसाइट पर देखें।

किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें: **+91 981 8997 856**

स्थान: गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक: 07.04.2026 सेव फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

मंयाई (समाधि) इस्पतनगर

मुजाबि/यांत्रिक-04

ट्रेनों में भीड़ी/सिगरेट न पिघें

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

खबर कोना

बिली जीन किंग कप के पहले मैच में हारा भारत, दूसरे में सहजा पिछड़ीं

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (भाषा)।

भारत की वैश्वी अडकर ने कई सहज गलतियों की जिससे बिली जीन किंग्स कप एशिया ओशिनिया ग्रुप एक के मुकाबले में मंगलवार को उन्हें ओचिसा चांता ने हराया और मेजबान टीम थाईलैंड से 0-1 से पिछड़ गई। अपनी प्रतिद्वंद्वी से 73 रैंक ऊपर वैश्वी को एक घंटे 13 मिनट तक चले मुकाबले में 1-6, 3-6 से पराजय का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण मैच तीन घंटे विलंब से शुरू हुआ था। दूसरे एकल मुकाबले में सहजा यमलापल्ली का सामना पातचारिन चीपचांदेज से था और बारिश के कारण जब खेल रोक़ा गया तब भारतीय खिलाड़ी 4-6, 6-1, 3-4 से पिछड़ रही थी। यह मुकाबला अब बुधवार सुबह 11 बजे से आगे खेला जाएगा जबकि दोपहर तीन बजे मेजबान टीम अपने दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी।



सैन फ्रांसिस्को : बैसबाल मैच के तीसरी पारी के दौरान आउट होने के बाद डगआउट में वापस जाते फिलाडेल्फिया फिली के ट्रे टर्नर।

अभय पांच गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में हारे

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (भाषा)।

भारत के शीर्ष खिलाड़ी अभय सिंह मिस्र के एल गौना में चल रही पीएसए लैटिनम प्रतियोगिता एल गौना ओपन स्ववाश के पुरुष वर्ग के दूसरे दौर में पांच गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में स्थानीय खिलाड़ी युसुफ इब्राहिम से हार गए। विश्व में 25वें नंबर के खिलाड़ी अभय ने सोमवार को खेले गए मैच में अच्छी शुरुआत की थी। उन्होंने विश्व में सातवें नंबर के खिलाड़ी इब्राहिम के खिलाफ पहला और तीसरा गेम जीता, लेकिन वह अपनी लय बरकरार नहीं रख पाए। मिस्र के छठे वरीयता प्राप्त खिलाड़ी इब्राहिम ने आखिर में यह कड़ा मुकाबला 7-11 11-9 9-11 11-5 11-8 से जीता।

डेविड वार्नर शराब पीकर गाड़ी चलाने पर गिरफ्तार

सिडनी, 7 अप्रैल (भाषा)।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को मंगलवार को शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। संवेन न्यूज ने बताया कि मारुबा में शवास की औचक जांच के बाद उनके शरीर में शराब की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई। वार्नर अगले महीने अदालत के समक्ष पेश होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट लीग में कराची किंग्स के साथ करार करने वाले वार्नर को स्थानीय थाने ले जाया गया जहां फिर उनके शरीर में शराब की मात्रा तय सीमा से दुगुनी पाई गई। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। कानूनी कार्रवाई का असर वार्नर के पीएसएल में खेलने पर नहीं पड़ेगा। उनकी टीम का अगला मैच नौ अप्रैल को है और वह सात दिन के ब्रेक में निजी दौरे पर यहां आए हैं।



इंग्लैंड : मैच से पहले अपने साथियों के साथ अभ्यास करते लिवरपूल के इब्राहिमा कोनेट (बीच में)।

तैयारी

एशिया चैंपियनशिप : ध्रुव और तनीषा की जोड़ी मिश्रित युगल में जीते

निंगबो, 7 अप्रैल (भाषा)।

भारत के ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो की जोड़ी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 के मिश्रित युगल वर्ग के दूसरे दौर में पहुंच गई जबकि बाकी जोड़ियां हारकर बाहर हो गई। कपिला और क्रास्टो ने थाईलैंड के फुनावत होरबालूकीत और बेनयापा ऐमखार्द को 21-14, 11-21, 21-15 से हराया। इससे पहले रोहन कपूर और रुक्मिका शिवानी गाडे की जोड़ी मलेशिया की आठवीं वरीयता प्राप्त गोह सुन हुआत और लेइ शेवोन जैमी की जोड़ी से 34 मिनट तक चले मुकाबले में 13-21, 19-21 से हारकर बाहर हो गई।

एक अन्य मैच में असित सूर्या और अमृता प्रथमेश की जोड़ी मलेशिया के वोंग लियेन सि और लिम चियू सियेन से 31 मिनट में 16-21, 15-21 से हार गई।



एकल वर्ग के मुकाबले बुधवार से शुरू होंगे। पुरुष एकल में आल इंग्लैंड चैंपियनशिप उपविजेता लक्ष्य सेन का सामना हांगकांग के ली चियुक यू से होगा। वहीं महिला एकल में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पी वी सिंधू मलेशिया की वोंग लिंग चिंग से खेलेंगी।

मीनाक्षी, जैसमीन, विश्वनाथ और सचिन फाइनल में पहुंचे

उलानबटोर, 7 अप्रैल (भाषा)।

मौजूदा विश्व चैंपियन जैसमीन लंबोरिया और मीनाक्षी हुड्डा एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई जिससे स्वर्ण पदक के लिए खेलने वाले भारतीय मुक्केबाजों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है। विश्वनाथ सुरेश (50 किलो) और सचिन सिवाच (60 किलो) ने भी फाइनल में जगह बनाई। वहीं आकाश (75 किलो), लोकेश (85 किलो), नरेंद्र बेरवाल (90 प्लस किलो) और हर्ष चौधरी (90 किलो) को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारत के आठ मुक्केबाज फाइनल खेलेंगे। महिलाओं के 48 किलोवर्ग सेमीफाइनल में

मुक्केबाजी

आकाश, लोकेश, नरेंद्र बेरवाल और हर्ष चौधरी को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।

मीनाक्षी ने थाईलैंड की थिपसाशा योदवारी को 4-1 से हराया। जैसमीन ने 57 किलोवर्ग के सेमीफाइनल में उजबेकिस्तान की निजिना उक्तामोवा को 3-2 से हराया। पुरुष वर्ग में विश्वनाथ ने जॉर्डन के हुताइफा एशिया को 5-0 से हराया। सचिन ने थाईलैंड के साकदा रूआमथाम को 4-1 से मात दी।

पलक व मुकेश ने विश्व रिकार्ड के साथ स्वर्ण जीता

कियानसुन याओ और कार्ड हू की चीन की जोड़ी ने रजत पदक अपने नाम किया

ग्रेंनाडा, 7 अप्रैल (भाषा)।

भारतीय निशानेबाज पलक और मुकेश नेलावल्लो ने मंगलवार को राइफल और पिस्टल के आइएसएसएफ विश्व कप में 10 मीटर एअर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में विश्व रिकार्ड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पलक और मुकेश की भारतीय जोड़ी ने कुल 487.7 अंक बनाकर शीर्ष स्थान हासिल किया जो कि जूनियर विश्व रिकार्ड भी है। इस जोड़ी ने क्वालीफिकेशन दौर में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 581 अंक के साथ पदक दौर में जगह बनाई। कियानसुन याओ और कार्ड हू की चीन की जोड़ी ने 484.8 अंक के साथ रजत पदक जीता जबकि वेरोनिका मेजर और अंकोस कैरोली नागी की हंगरी की जोड़ी ने फाइनल में कुल 414.9 अंक के साथ कांस्य पदक हासिल किया।

पलक ने फाइनल में 243.0 जबकि मुकेश ने

निशानेबाजी



पलक ने फाइनल में 243.0 जबकि मुकेश ने 244.7 अंक बनाए। क्वालीफिकेशन दौर में पलक और मुकेश ने दूसरा स्थान हासिल किया। पलक और मुकेश की भारतीय जोड़ी ने कुल 487.7 अंक बनाकर शीर्ष स्थान हासिल किया जो कि जूनियर विश्व रिकार्ड भी है।



244.7 अंक बनाए। क्वालीफिकेशन दौर में पलक और मुकेश ने दूसरा स्थान हासिल किया। उनसे आगे चीन की जोड़ी थी जिसने 586 अंक जुटाए। पलक (18 साल) पहली बार 2023 एशियाई खेलों में 10 मीटर एअर पिस्टल के व्यक्तिगत मुकाबले में स्वर्ण और टीम वर्ग में

रजत पदक जीतकर सुर्खियों में आई थी। उन्होंने 242.1 अंक का एशियाई खेलों का रिकार्ड बनाकर 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भी कोटा पक्का कर लिया था। मुकेश भी भारतीय पिस्टल निशानेबाजी के एक उभरते हुए सितारे हैं और जूनियर विश्व चैंपियन हैं।

त्रिकूद खिलाड़ी अब्दुल्ला ने बर्मिंघम में रजत पदक जीता था

साक्षात्कार

अगली प्रतियोगिता मई में होने वाला फेडरेशन कप है

अबुबाकर की निगाहें राष्ट्रमंडल खेलों में दूसरी बार पदक जीतने पर

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (भाषा)।

भारत के शीर्ष त्रिकूद खिलाड़ी अब्दुल्ला अबुबाकर के लिए पिछला सत्र उतार-चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वह अपनी गलतियों को सुधारेंगे और इस साल के आखिर में ग्लारसो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार दूसरा पदक जीतेंगे। केरल के 30 साल के इस खिलाड़ी ने बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में 17.02 मीटर के प्रयास से रजत पदक जीता था। अबुबाकर ने 2026 सत्र की शुरुआत 16.82 मीटर और 16.83 मीटर के दो प्रयास साथ की है जिससे उन्हें ग्लारसो (23 जुलाई से दो अगस्त) में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आत्मविश्वास मिला है। अबुबाकर ने मंगलवार को दिए साक्षात्कार में कहा, 'मैं दूरी पर ध्यान नहीं दे रहा



हूँ। मैं बस अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा कर पाता हूँ तो मेरी दूरी और प्रदर्शन अपने आप बेहतर हो जाएगा और मैं कम से कम पौडियम पर तो जगह बना ही लूंगा। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में मेरा यही लक्ष्य है। मैंने

केरल के अबुबाकर ने कहा, 'मैं अपना लक्ष्य जरूर हासिल करूंगा। अगर मैं वहां (ग्लारसो में) 17 मीटर का प्रयास कर पाता हूँ तो पदक जीत सकता हूँ। उम्मीद है कि मुझे कोई चोट नहीं लगेगी। मैं बहुत बेहतर या कोई बहुत बड़ा प्रयास कर सकता हूँ।' अबुबाकर की अगली प्रतियोगिता मई में रॉची में होने वाला फेडरेशन कप है जो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आखिरी चयन प्रतियोगिता होगी। उन्होंने कहा, 'अगर मैं पदक कप में अच्छा प्रदर्शन करता हूँ तो राष्ट्रमंडल खेलों और उसके बाद एशियाई खेलों में भी मेरा प्रदर्शन अच्छा रहेगा। मुझे दो बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा— एक बार राष्ट्रमंडल खेलों में और दूसरी बार एशियाई खेलों में। मैं पूरी तरह से फिट हूँ और मेरा ध्यान दोनों पर है। मैं दोनों प्रतियोगिताओं में अपना पूरा जोर लगा दूंगा।'

2022 राष्ट्रमंडल खेलों में 17.02 मीटर का प्रयास किया था। उससे पहले मेरे प्रदर्शन के बारे में कोई नहीं जानता था। वहां तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत कड़ी मेहनत की थी। मैंने अपनी गलतियों को सुधारा। मैंने वह सब कुछ किया जो जरूरी था।'

भारोत्तोलक साईराज डोप परीक्षण में विफल, कोच पर लगाया आरोप

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (भाषा)।

राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप (जूनियर) के स्वर्ण पदक विजेता भारोत्तोलक साईराज परदेशी को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडो) ने डोप परीक्षण में विफल होने के कारण अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। उन्होंने कुछ महीने पहले एक कोच पर करियर को बर्बाद करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। साईराज का परीक्षण 'मेटानोलोन' के लिए पाजिटिव आया है। यह एक प्रतिबंधित एनाबोलिक स्टेरॉयड है जो मांसपेशियों को बनाने में मदद करता है।

महाराष्ट्र के 18 साल के साईराज ने पिछले साल राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में पुरुषों के 88 किग्रा जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने इस नतीजे के पीछे साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने अक्टूबर में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ (आइडब्ल्यूएलएफ) और भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) को लिखकर दवा

गिलांबन

साईराज ने दावा किया था कि राष्ट्रीय शिविर में मौजूद एक कोच उनसे निजी दुरुस्ती करता है।



किया था कि राष्ट्रीय शिविर में मौजूद एक कोच उनसे निजी दुरुस्ती करता है। साईराज ने 24 अक्टूबर 2025 को भेजे एक ईमेल में लिखा, 'कोच ने मेरे दोस्तों और कुछ प्रतिद्वंद्वियों को उकसाया कि वे मेरे खाने या पानी की बोतल में ड्रग्स मिला दें।' भारोत्तोलक ने हालांकि कोच की पहचान जाहिर नहीं की है। उसने आगे दावा किया कि कोच ने पहले भी उसे घमकी दी थी कि वह उसका करिअर बर्बाद कर देगा।

जायसवाल का तफानी अर्धशतक, रायल्स ने मुंबई इंडियंस को हराया

बारिश के कारण मुकाबला 11-11 ओवर का कर दिया गया

गुवाहाटी, 7 अप्रैल (भाषा)।

सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के धमाकेदार अर्धशतक से राजस्थान रायल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के वर्षा से प्रभावित 11 ओवर के मैच में मंगलवार को मुंबई इंडियंस को 27 रन से हराया। बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर राजस्थान रायल्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ तीन विकेट पर 150 रन बनाए। इसके बदले में मुंबई इंडियंस 11 ओवर में नौ विकेट पर 123 रन ही बना सकी। रायल्स की तरफ से नांदी बर्गर, संदीप शर्मा और रवि बिश्नोई ने दो-दो विकेट लिए। यह मुंबई इंडियंस की लगातार दूसरी हार है, जबकि राजस्थान रायल्स लगातार तीन मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है।

जायसवाल ने 32 गेंद में चार छक्कों और 10 चौकों से नाबाद 77 रन की पारी खेलने के अलावा वैभव सूर्यवंशी (39 रन, 14 गेंद) के साथ पांच ओवर में 80 रन जोड़कर रायल्स को तूफानी शुरुआत दिलाई। मुंबई की ओर से स्पिनर अल्लाह गजनफर सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 21 रन देकर दो विकेट चटकए। इससे पहले बारिश के कारण मुकाबला दो घंटे और 40 मिनट के विलंब से शुरू हुआ जिसके कारण इसे 11 ओवर का कर दिया गया। जायसवाल ने दीपक चाहर के पहले ही ओवर में चार चौकों और एक छक्के से 22 रन जोड़े जायसवाल ने तीसरे ओवर में ट्रेट बोल्ट पर तीन छक्कों से 22 रन जुटाकर टीम के रनों का अर्धशतक पूरा

आइपीएल 2026



जायसवाल ने दीपक चाहर के पहले ही ओवर में चार चौकों और एक छक्के से 22 रन जोड़े जबकि सूर्यवंशी ने अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह पर दो छक्के मारे। जायसवाल ने तीसरे ओवर में ट्रेट बोल्ट पर तीन छक्कों से 22 रन जुटाकर टीम के रनों का अर्धशतक पूरा किया।

गिल दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलने के लिए फिट

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (भाषा)।

गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल मांसपेशियों में जकड़न से उबर गए हैं और मैच में वापस आने में सफल हुए हैं। पिछले मैच से बाहर रहे गिल के सलामी जोड़ीदार साई सुदर्शन ने इस बात की पुष्टि की कि वह खेलने के लिए पूरी तरह फिट हैं।



मैच से एक दिन पहले सुदर्शन ने कहा,

'वह बिल्कुल ठीक हैं और खेलेंगे।' टाइटंस की टीम अपने शीर्ष बल्लेबाजी क्रम पर अधिक निर्भर मानी जाती रही है। पिछले मैच में सुदर्शन से मिली अच्छी शुरुआत के बावजूद मध्य क्रम के खराब प्रदर्शन के कारण टीम को हार झेलनी पड़ी। वाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने कहा कि टीम को वाशिंगटन सुंदर और ग्लेन फिलिप्स की मौजूदगी वाले अपने मध्य क्रम पर पूरा भरोसा है।

किया। जासवाल ने पांड्या पर चौके के साथ 23 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने पारी के अंतिम ओवर में शारदुल पर तीन चौकों के साथ टीम का स्कोर 150 रन तक पहुंचाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरे मुंबई की शुरुआत खराब रही और टीम ने तीसरे ओवर में 22 रन

तक ही तीन विकेट गंवा दिए। नमन और रदरफोर्ड ने पारी को संभाला लेकिन सिर्फ हार के अंतर को कम कर पाए। रदरफोर्ड ने देशपांडे पर दो छक्के मारे लेकिन फिर स्लिप में संदीप को कैच दे बैठे। नमन ने भी बर्गर की गेंद पर बिश्नोई को कैच थमा दिया।

ललित को रजत और सुनील को कांस्य पदक, नितेश फाइनल में

बिश्केक, 7 अप्रैल (भाषा)।

ललित ने 2026 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक जीता जब उन्होंने 55 किग्रा ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया जबकि नितेश मंगलगी को 97 किग्रा वर्ग के फाइनल में पहुंच गए। पूर्व चैंपियन सुनील कुमार ने अपने पदकों की सूची में एक और कांस्य पदक जोड़ा जिससे भारतीय टीम के लिए यह दिन काफी सफल रहा। अंडर-23 एशियाई चैंपियनशिप के पूर्व कांस्य पदक विजेता ललित को फाइनल में उज्बेकिस्तान के इल्खियार बातिरोव के खिलाफ 0-9 से शिकस्त झेलनी पड़ी।

सुनील ने 87 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक के मुकाबले में पहले राउंड में चार अंक गंवाने के बाद शानदार वापसी की और उज्बेकिस्तान के

कुश्ती



मुखम्मदकोदिर रासुलोव को 5-4 से हराकर एशियाई चैंपियनशिप में अपना लगातार दूसरा कांस्य पदक जीता। इससे पहले नितेश ने 97 किग्रा ग्रीको रोमन वर्ग के फाइनल में जगह बनाकर यह सुनिश्चित कर लिया कि वे 2025 चैंपियनशिप के अपने प्रदर्शन में सुधार करेंगे।

गिरी के खिलाफ हारे

प्रज्ञानानंद, शीर्ष स्थान की दौड़ से लगभग बाहर

पाफोस, 7 अप्रैल (भाषा)।

भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद मंगलवार को आठवें दौर में नीदरलैंड के अनोष गिरी के खिलाफ शिकस्त के साथ कैडिडेट्स टूर्नामेंट में शीर्ष पर रहने की दौड़ से लगभग बाहर हो गए। उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव ने रूस के आंद्रे एसिंपेको के खिलाफ ड्रा खेलकर शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत की। पहले दौर में गिरी के खिलाफ अपनी एकमात्र जीत दर्ज करने वाले प्रज्ञानानंद को प्रतियोगिता में अपनी दूसरी हार झेलनी पड़ी। सिंदारोव के संभावित आठ में से 6.5 अंक हैं। गिरी और अमेरिका के फाबियानो करुआना 4.5 अंक के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। प्रज्ञानानंद, वेई यी, मथियास ब्लुबाम और अमेरिका के हिकारू नाकामुरा 3.5 अंक के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं।